डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2024-2026
लाइसेंस क्र. Tech/23-04/08/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 06.02.2024 से 11.02.2024 | वर्ष 41 | अंक 06 | मूल्य ₹ 10.00

संक्षिप्त खबर

प्रदेश में 730 पीएमश्री स्कूल होंगे विकसित

भोपाल, प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिये 730 स्कूलों को पीएमश्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें 313 विकासखंडों में 626 और नगरीय निकायों में 104 सरकारी स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। यह स्कूल राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में चयनित 416 विद्यालयों की योजना के लिये 219 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है। चयनित इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। स्कूल में लैब, लाइब्रेरी, व्यावसायिक शिक्षा, आई.सी.टी. लैब और अटल टिंकरिंग लैब भी बनाई जा रही है। प्रदेश के 2350 सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब स्थापित की जा चुकी हैं।

निपुण भारत की प्रगति के अध्ययन के लिये होगा सर्वे

भोपाल, निपुण भारत अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के जरिये कक्षा-2 एवं 3 में बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि को सर्वेक्षण से जाना जाता है। प्रदेश में सत्र 2025-26 तक कक्षा-3 तक के बच्चों के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। सत्र 2022-23 में नवम्बर 2022 में सर्वे कर किया गया था। परिणाम के आधार पर कार्यक्रम के आगामी लक्ष्यों की रणनीति तैयार की गई। राज्य शिक्षा मिशन शिक्षण सत्र 2023-24 में कक्षा-2 एवं 3 में अध्ययनरत बच्चों पर राज्य स्तरीय सर्वे 19 से 23 फरवरी तक करने जा रहा है।

विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल 23 जिलों में होंगे विकास कार्य

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिये किये जा रहे प्रयासों एवं नवाचारों के संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं संकल्पों की जानकारी दी। गणतंत्र दिवस पर जनसंदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। प्रदेश के 23 जिलों की 4 हजार 597 बसाहटों में निवासरत बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित होंगे।

भीतर के पृष्ठों पर

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने किया 499 किलोमीटर लम्बाई की 15 सड़क योजनाओं का शिलान्यास

मध्यप्रदेश का सड़क नेटवर्क बढ़ाएगा निवेश और निर्यात विकास को मिलेगी गति, खुलेंगे रोज़गार के नए अवसर

- राजमार्ग परियोजनाओं से प्रदेश बनेगा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब
- भोज ताल पर रोप-वे और केबल कार के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी
- 10 हजार करोड़ के सड़क निर्माण कार्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण
- प्रदेश के अनेक स्थानों की दूरियां कम होंगी
- उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोप-वे

भोपाल, मध्यप्रदेश में सड़क परियोजनाओं से प्रदेश को इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में सड़क नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए नए कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक अनेक कार्य पूर्ण होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने यह बात भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के अवसर पर कही। इस दौरान श्री गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में सड़कों के निर्माण से निवेश आएगा, निर्यात भी बढ़ेगा और युवाओं को रोज़गार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस दौरान श्री गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8038 करोड़ लागत की 499 किलोमीटर लंबाई की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

महानगरों का सफर होगा आसान

श्री गडकरी ने कहा कि मुम्बई-दिल्ली कॉरिडोर पूरा होने से मध्यप्रदेश से दोनों महानगरों तक आना-जाना 5-6 घंटे में हो जाएगा। ग्रीन फील्ड हाई-वे के अंतर्गत ग्वालियर, आगरा और ग्वालियर-दिल्ली की यात्रा कम समय में पूरी की जा सकेगी। भोपाल से कानपुर की यात्रा भी नए कॉरिडोर के निर्माण से सात-आठ घंटे में ही पूरी हो जाएगी जो वर्तमान में पंद्रह घंटे में होती है। सागर से कानपुर की दूरी में 21 किलोमीटर की कमी आएगी।

विकास की संभावनाओं को साकार करती हैं सड़कें

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़कों का निर्माण विकास की अनेक संभावनाओं को साकार करता है। मालवा का आटा अनेक देशों में पसंद किया जाता है। इसके निर्यात में नई सड़क संरचनाएं उपयोगी होंगी। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप-वे के संचालन के प्रकल्प के लिए आगामी महीने में 171 करोड़ रुपये की निविदा कार्यवाही की तैयारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए

सड़कों का निर्माण और विस्तार महत्वपूर्ण उपलब्धि

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दस हजार करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यों की शुरुआत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जबलपुर में 9 और भोपाल में 15 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। इन 24 सड़क परियोजनाओं की लागत 10 हजार करोड़ से अधिक है। मध्यप्रदेश सड़क निर्माण के नए कार्यों के साथ ही आवागमन के हवाई साधनों और केबल कार, रोप-वे जैसे साधनों के प्रयोग में भी आगे बढ़ रहा है। राजमार्गों के निर्माण से प्रदेश के सभी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। औद्योगिक गतिविधियां भी तेज होंगी। गत 70 वर्ष में 5 हजार किलोमीटर के मार्ग तैयार हुए थे, लेकिन गत दस वर्ष में इतने ही अर्थात 5 हजार किलोमीटर के नए मार्ग बने हैं।

आयोजनों में सहभागिता के लिए स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। संशोधन अनुसार प्रदेश के स्टार्ट-अप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। घरेलू आयोजनों में सहभागिता पर प्रति आयोजन किए गए व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये तक की प्रतिपूर्ति एवं देश से बाहर के आयोजनों में सहभागिता करने पर प्रति आयोजन व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। एक स्टार्ट-अप को 1 वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 बार तथा पूरे जीवनकाल में अधिकतम 2 बार सहायता दी जाएगी। साथ ही बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए 164 करोड़ 49 लाख रुपये की स्वीकृति मिली। यह राशि नए आईसीयू बेड्स, कैथ लैब, प्रायवेट वार्ड निर्माण एवं फर्नीचर क्रय आदि कार्यों में व्यय होगी।

जनजातीय युवाओं के लिये स्वरोज़गार की तीन नई योजनाएं

भोपाल, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा तीन नई वित्तीय सहायता योजनाएं संचालित हो रही हैं। इनमें से भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोज़गार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से जनजातीय युवाओं के समग्र कल्याण के प्रयास किये जा रहे हैं। 'भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोज़गार योजना' द्वारा जनवरी 2024 तक 5,523 आवेदन में से बैंकों द्वारा 716 आवेदन के 561 पात्र हितग्राहियों को 22 करोड़ 10 लाख 64 हजार 895 रुपये वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है।

राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह

अग्निवीर योजना के लिए युवाओं को 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और सेना में नई ऊर्जा लाने के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना में प्रदेश के युवाओं को चयनित कराने के लिए प्रति बैच 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रशिक्षण में युवाओं को गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसे विषयों की कोचिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को अग्निवीर योजना में चयन में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर सहित शासन की विभिन्न योजनाओं से मिले रोज़गार और स्वरोज़गार से युवाओं के जीवन में नव सुख जीवन का सूरज उदय होगा।

नदी जोड़कर बहेगी विकास की धारा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र करते हुए बताया कि नदी से नदी को जोड़कर गांव-गांव तक विकास की धारा बहाने के लिए योजना शुरू की गई थी। मध्यप्रदेश और राजस्थान को भी इसका लाभ मिलना था लेकिन पिछली सरकारों ने इसे लागू नहीं किया।

27 जनवरी

तीसरी तिमाही में 231 करोड़ रुपये रहा यस बैंक का शुद्ध लाभ

● यस बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसम्बर

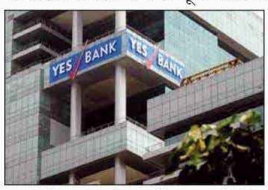

2023 में 231 करोड़ रुपये रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 52 करोड़ रुपये रहा था। जबकि बैंक का शुद्ध लाभ जुलाई-सितम्बर 2023 तिमाही में 225 करोड़ रुपये रहा था। बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसकी कुल शुद्ध आय 5.8 प्रतिशत बढ़कर 3,211 करोड़ रुपये हो गई। यह एक साल पहले समान अवधि में 3,036 करोड़ रुपये थी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में पहले ही 3,800 करोड़ रुपये की संपत्ति वसूल कर ली है। बैंक को चालू वित्त वर्ष में अपने 5,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करने का भरोसा है।

● कोटेश्वर (कोरी क्रीक), कच्छ, गुजरात में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछुआरों को समुद्री शैवाल की खेती अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कोरी क्रीक का पायलट प्रोजेक्ट समुद्री शैवाल की खेती के लिए गेम चेंजर हो सकता है। उन्होंने समुद्री शैवाल की खेती को सफल बनाने के लिये सभी हितधारकों से अपने सुझाव और इनपुट के साथ आगे आने का आह्वान किया। समुद्री शैवाल को विश्वस्तर पर पोषक तत्वों के एक महत्वपूर्ण स्रोत रूप में देखा जाता है। भारत में समुद्री शैवाल का आर्थिक महत्व खेती, भोजन, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, जलीय कृषि और जैव ईंधन उत्पादन में है। यह रोज़गार उत्पन्न करता है, ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करता है और निर्यात के अवसर प्रदान करता है।

28 जनवरी

डिब्रूगढ़ में बनेगा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल

● असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल एवं केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई। इस संस्थान को लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से करीब 15 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। यह योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं अनुसंधान में बेंचमार्क मानक स्थापित करेगा। यह अत्याधुनिक संस्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा में वैश्विक प्रचार और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। यह साक्ष्य-आधारित अनुसंधान के माध्यम से मौलिक पहलुओं, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों और प्रथाओं की वैज्ञानिक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

● पंजाब में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल-एसएसएफ की स्थापना की गई है। इस बल के वाहन राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की 5,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। प्रत्येक वाहन करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नशे में गाड़ी चलाने और तेज गति से गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए बल के वाहनों में विशेष उपकरण लगाए गए हैं। राज्य में कोई भी 112 नंबर डायल करके इस बल से सहायता मांग सकता है। एस.एस.एफ. का वाहन कॉल आने के 10 मिनट के अंदर सम्बन्धित स्थल पर पहुंच जाएगा।

29 जनवरी

प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिए तनाव से बचने के टिप्स

● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण के दौरान

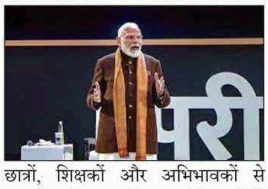

छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों से शांत मानसिकता के साथ परीक्षा देने और किसी भी बाहरी विध्वंस से बचने के लिए कहा। उन्होंने प्रश्न पत्र पढ़ने और अंतिम समय में घबराहट से बचने के लिए समय आवंटित करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने छात्रों को याद दिलाया कि अधिकांश परीक्षाएं अभी भी लिखित होती हैं और कम्प्यूटर एवं फोन के कारण लिखने की आदत कम हो रही है। उन्होंने बच्चों से लिखने की आदत बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि जब आप कुछ लिखते हैं तभी आप उसे सही मायने में समझते हैं।

● एयर इंडिया जुलाई में अपने 40 पुराने बोइंग 787 और 777 विमानों को उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। वहीं जून तक अपने बेड़े में पांच और ए350 विमान शामिल करेगी। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने यह जानकारी दी। इसके अलावा एयर इंडिया 17 ए320 और 46 बी737 विमानों को भी अपने बेड़े में शामिल करेगी। एयर इंडिया के फिलहाल 117 विमान परिचालन में हैं। जबकि सहयोगी एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिलाकर कुल 180 विमान परिचालन में हैं। एयर इंडिया ने पिछले साल विमान बनाने वाली कंपनियों एयरबस और बोइंग को 470 विमानों का ठेका दिया था।

30 जनवरी

राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव का ऐलान

● चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। इन राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। इन 56 सीटों में से सबसे ज्यादा 10 उत्तरप्रदेश की हैं। इसके

अलावा महाराष्ट्र और बिहार की 6-6 सीटों पर चुनाव होना है। जबकि मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटें, कर्नाटक और गुजरात की 4-4 राज्यसभा सीटें, तेलंगाना-राजस्थान और ओडिशा की 3-3 सीटों पर भी 27 फरवरी को मतदान होगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल की 1-1 सीट पर मतदान होना है।

● सरकार ने 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)' को और पांच साल के लिए 'विधि विरुद्ध संगठन' घोषित किया है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। राजपत्र अधिसूचना क्रमांक S.O. 564(E) द्वारा सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था। सिमी, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

31 जनवरी

संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार

● संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार

हासिल किया है। मंत्रालय की इस बार की झांकी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई गई थी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का संदेश 'भारत : लोकतंत्र की जननी' था। मंत्रालय ने कहा कि उसे यह उपलब्धि हासिल करने पर गर्व है। यह जीत सिर्फ रचनात्मकता की पहचान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रमाण है। झांकी की सफलता हमारी समर्पित टीम के सामूहिक प्रयास, भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभिनव और आकर्षक रूप में पेश करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

● केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। भारतीय वन्यजीव संस्थान हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। इस कार्यक्रम को सभी हिम तेंदुआ रेंज वाले राज्यों और दो संरक्षण भागीदारों- नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, मैसूर और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के सहयोग से किया गया था। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों सहित ट्रांस-हिमालयी इलाके में लगभग 1,20,000 किलोमीटर क्षेत्र को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। यह कार्यक्रम 2019 से 2023 तक दो चरणों में चलाया गया था।

1 फरवरी

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अस्पतालों में खुलेंगी अमृत फार्मेसी

● कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एसईसीएल) अपने अस्पतालों में अमृत फार्मेसी खोलेगी। एसईसीएल ने अपने अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर की स्थापना के लिए सार्वजनिक उपक्रम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के साथ समझौता किया है। शुरुआत में एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर के अस्पतालों तथा गेवरा, सोहागपुर और चिरिमिरी के परिचालन क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय अस्पतालों में अमृत फार्मेसियां स्थापित की जाएंगी। अस्पतालों में अमृत फार्मेसी जेनेरिक और जीवनरक्षक ब्रांडेड दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। ये फार्मेसियां सामान्य बीमारियों के साथ-साथ गंभीर स्थितियों के लिए दवाएं, प्रत्यारोपण, सर्जिकल वस्तुएं आदि रियायती दरों पर प्रदान करेंगी। इससे एसईसीएल कर्मचारियों के साथ-साथ इन अस्पतालों में आने वाले आम लोगों को भी लाभ होगा।

● उत्तरप्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से व्यासजी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने इस मामले में आदेश जारी किया। न्यायालय ने कहा कि एक सप्ताह में इस निर्णय का पालन हो। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश के बाद पूजा पाठ बंद हो गया था।

2 फरवरी

आईआईएमसी को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा

● शिक्षा मंत्रालय ने पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आईआईएमसी, नई दिल्ली तथा जम्मू (जम्मू-कश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), आइजोल (मिजोरम), कोट्टायम (केरल) और ढेंकनाल (ओडिशा) स्थित इसके पांचों क्षेत्रीय परिसरों पर भी लागू होगा। इस नए दर्जे के साथ आईआईएमसी अब डॉक्टरेट की डिग्री सहित विभिन्न डिग्री प्रदान कर सकता है।

● जनवरी 2024 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,72,129 करोड़ रुपये हुआ। जबकि जनवरी 2023 में 155,922 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था। यह राजस्व में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह अब तक दूसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह है। यह इस वित्तीय वर्ष में 1.70 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक का संग्रह वाला तीसरा महीना है। सरकार ने आईजीएसटी संग्रह से सीजीएसटी में 43,552 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 37,257 करोड़ रुपये का निपटान किया है। अप्रैल 2023 - जनवरी 2023 की अवधि के दौरान संचयी सकल जीएसटी संग्रह में 11.6 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में संग्रह हुए 14.96 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 16.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

स्काई डाइविंग फेस्टिवल 8 फरवरी से

भोपाल, मध्यप्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक बार फिर रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा।

प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में दताना एयरस्ट्रिप पर 8 से 17 फरवरी तक और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक एडवेंचर लवर्स आसमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है।

प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में 20 फरवरी से 26 फरवरी तक 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होगा। महोत्सव के स्वर्ण जयंती अवसर को खास बनाने के लिए दुनिया का सबसे रोमांचक खेल स्काई डाइविंग फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है।

MAHARANA PRATAP COLLEGE OF MANAGEMENT, BHOPAL
(Affiliated to Barkatullah University Bhopal),
Email : mpcmbhopal@gmail.com
MPCM is one of the best and fastest transforming institutes of central India. Applications are invited from eligible candidates for different teaching positions under college code 28 and non teaching positions.

Professor - 03, Associate Professor - 06,
Assistant Professor - 04, Computer Operator - 01, Peon - 01

Qualification, experience and salary as per norms. The number of vacancies is subject to change and institute reserves full rights for it. Interested candidates may apply along with CV, testimonials and four recent passport size photographs within 15 days mentioning the post applied for on the top of envelope, to Chairman, Maharana Pratap College of Management, **City Office A-6 Vidhya Nagar, Opposite Barkatullah University Bhopal - 462026 or mail us on mpcmbhopal@gmail.com. For further enquiry contact 7049813180**

R-49422/2024 **Chairman**

वर्ष 41, अंक 06 05.02.2024 से 11.02.2024
रोज़गार और निर्माण
www rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - संदीप यादव
- सम्पादक - रंजना चितले
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अशेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

लोकसभा में विकसित भारत संकल्प के साथ सर्वहितैषी और सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत

लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला है। यह भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की यात्रा में पिछले 10 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त उपलब्धियों पर रोशनी डालता है। बजट में दो महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, अनुसंधान और नवाचार। जिसके लिये वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये के फंड देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बजट विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा।

अंतरिम बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। यह बजट सर्वहितैषी और सर्वस्पर्शी है। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। देश में जारी विकास और जनकल्याण के कार्यों से 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आयी है, जो बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुआ है। आने वाले समय में हम श्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। अमृतकाल में वर्ष 2047 तक भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र होगा।

बजट में देश के दो करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराने की जो कल्पना की गई है, वह अद्भुत है। कोई भी घर पक्की छत के बिना न रहे। मध्यम वर्ग के लिए लाई गई नयी आवास योजना भी उपलब्धिपरक है। बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान योजना का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। गरीब परिवारों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की लंबे समय से दरकार थी। डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करने की दिशा में किए जा रहे कार्य और डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे सुधार कार्यों से भारत बहुत आगे बढ़ेगा। नौ से चौदह वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की सुविधा के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं। आगामी समय में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट के अंतर्गत बनाई गई नई योजना से इन घरों में 300 यूनिट बिजली बचत का मार्ग प्रशस्त होगा। यह ऊर्जा की बचत के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा और हम सबको इसका लाभ मिलेगा।

बजट भारत की प्रगति-उन्नति और आर्थिक दृष्टि से उम्मीदों भरा है। राज्य सरकार लेखानुदान में बजट का लाभ लेगी और हम मध्यप्रदेश को देश में नंबर वन बनाने की ओर अग्रसर होंगे। मध्यप्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र में ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण देने के निर्णय से पर्यटन का सर्वांगीण विकास होगा। उड़ान योजना में 517 नए रूट पर एयरपोर्ट का निर्माण और विस्तार हवाई यातायात की प्रगति की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे मध्यप्रदेश में भी हवाई यातायात का विस्तार होगा।

अमेरिकी एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों को मिलीं 19 स्पाइरल आकाशगंगाओं की तस्वीरें

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने प्रयोगों के लिये विश्व में विशिष्ट पहचान रखती है। इसी क्रम में नासा के वैज्ञानिक हाल ही में एक नये प्रयोग के लिए दुनियाभर में चर्चा का केन्द्र बन गए हैं। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा कुछ समय पहले अंतरिक्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्थापित की गई थी। इस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से तस्वीरें भेजना आरंभ कर दिया है। पिछले दिनों टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के पास उपस्थित सर्पिल आकाशगंगाओं की तस्वीर खींची और नासा को भेजीं। इस टेलीस्कोप ने कुल 19 स्पाइरल आकाशगंगाओं के फोटो खींचे हैं। इन तस्वीरों को देखकर मालूम चलता है कि आकाशगंगाएं अंदर से बाहर की ओर बढ़ती हैं। इसका मतलब है कि तारे का निर्माण आकाशगंगा के केंद्र में शुरू होता है और यह बाहर की ओर फैलता जाता है। अमेरिका के बाल्टीमोर में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक जेनिस ली के अनुसार जेम्स वेब की नई तस्वीरें अद्भुत हैं। यह उन शोधकर्ताओं के लिए भी जांच का विषय हैं जिन्होंने दशकों तक ऐसी आकाशगंगाओं पर शोध किया है। जेम्स वेब पर लगे मिड-इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट ने इन तस्वीरों को तैयार किया। इंस्ट्रूमेंट ने ऐसे तारों को भी कैप्चर किया है जो अभी विकसित अवस्था में हैं। जानकारी के अनुसार कैमरे में कैद हुई सबसे नजदीकी आकाशगंगा भी पृथ्वी से लगभग 15 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे दूर कैप्चर हुई आकाशगंगा पृथ्वी से 60 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है।

उल्लेखनीय है कि नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में वर्ष 2021 में लॉन्च किया था। यह जुलाई 2022 में स्थापित होने के बाद अपना कार्य आरंभ करने में सफल हो सका।

- विकास तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं)

विकास के पक्के इरादों का अंतरिम बजट

यकीनन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट आम आदमी की खुशहाली और देश के तेजी से विकास के दावों, वादों, इरादों और वित्तीय अनुशासन का आदर्श गुलदस्ता है। इस बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए जो अहम घोषणाएं की गई हैं, उनसे विकास और आर्थिक कल्याण का नया अध्याय लिखा जा सकेगा। साथ ही यह अंतरिम बजट विकास का ऐसा रोडमैप भी है, जिससे आगामी वर्षों में देश पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनने की राह पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकेगा। गौरतलब है कि अंतरिम बजट के तहत मध्यप्रदेश को चालू वित्त वर्ष में 6500 करोड़ रुपये केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में अधिक मिलेंगे। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय करों में 15,000 करोड़ रुपये बढ़कर मिलने का अनुमान है। इससे हमारे लेखानुदान का आकार भी बढ़ेगा। अंतरिम बजट में 'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार के तहत राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। उससे मध्यप्रदेश को भी बड़ा लाभ होगा। उसमें अभी हमें 7850 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। जिसमें एक किस्त मिल भी चुकी है।

यदि हम वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2023-24 के आय-व्यय से संशोधित अनुमान की स्थिति देखें तो पाते हैं कि उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपये है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये है। 30.03 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है। इसी तरह वर्ष 2024-25 के बजट के तहत उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपये और 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

नि:संदेह देश की आजादी के बाद से अब तक जितने अंतरिम बजट आए हैं, उन सभी बजटों में वित्तीय अनुशासन के मद्देनजर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का यह बजट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि मोटे तौर पर अंतरिम बजट लेखानुदान की तरह ही है। अंतरिम बजट में नई सरकार बनने तक की व्यय जरूरतों को पूरा करने का उद्देश्य ही प्रमुख है। यह बात महत्वपूर्ण है कि नए अंतरिम बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री की मुट्ठी वित्तीय संसाधनों की अधिक शक्ति से भरपूर थी। श्रीमती सीतारमण के पास रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे प्रत्यक्ष कर और आयकर के संग्रहण, जीएसटी में भारी वृद्धि और बढ़ती विकास दर की भरपूर ताकत रही। अंतरिम बजट के पूर्व वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7 फीसदी विकास दर के साथ आगे बढ़ते हुए तीन साल में अमेरिका व चीन के बाद आर्थिक आकार में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत 6.5 फीसदी विकास दर के साथ तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2014 से 2022 के पिछले आठ वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में वृद्धि हुई है। 2023-24 के 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न रिकॉर्ड 8.18 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। इस आर्थिक और वित्तीय ताकत को मुट्ठी में लेकर वित्त मंत्री ने विकास के वादों, इरादे और लक्ष्यों के संकल्प को दिखाते हुए लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई माह में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के नए प्रभावी अध्यायों को रेखांकित किया है।

नि:संदेह अंतरिम बजट 2024-25 की तस्वीर में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचा विकास के सशक्तिकरण और प्रगति के अध्याय को आगे बढ़ाया है। कहा गया है कि कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। आगामी वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इससे हरेक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। बुनियादी ढांचा के विकास और रोज़गार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा। लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है। ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्कता गलियारा, अधिक यातायात वाला गलियारा। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के लिए कम्प्रस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस समय जब दुनिया में भारत पर्यटकों के नए आकर्षक देश के रूप में आगे बढ़ रहा है तब अंतरिम बजट पर्यटन को बड़े प्रोत्साहन देते हुए दिखाई दे रहा है। देश के पर्यटन केन्द्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। 'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार के तहत राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए योजना आरंभ की जाएगी। डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। नए मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों में वर्तमान अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को उपयोग में लाया जाएगा। मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करने और मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में सिफारिश के लिए समिति का गठन किया जाएगा। सरकार माताओं और बच्चों की स्वास्थ की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल स्थापित करेगी। डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूती देने के लिए नया यू-विन प्लेटफॉर्म शुरू होगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख एवं विकास के लिए 'सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। सरकार किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी अथवा चाल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में सहायता के लिए योजना का शुभारंभ करेगी। वित्त मंत्री द्वारा अंतरिम बजट में लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है।

वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट स्वागत योग्य है। चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार वित्तीय अनुशासन की दृढ़ता दिखा रहे हैं। ऐसे में केंद्र को अपने घाटे को चालू वर्ष में जीडीपी के 5.9 फीसदी के लक्ष्य से भी कम 5.8 फीसदी पर सीमित रखना एक बड़ी उपलब्धि है साथ ही वर्ष 2024-25 का लक्ष्य 5.1 फीसदी और 2025-26 में 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य भी सराहनीय है। ऐसे में हम उम्मीद करें कि यह अंतरिम बजट आने वाले महीनों में मजबूत आर्थिक सुधार और तेज विकास का आधार बनेगा। साथ ही 2024 आम चुनाव के बाद पेश किया जाने वाला वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट विकास की नई बुनियाद बन सकेगा।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी

(लेखक, कॅरियर मार्गदर्शन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.)

फा.नं. 34 /स्था./परीक्षा/5600/2024 दिनांक : 27.01.2024

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में भृत्य के 21 तथा आदेश तामीलकर्ता के 10 पद कुल 31 पदों हेतु वेतनमान 15500-49000/- में इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि :- 04 मार्च 2024 (सोमवार)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि :- 07 मार्च 2024 (गुरूवार)
अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/साक्षात्कार दिनांक :- बाद में अधिसूचित किया जावेगा।

खण्ड "अ"

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।
2. आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक से **दिनांक 04 मार्च 2024 (सोमवार) को रात 11:59 बजे तक** ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
3. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी **दिनांक 07 मार्च 2024 (गुरुवार) रात 11:59 बजे तक** संबंधित त्रुटि को MPONLINE द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क रुपये 50/- +18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे। परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क :-

सभी वर्ग के आवेदकों के लिये एम.पी. ऑनलाइन को देय पोर्टल शुल्क रुपये 100/- एक सौ रुपये +18 प्रतिशत जी.एस.टी. देय होगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र वेबसाइट **www.mponline.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये **www.mponline.gov.in** पर **Authorized Kiosk Link** देखें। आवेदन इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

आवेदक **www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से **नागरिक सेवायें** होम पेज ऑप्शन में क्लिक करें। फिर ड्रापडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् MP State Legal Services Authority के Logo पर Click करें, तत्पश्चात् Application and Services ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिये दी हुई link पर click करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले Advertisement को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही Online Apply करने के लिये Form को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के Link (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्केन कर .jpg फारमेट में ही सेव/सुरक्षित करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है, वह सही हैं। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई हैं, तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरान्त Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नम्बर प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to Payment बटन दबायेगा, तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

1. **क्रेडिट/डेबिट कार्ड।**
2. **इंटरनेट बैंकिग।**
3. **क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं ही इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेंट गेट-वे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
4. **इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक आर्नलाइन फार्म भरने के उपरान्त proceed to payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लॉग-इन करेगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट अवश्य लें।
5. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:** आवेदक ऑनलाइन - आवेदन फॉर्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालन **www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेस में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें, ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां सही-सही भरे होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रकिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।
6. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क मे माध्यम से Pay For Unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
7. इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay For Unpaid Application में उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रकिया पूर्ण होने पर, कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
8. ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिन्हें ऑनलाइन नहीं भरा गया हो अथवा ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया हो। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा न करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट: यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबर पर तत्काल सम्पर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर **"संपर्क करें"** में क्लिक करें तथा **"शिकायत"** विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कस्टमर केयर (8:30 AM - 07:30 PM) :- 0755-6720200
एम.पी. ऑनलाइन कार्यालय दूरभाष क्रमांक :- 0755-6720222
3rd फ्लोर, स्टेट आईटी पार्क, अब्बास नगर,
नियर आरजीपीवी गांधी नगर, भोपाल 462033

(1) पदनाम, वेतनमान और अर्हतायें :-

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
भृत्य/आदेश तामीलकर्ता	सातवें वेतनमान के अनुसार 15500-49000	आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण।

टीप :- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

पदवर्ग (i) भृत्य के 21 पदों का आरक्षण विवरण :-

कमांक	रोस्टर	सामान्य	भू.पू. सैनिक (होरीजेन्टल कम्पार्टमेट वाइज)	विकलांग (दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित)	महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत	कुल पद
1.	अनारक्षित	3	1	0	2	6
2.	अनु. जाति	1	1	0	1	3
3.	अनु. जनजाति	2	1	0	1	4
4.	अन्य पिछडा वर्ग	3	1	0	2	6
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0	0	0	2
	योग	**11**	**4**	**0**	**6**	**21**

(ii) आदेश तामीलकर्ता के 10 पदों का आरक्षण विवरण :-

कमांक	रोस्टर	सामान्य	भू.पू. सैनिक (होरीजेन्टल कम्पार्टमेट वाइज)	विकलांग (दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित)	महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत	कुल पद
1.	अनारक्षित	1	1	0	1	3
2.	अनु. जाति	1	0	0	1	2
3.	अनु. जनजाति	1	0	0	1	2
4.	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	1	2
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0	0	0	1
	योग	**5**	**1**	**0**	**4**	**10**

नोट:

1. उक्त पदों में वर्गवार 20 प्रतिशत पद (म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रहेंगे।
2. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक फा.क्र. सी-3-8/2015/3/एक दिनांक 19.11.2015 के अनुसार महिलाओं के पक्ष में समस्त पदों के तेतीस प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्त और प्रभागवार (होरिजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्ट वाइज) होगा।
3. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सी-3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

(2) आयु की गणना:-

समस्त अभ्यर्थीयों के लिये दिनांक 01 जनवरी 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क.सी-3-11/2012/1/3, दिनांक 3 नवम्बर, 2012 तथा क.सी-3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार, निम्नानुसार होगी:-

1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम / मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.वर्ग)	45 वर्ष

(शेष अगले पृष्ठ पर)

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P.-462011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 1169 (UPG)

No./1472/22/D-12/MPRRDA/2024 **Bhopal, Dated : 29.01.2024**

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below.

- **Name of Work :** UPG (MPRRDA SSR : 01.09.2017)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Narsinghpur	1	50415000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **30.01.2024 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/113462/2024 **(TENDER)**

"मेरी सड़क" ऐप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

R-49423/2024

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02
डी-16, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002
Email - mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 26/2023-24 निर्माण कार्य स्टोर रूम एस.डी.ई.आर.एफ. होमगार्ड दरीखाना, जिला जबलपुर (ऑनलाइन निविदा क्र. 2024_MPPHC_328946) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 09.02.2024 तक खरीद कर सायं 6:00 बजे तक** सबमिट किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/113538/2024 R-49429/2024 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. – 462011
No./1728/22/D-12/NIT-Maint./2024 Bhopal, Dated : 01.02.2024

NOTICE INVITING TENDER No. 276/MTN/2024 (BW)

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. Table-1 : Name of Work : Post 5 Year (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Dhar	1	11510000.00

2. Table-2 : Name of Work : Post 10 Year (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Anuppur	1	5146850.00
2	Dhar	1	8616000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **02.02.2024 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/113540/2024 R-49430/2024 **(TENDER)**

"मेरी सड़क" एप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, ग्वालियर संभाग क्र. 02
फ्लेट क्र. 303 एवं 304 थर्ड फ्लोर साक्षी ग्रीन बिल्डिंग, हरदौल गार्डन के फ्रन्ट पर, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर, पिन-474011

निविदा आमंत्रण सूचना- 07/2023-24

कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग, ग्वालियर क्र. 2 द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 07/2023-24 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदा की कार्यवाही की गई है। जिसके ऑनलाइन निविदा क्र. MPPHC_329199_1, है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 07.02.2024 तक** खरीदे जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/113526/2024 R-49428/2024 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-462011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 275/MTN/2024

No./1517/22/D-12/NIT-Maint. /2024 **Bhopal, Dated : 30.01.2024**

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. Table No. 1 :- Name of Work – Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 5 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Bhopal	1	8727644.00
2	Dewas	2	7627776.00
3	Katni	1	3586897.00
4	Raisen	1	5068224.00

2. Table No. 2 :- Name of Work – Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 10 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Burhanpur	4	47651315.00
2	Jabalpur	1	733941.00
3	Khandwa	1	1744257.00
4	Narmadapuram	1	11559711.00
5	Vidisha	1	3822934.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **01.02.2024 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/113496/2024 R-49426/2024 **(TENDER)**

"मेरी सड़क" ऐप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

नोट:-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक 550-2532/1(3)/80 दिनांक 12.02.1981 के अनुसार दिव्यांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष अतिरिक्त छूट दी जावेगी।
2. आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासियों को ही दिया जायेगा।
3. भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार छूट दी जावेगी।

(3) अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग)/साक्षात्कार (उपरोक्त सभी पदों हेतु):-

अनुवीक्षण (स्क्रनिंग)/साक्षात्कार के समय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (574, साउथ सिविल लाईन्स) जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय अनारक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक एवं आयु प्रमाण पत्र की मूलप्रतियों के साथ पठनीय छायाप्रति तथा आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को शैक्षणिक, आयु प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा जारी किया गया तथा सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(4) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :-

(1) अभ्यर्थी दोनों पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उसे आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शित करनी होगी।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो -

(क) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन/विभाग ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन/विभाग का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(ग) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(घ) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है (परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो अधिक संतान का जन्म होता है।)

(3) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है अर्थात् पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अंतिम/चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेंगी, परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

(4) **चयन प्रकिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को होगा।**

(5) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रकम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन पत्रों में की गई त्रुटियों के सुधार हेतु एक निश्चित समय प्रदान किया जावेगा तथा इसी निश्चित समय में समस्त अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार करवाना आवश्यक होगा। निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा, बल्कि अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

(8) आरक्षित प्रवर्ग (अनु.जाति., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.वर्ग) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ-7-13/2004/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 11.07.2005 में दिये गये निर्देशों के अध्याधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(9) दिव्यांग पदों के लिये आवेदन करने की तारीख को, दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। इस उपबंध का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, केन्द्रीय/राज्य सरकार के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र वैध होगा।

(10) साक्षात्कार दिनांक की सूचनाएं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट **www.mpslsa.gov.in** पर प्रदर्शित की जावेगी। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट में प्रकाशित किये जावेंगे जिसका अभ्यर्थी को स्वयं प्रिन्ट निकालना होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगा।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यत: दें।

(12) पुनः मूल्यांकन/पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन संक्षिप्तत: निरस्त कर दिये जायेंगे।

(13) आवेदक को स्क्रीनिंग व साक्षात्कार की सूचना उनके मोबाइल नं. पर एस.एम.एस. के माध्यम से एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वेबसाइट पर दी जावेगी। जिसमें आवेदक समय-समय पर वेबसाइट एवं अपने मोबाइल की जांच करते रहें सूचना न मिलने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं एम.पी. ऑनलाइन की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

प्राप्तांक/स्कोर कार्ड :-

साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिये जायेंगे। अभ्यार्थी अपने प्राप्तांक/स्कोर कार्ड, अपनी आई.डी. (आवेदन क्रमांक) पासवर्ड (जन्मतिथि) एवं ओ.टी.पी. (रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा जावेगा) से लॉगइन कर देख सकते हैं तथा प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी:-

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

विनिष्टीकरण :-

आवेदन पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षापरिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन)
सदस्य सचिव

R-49414/2024

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) 462011

NOTICE INVITING TENDER No. 1170 (PMGSY-Bridge-BW)

No./1469/22/D-12/MPRRDA/2024 **Bhopal, Dated : 29.01.2024**

Online Tenders for Construction of Bridges with 5 years defect liability & maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.pmgsytenders.gov.in** detailed below :

- **Name of Work –** Construction of Bridges under PMGSY including maintenance for Five year after construction

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Indore	1	5583311.00
2.	Khargone	1	7540000.00
3.	Mandla	1	13786000.00

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in **www.pmgsytenders.gov.in.** The bidder would be required to register in the website which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online from **30.01.2024 (17:30 hrs)** and last date for online bid submission is **14.02.2024 (17:00 hrs.).**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/113463/2024 R-49424/2024 **(TENDER)**

''मेरी सड़क'' ऐप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
Block-IInd, 5th Floor, Paryavas Bhavan
Arera Hills, Bhopal (M.P.)-462011

DPR CONSULTANCY OF BRIDGES (Short Time E-Procurement Notice)

No. 1632/22/D-12/Brg.DPR/2023-24 **Bhopal, Dated : 31.01.2024**

Online Bids are invited from the reputed Consultants for preparation of DPR of Bridge under PMGSY-III as per details given below :-

- No. of Packages - 05
- Nodal PIU - Sidhi, Shahdol, Balaghat-2, Shivpuri-2, Narsinghpur,
- No. of Bridges - 16

Total Estimated Construction Cost (in Rs.) - Rs. 540704000.00

- **Cost of Bid Document, Bid Security (EMD) and service charges as appearing on e-procurement portal are to be paid simultaneously through Debit Card/Credit Card/Internet Banking or system generated challan. For detailed procedure of online payment of EMD and submission of affidavit please refer condition number 2 of detailed NIT.**

1. RFP document may be seen, downloaded and purchased from our e-procurement website **https://mptenders.gov.in** from 17:30 hrs on **01.02.2024.**
2. Last date of Submission of bid is date **15.02.2024 upto 15.00 hrs.**

Other details & Conditions may be seen in the detailed NIT and Tender Document for preparation of DPR of Bridges under PMGSY January-2020 amended up to date on our Website **http://mptenders.gov.in.**

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/113522/2024 R-49427/2024 **(TENDER)**

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल

'चयन भवन' मेन रोड नं. 1 चिनार पार्क ईस्ट, भोपाल

आम-सूचना

''सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा **समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023 एवं समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023** का आयोजन हेतु दिनांक 07.04.2023 को विज्ञापन क्रमांक 01/2023 प्रकाशित किया गया था। उक्त परीक्षा हेतु जारी पूर्व विज्ञापन, विभागों/कार्यालयों से प्राप्त पुनरीक्षित आरक्षण तालिका को समाहित कर जारी शुद्धि पत्र क्रमांक MPESB/5-1/421/2024 दिनांक 28.01.2024 एवं तदानुसार घोषित किये जाने वाले परिणाम के संबंध में मण्डल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर म.प्र. के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा उक्त संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता- (1) श्री राहुल दिवाकर अधिवक्ता-751 अग्रवाल कॉलोनी, जबलपुर (2) श्री कौस्तुभ पाठक अधिवक्ता-102 बी ब्लॉक प्रकृति कार्पोरेट 18/2 वाय.एन. रोड, इंदौर एवं (3) श्री विवके खेडकर, अधिवक्ता-विंच्योरकर की गोठ, चावड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें''।

विज्ञापन क्रमांक-16/2023-24

म.प्र. माध्यम/113469/2024 R-49425/2024 **संचालक**

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

'चयन भवन' मैन रोड नं.1 चिनार पार्क ईस्ट, भोपाल

आम-सूचना

''सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा समूह 5 के अंतर्गत स्टॉफ नर्स महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता ए.एन.एम. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन हेतु दिनांक 15.02.2023 को विज्ञापन क्रमांक 53/2023 प्रकाशित किया गया था। उक्त परीक्षा हेतु जारी पूर्व विज्ञापन, विभागों/कार्यालयों से प्राप्त पुनरीक्षित आरक्षण तालिका को समाहित कर जारी शुद्धि पत्र क्रमांक MPESB/प-1/508/2024 दिनांक 01.02.2024 एवं तदानुसार घोषित किये जाने वाले परिणाम के संबंध में मण्डल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर म.प्र. के समक्ष केवियट दायर की जा रही है। यदि किसी अन्य द्वारा उक्त संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाती है, तो उसकी एक प्रति बोर्ड के अधिवक्ता- (1) श्री राहुल दिवाकर अधिवक्ता-751 अग्रवाल कॉलोनी, जबलपुर (2) श्री कौस्तुभ पाठक अधिवक्ता-102 बी ब्लॉक प्रकृति कार्पोरेट 18/2 वाय.एन. रोड, इंदौर एवं (3) श्री विवके खेडकर, अधिवक्ता-विंच्योरकर की गोठ, चावड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विज्ञापन क्रमांक-17/2024

म.प्र. माध्यम/113589/2024 R-49433/2024 **संचालक**

पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाये

सिवनी, हर घर तक नल के माध्यम से शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन योजना का मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। मिशन से जुड़े विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर योजना को मूर्तरूप देने का कार्य करें। ये निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने सिवनी जिले में विभागीय समीक्षा बैठक में दिये।

श्रीमती संपतिया उइके ने जिले में संचालित एकल एवं समूह नल जल योजनाओं की विकासखण्डवार विस्तृत समीक्षा करने के साथ-साथ उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी नल जल योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रगति को लेकर चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया। जल जीवन मिशन के सभी कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। मैदानी अमला अपने क्षेत्र में प्रगतिरत सभी कार्यों का निरंतर अवलोकन करे। श्रीमती उइके ने अधिकारियों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे सभी ग्राम जिन्हें स्रोत न होने से एकल नल-जल योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनमें समूह नल-जल योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने समूह नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जल संसाधन विभाग के छोटे-बड़े टैंकों को स्रोत के रूप में उपयोग करके बरघाट, कुरई, लखनादौन जैसे क्षेत्रों के ग्रामों को लाभांवित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य के लिए नवीन डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।

श्रीमती उइके ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को पेयजल संबंधी कोई भी समस्या न हो, इसका ध्यान रखा जाए। पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिये कंट्रोल रूम बनाकर टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए। श्रीमती उइके ने बैठक में उपस्थित अनुबंधकर्ताओं को भी निर्देशित किया कि सभी कार्यों को पूरी गम्भीरता एवं गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। आगामी ग्रीष्म ऋतु में कहीं भी पेयजल संबंधी समस्या न आए। उन्होंने अनुबंधकर्ताओं को पूरी क्षमता एवं पर्याप्त मानव संसाधन के साथ कार्य करने को कहा।

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थी

नई दिल्ली, नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 7वें 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के जनजातीय विद्यार्थी भी शामिल हुए। जनजातीय कार्य विभाग के अधीन बावड़िया कला स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) के 10 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। कक्षा 11वीं के 8 और कक्षा 9वीं के 2 विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा में शामिल होकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रेरक उद्बोधन का श्रवण किया। जनजातीय कार्य विभाग के अपर आयुक्त डॉ. सतेन्द्र सिंह ने इन विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। इन विद्यार्थियों ने भारत मंडपम में आयोजित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के करीब 3000 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहली बार 10 राज्यों के ई.एम.आर.एस. के 100 विद्यार्थी भी विशेष रूप से शामिल हुए। मध्यप्रदेश से ई.एम.आर.एस. भोपाल के 10 विद्यार्थी शिक्षक श्री शैलेन्द्र नेमा के नेतृत्व में कार्यक्रम में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 घंटे 10 मिनट तक बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों की समस्याओं, प्रतिस्पर्धा की भावना, अभिभावकों की चिंता, समय का प्रबंधन जैसे कई विषयों पर विद्यार्थियों से चर्चा की और उनके प्रश्नों का समाधान किया। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के जिलों में संचालित ई.एम.आर.एस., सी.एम. राइज विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर व आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया।

MADHYA PRADESH BUILDING DEVELOPMENT CORPORATION

(An Agency of Govt. of M.P. Public Works Department)
16-A, CEDMAP Building, Arera Hills, Bhopal (MP)-462011
Telephone No : 0755-4853297, 0755-4853295
Email: einc-mpbdc@mp.gov.in, ajay.nagaria@mp.gov.in
NIT No. : 4268/GM/MPBDC/CW/24/NIT-50 Bhopal, Dated: 01.02.2024

NOTICE INVITING TENDER

Madhya Pradesh Building Development Corporation invites online tender for the following work in Sagar Districts of Madhya Pradesh

1. Construction Work of CM Rise School at Rahatgarh and Jaisingh Nagar, District Sagar (Balance Work) – 01 Work – **Rs. 5145.98 Lakhs**

From bidders registered in M.P. PWD Department under appropriate category. Detailed NIT and tender documents can be viewed and purchased online only from **07.02.2024 at 18:00 hrs.** to **22.02.2024 at 15:30 hrs.** from website **www.mptenders.gov.in**

M.P. Madhyam/113570/2024 **MANAGING DIRECTOR**

R-49432/2024

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश

E-Mail ID : cscd.bhopal@mp.gov.in

विज्ञप्ति

महर्षि बाल्मिकी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पात्रता एवं शर्तें :-

1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो।
2. जे.ई.ई., एडवान्स्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर आई.आई.टी. में, नीट में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में, क्लेट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर एन.एल.आई.यू. में, एन.डी.ए. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/पालक/स्वयं की आय रुपये 6.00 लाख वार्षिक तक है, उन्हें प्रोत्साहन राशि रुपये 50,000/- के मान से प्रदाय की जायेगी।
3. आय सीमा रुपये 6.00 लाख से अधिक एवं रुपये 10.00 लाख से कम होने पर आई.आई.टी., एम्स, एन.एल.आई.यू., एन.डी.ए. तथा नीट (मेडिकल कॉलेज) हेतु रुपये 25000/- प्रोत्साहन राशि देय होगी।
4. जे.ई.ई. मेन्स प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एन.आई.टी. में प्रवेश लेने पर प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/पालक/स्वयं की आय रुपये 6.00 लाख वार्षिक तक है उन्हें प्रोत्साहन राशि रुपये 25000/- के मान से प्रदाय की जायेगी। राशि रुपये 10.00 लाख वार्षिक से अधिक है उन्हें प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।

उक्त योजना के तहत अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में सीधे जमा करें।

योजना के तहत वही विद्यार्थी आवेदन करें, जिन विद्यार्थियों ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उपरोक्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लिया हो। जिला कार्यालयों में आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 20.02.2024** है।

अपर आयुक्त

जी-23692/49440/2024 **अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, मंदसौर

दूरभाष क्रमांक : 07422-256284, फैक्स : 07422-255215
महू-नीमच रोड, शासकीय महाविद्यालय के पास, मंदसौर
E-Mail : eephedmas@mp.nic.in

क्रमांक 308/व.ले.लि./का.यं./2024 **मंदसौर, दिनांक : 01.02.2024**

NIT No. 14/2023-24

निम्नलिखित कार्य की निविदा आमंत्रण सूचना वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर प्रदर्शित की गई है। टेंडर का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

टेंडर आई.डी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रुपयों में)	1. अर्नेस्टमनी (रु. में) 2. आमंत्रण क्र.	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	निविदा क्रय की अंतिम तिथि
2024_PHED_329678_1	Providing, laying & fixing Cement Concrete interlocking Paver Block in Water Testing Lab Premises Sub Division Office Bhanpura of Distt. Mandsaur As Par BOQ	164000/-	1. 3280/- 2. प्रथम आमंत्रण	30 दिवस	**16.02.2024 17.30 तक**

उक्त कार्य की निविदा क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग एकाउंट के माध्यम से भुगतान करने पर ऑनलाइन उक्त वेबसाइट पर क्रय की जा सकती है। निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-23698/49442/2024 **लोक स्वा. यां. खंड, मंदसौर, फोन : 07422232190**

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग
राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान वर्ष 2023
अनुशंसाओं का आमंत्रण

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा कला, साहित्य, सिनेमा, संस्कृति एवं समाज सेवा की विविध विधाओं के क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान उनके सामने अंकित विधाओं के लिये दिए जाने हैं :-

क्र.	सम्मान	विधा	राशि
राष्ट्रीय सम्मान			
1.	महात्मा गांधी सम्मान	गांधी विचार दर्शन (संस्था हेतु)	20.00 लाख
2.	कबीर सम्मान	भारतीय भाषाओं की कविता के लिए	5.00 लाख
3.	कालिदास सम्मान	शास्त्रीय संगीत	5.00 लाख
4.	कालिदास सम्मान	शास्त्रीय नृत्य	5.00 लाख
5.	कालिदास सम्मान	रंगकर्म	5.00 लाख
6.	कालिदास सम्मान	रूपंकर कलाएं	5.00 लाख
7.	मैथिलीशरण गुप्त सम्मान	हिन्दी साहित्य	5.00 लाख
8.	किशोर कुमार सम्मान (फिल्म)	पटकथा लेखन	5.00 लाख
9.	तानसेन सम्मान	हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत	5.00 लाख
10.	लता मंगेशकर सम्मान (फिल्म)	पार्श्व गायन	5.00 लाख
11.	इकबाल सम्मान	उर्दू साहित्य	5.00 लाख
12.	देवी अहिल्या सम्मान (महिला)	लोक एवं जनजातीय पारंपरिक कलाओं के लिए	5.00 लाख
13.	तुलसी सम्मान (पुरुष)	लोक एवं जनजातीय पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में रूपंकर कलाओं के लिए	5.00 लाख
14.	शरद जोशी सम्मान	हिन्दी व्यंग्य, ललित निबंध, संस्मरण रिपोर्ताज, डायरी, पत्र लेखन आदि	5.00 लाख
15.	नानाजी देशमुख सम्मान	सामाजिक, सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, आध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति की मूल अवधारणा के प्रति कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था	5.00 लाख
16.	कवि प्रदीप सम्मान	मंचीय कविता के क्षेत्र में	5.00 लाख
17.	कुमार गंधर्व सम्मान	वादन (आयु समूह 24 से 45 वर्ष)	2.51 लाख
18.	राजा मानसिंह तोमर सम्मान	संगीत, संस्कृति एवं कला संरक्षण में कार्य करने वाली संस्था के लिए	5.00 लाख
19.	सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान	हिन्दी सॉफ्टवेयर सर्च इंजिन, वेब डिजाइनिंग, डिजीटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजीटल ऑडियो विजुअल एडीटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान	5.00 लाख
20.	निर्मल वर्मा सम्मान	भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान	5.00 लाख
21.	फादर कामिल बुल्के सम्मान	विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान	5.00 लाख
22.	गुणाकार मुले सम्मान	हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्यपुस्तकों के लिए लेखन	5.00 लाख
23.	हिन्दी सेवा सम्मान	अहिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन-सृजन से हिंदी की समृद्धि के लिए योगदान	5.00 लाख

राज्य सम्मान

1.	शिखर सम्मान	हिन्दी साहित्य	2.00 लाख
2.	शिखर सम्मान	उर्दू साहित्य	2.00 लाख
3.	शिखर सम्मान	संस्कृत साहित्य	2.00 लाख
4.	शिखर सम्मान	रूपंकर कलाएं	2.00 लाख
5.	शिखर सम्मान	नृत्य	2.00 लाख
6.	शिखर सम्मान	नाटक	2.00 लाख
7.	शिखर सम्मान	संगीत	2.00 लाख
8.	शिखर सम्मान	आदिवासी एवं लोक कलाएं	2.00 लाख
9.	शिखर सम्मान	दुर्लभ वाद्य वादन	2.00 लाख

उक्त सम्मान देश के सृजन सक्रिय साहित्यकार/कलाकार/संस्था की उच्च सृजनात्मकता, असाधारण उपलब्धि, अनवरत दीर्घ साधना तथा समग्र रचनात्मक अवदान के लिए देय हैं। प्रत्येक सम्मान के अंतर्गत आयकर मुक्त सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है।

वर्ष 2023 के इन सम्मानों हेतु संबंधित विधाओं के प्रति सार्थक सरोकार और रुझान वाले समीक्षकों, लेखकों, विचारकों, कला-रसिकों, आलोचकों एवं संस्थाओं से ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों के चयन के लिए अनुशंसाएं विधिवत् आमंत्रित की जाती हैं, अनुशंसाएं निम्न प्रारूप में भेजी जा सकती हैं :-

1. सम्मान का नाम (जिसके लिए अनुशंसा की जा रही है)
2. अनुशंसित का पूरा नाम
3. अनुशंसित की आयु
4. अनुशंसित का वर्तमान पता एवं दूरभाष, मोबाइल, ई-मेल आदि
5. अनुशंसित की सृजनात्मक एवं प्रतिष्ठादायी उपलब्धियों का सुस्पष्ट विवरण, छायाचित्र, ब्रोशर, कैटलॉग आदि
6. प्रस्तावक का नाम, पता एवं दूरभाष क्रमांक

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सम्मान एवं वर्ष के लिए अलग-अलग अनुशंसाएं तथा प्रत्येक सम्मान का नाम विधा सहित लिफाफे के ऊपर अंकित किया जाना आवश्यक है। उल्लेखित सम्मानों के लिए गठित जूरी समिति के समक्ष अनुशंसाएं विचार एवं निर्णय के लिए रखी जावेंगी। चयन समिति की सर्वसम्मत अनुशंसा पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा। घोषणा तक सभी कार्यवाहियां गोपनीय होती हैं। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा और न ही दूरभाष पर जानकारी देना संभव हो सकेगा। प्रविष्टियां तथा संलग्न दस्तावेज लौटाये नहीं जा सकेंगे। जमा प्रस्तावों पर संशोधन आदि भी मान्य न होगा। प्रत्येक सम्मान के लिए अलग-अलग अनुशंसाएं **11 मार्च, 2024 तक संचालक, संस्कृति संचालनालय, 1, शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे), भोपाल-462016** के पते पर पहुंचाना आवश्यक है।

संचालक

जी-23657/49435/2024 **संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश**

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष : 07592-297254
E-Mail : dean.vdsA@mp.gov.in, Website : www.gmcvidisha.org

क्रमांक 493/स्था./सीएमओ. विज्ञप्ति-6/24 **विदिशा, दिनांक : 01.02.2024**

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018 के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के अधीन निम्नलिखत आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर					वेतनमान
			UR	SC	ST	OBC	EWS	
1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	01	--	--	01	--	--	छठवें वेतनमान 15600-39100+ 5400 ग्रेड-पे के समकक्ष
2.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	03	01	--	01	---	01	7वां वेतनमान लेवल (12) में पे-मेट्रिक्स 56,100/- अनुसार देय होगा।

उक्त पदों की शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अर्हताएं निम्नानुसार हैं :-

क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष
2.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष

उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संचालक, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट **www.medicaleducation.mp.gov.in** एवं अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की वेबसाइट पर **www.gmcvidisha.org** पर उपलब्ध है। आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के नाम से बंद लिफाफे में पद का नाम व स्वयं का नाम एवं श्रेणी आवश्यक रूप से अंकित कर भेजें (**आवेदन की अंतिम तिथि 22.02.2024 सायं 5.00 बजे तक है**) निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की तिथि पृथक से संस्था की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जावेगी। स्क्रूटिनी एवं साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु समय-समय पर संस्था की वेबसाइट का अवलोकन करें।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अटल बिहारी वाजपेयी

जी-23691/49439/2024 **स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा**

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, 1, शिवाजी नगर, भोपाल

दूरभाष-0755-2731261, 0755-2441026, www.bgtrrd.mp.gov.in

क्रमांक : एफ 17/सं.नि./2024/231 **भोपाल, दिनांक : 01.02.2024**

चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति आवेदन की अंतिम तिथि 20.02.2024

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सा अधिकारियों (एम.बी.बी.एस.) के 68 रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, हमीदिया अस्पताल परिसर, भोपाल-462001 से **विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 20.02.2024, प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक** अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु. 500/- तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के लिये रु. 250/- का संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल (Director, Gas Relief and Rehabilitation, Bhopal) के नाम का बैंक ड्राफ्ट जमा कर आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं।

उपरोक्त भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रमाण-पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ समक्ष में या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक **20.02.2024** के सायं 5.00 बजे तक संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, हमीदिया अस्पताल परिसर, भोपाल-462001 में जमा किये जा सकते हैं।

चिकित्सा अधिकारियों (एम.बी.बी.एस.) के रिक्त पदों (जो परिवर्तनीय हैं), संविदा वेतन एवं सेवा शर्तों का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट **bgtrrd.mp.gov.in** पर देखा जा सकता है।

सहायक संचालक

जी-23693/49441/2024 **गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल**

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

(Established Under an Act of State Assembly in 1991)

Raja Bhoj Marg (Kolar Road), Chuna Bhatti, Bhopal, Madhya Pradesh 462016

NAAC ACCREDITED GRADE "A"

सत्र 2023-24
(जनवरी-दिसम्बर)
प्रवेश प्रारंभ

- ❖ दूरस्थ शिक्षा का प्रदेश में एकमात्र शासकीय विश्वविद्यालय।
- ❖ न्यूनतम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री।
- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) सत्र 2022-23 से लागू।
- ❖ पाठ्यक्रम/विषय/क्षेत्रीय केन्द्र/अध्ययन केन्द्र परिवर्तन की सुविधा।

नेटवर्किंग सक्षमता निर्माण संसाधनों को साझा करके और गुणवत्ता सुनिश्चित करके राष्ट्रीय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का प्रसार।

UGC-DEB/AICTE/RCI/NCTE से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का संचालन

Our Motto – Embrace, Engage, Enlighten and Empower

हमारा लक्ष्य - उच्च शिक्षा से वंचितों तक पहुंचना

UG Programmes	Eligibility	Duration	SLM Medium	Fees
B.A. (Bachelor of Arts)	10+2	3 Years	Hindi/English	2500
B.Sc. (Bachelor of Science Bio/Maths)	10+2 (Bio/Maths)	3 Years	Hindi/English	2965
B.Sc. (Data Science)	10+2 (Maths)	3 Years	Hindi/English	8000
B.Sc. (Cyber Security)	10+2 (Maths)	3 Years	Hindi/English	8000
B.Com. (Bachelor of Commerce)	10+2 (Commerce/Science)	3 Years	Hindi/English	2730
Bachelor of Library Information Science (B.Lİ.Sc)	Graduate	1 Year	Hindi	9000
Bachelor of Journalism (BJ)	Graduate	1 Year	Hindi	9000
BBA (Bachelor of Business Administration)	10+2	3 Years	English	9000
BCA (Bachelor of Computer Application)	10+2 with Maths	3 Years	English	8000

PG Programmes	Eligibility	Duration	SLM Medium	Fees
M.B.A. (General)	Graduate	2 Years	English	9000
M.B.A. (Lateral Entry)	BE/B Tech or BBA/BMS (4 Years)	1 Year	English	9000
M.B.A. (MM)	Graduate	2 Years	English	9000
M.A. (Hindi Lit.)	Graduate	2 Years	Hindi	6600
M.A. (English Lit.)	Graduate	2 Years	English	6600
M.A. (Political Science)	Graduate	2 Years	Hindi	6600
M.A. (Economics)	Graduate	2 Years	Hindi	6600
M.A. (Sociology)	Graduate	2 Years	Hindi	6600
M.A. (History)	Graduate	2 Years	Hindi	6600
M.A. (Geography)	Graduate	2 Years	Hindi	8640
MSW	Graduate	2 Years	Hindi/English	9000
Master of Journalism (MJ)	Graduate with Journalism	2 Years	Hindi	9000
M.Sc. (CYBER SECURITY)	Graduate in Cyber Security/ Computer Science/Maths	2 Years	English	9000
M.Sc. (Botany)	Science Graduate with Botany/ Bio. Technology	2 Years	English	9000
M.Sc. (Maths)	Science Graduate with Maths	2 Years	English	9000
M.Sc. (Physics)	Science Graduate with Physics/ BE. Electronic & Communication.	2 Years	English	9000
M.Sc. (Chemistry)	Science Graduate with Chemistry	2 Years	English	9000
M.Sc. (Zoology)	Science Graduate with Zoology/ Bio. Technology	2 Years	English	9000
M.Sc. (IT)	Science Graduate with IT/Computer Science	2 Years	English	9000
MCA	Passed any graduation degree (BE/B.Tech/B.Sc/B.Com./B.A./B.Voc./BCA) preferably with Mathematics at 10+2 level or at Graduation level. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination. (for students having no Mathematics background compulsory bridge course and additional bridge course related to computer subject as per the norms of the University.	2 Years	English	9000
MCA (Lateral Entry)	B.Tech/B.E. (CSE/IT) or BCA (4 Years)	1 Year	English	9000

PG Diploma Programmes	Eligibility	Duration	SLM Medium	Fees
PG Diploma in Cyber Security.	Graduate in Cyber Security/Computer Science/Maths	2 Years	English	8500
PG Diploma in Management Logistics and Supply Chain Mgt.	Graduate	2 Years	English	8500
PG Diploma in Event Management.	Graduate	2 Years	English	8500
PG Diploma in Energy Management.	Graduate	2 Years	English	8500

Diploma Programmes	Eligibility	Duration	SLM Medium	Fees
Diploma in Business Administration (DBA)	10+2	1 Year	English	9000
Diploma in Management (DIM)	10+2	1 Year	English	9000
Diploma in Computer Application (DCA)	10+2	1 Year	Hindi	8280
Diploma in Nutrition and Health Education (DNHE)	10+2 with Biology/Home Science	1 Year	English	5880
Ramcharitra manas se samajik vikas me Diploma (RSSM)	Graduate	1 Year	Hindi	3000
Diploma in Logistics and Supply Chain Management (DLSCM)	10+2	1 Year	English	8000
Diploma in Tribal Development (DTD)	10+2	1 Year	English	4000
Diploma in Travel and Tourism (DTT)	10+2	1 Year	English	5000
Diploma in Rural Management (DRM)	10+2	1 Year	English	4000
Diploma in Event Management (DEVM)	10+2	1 Year	English	8000
Diploma in Energy Management (DEM)	10+2	1 Year	English	6000
Diploma in Cyber Security (DCS)	10+2	1 Year	English	8000
Diploma in Data Science (DDS)	10+2	1 Year	English	8000
Diploma in AI & Data Science (DADS)	10+2	1 Year	English	8000

Certificate Programmes	Eligibility	Duration	SLM Medium	Fees
Certificate in Human Rights (CHR)	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Rural Development (CRD)	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Indian Literature	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Written and Spoken Sanskrit	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Introduction to Vedas	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Indic Philosophy	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Ayurvedic Dietetics	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Indian Education and Holistic Development.	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Basics of Intellectual Property Rights	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Indian Cultural Heritage	10+2	1 Year	Hindi	3312
Certificate in Introduction to Yoga Nidra	10+2	1 Year	Hindi	3312
Foundation Course (Special Education)	10+2 (Inservice Teacher)	3 Months	Hindi/English	2150

आवेदन करने की प्रकिया

1. प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक स्वयं **www.mpbou.edu.in** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
2. असुविधा होने पर नजदीकी कियोस्क पर जाकर प्रवेश आवेदन एवं फीस जमा की जा सकती है।
3. अर्हतादायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति तथा मूल अंकसूची एवं अन्य मूल दस्तावेज से मिलान करा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराएं।
4. चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का चयन करने पर शोध सहित स्नातक उपाधि प्रदान की जावेगी।

नोट: बी.एड/डी.एल.एड/बी.एड (विशेष शिक्षा) में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। जिसकी सूचना अलग से विज्ञापित कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है।

प्रवेश हेतु जानकारी के लिए

आपकी शिक्षा आपके द्वार

क्षेत्रीय केन्द्रों के पते निम्नानुसार हैं :- 1. क्षेत्रीय निदेशक भोपाल, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, राजा भोज मार्ग (कोलार रोड) भोपाल-462016 (म.प्र.), फोन नं. - 0755-2490494, 2492105, 2492272, **2. क्षेत्रीय निदेशक इंदौर,** देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर आई.एम.एस. भवन, खण्डवा रोड, इन्दौर-452001 (म.प्र.) फोन नं. - 0731-2465689, **3. क्षेत्रीय निदेशक ग्वालियर,** न्यू कलैक्ट्रेट रोड, सत्यम रेजीडेंसी टॉवर के पास, प्राइम हॉस्पिटल वाली गली, कैलाश नगर, ग्वालियर-474006 (म.प्र.) फोन नं. - 0751-2345559, **4. क्षेत्रीय निदेशक जबलपुर,** पी.एस.एम. महाविद्यालय, दूसरा तल, कलैक्ट्रेट के पास, जबलपुर-482002 (म.प्र.) फोन नं. - 0761-2997294, **5. क्षेत्रीय निदेशक रीवा,** शासकीय सदाशिव माधवराव गोलवलकर महाविद्यालय परिसर, सिविल लाइन, रीवा-488001 (म.प्र.) फोन नं. - 07662-297210, 9425361851, **6. क्षेत्रीय केन्द्र सतना,** राजा भोज परिसर पॉलिटेक्निक कालेज के आगे नीमी रोड बदखर जिला सतना-485005 (म.प्र.) फोन नं. - 07672-299140, **7. क्षेत्रीय केन्द्र सागर,** विश्वविद्यालय क्वार्टर क्रमांक 05, स्वर्ण जयन्ती हॉल के पीछे नेपाल पैलेस, सागर-470001 (म.प्र.) फोन नं. - 07582-264130, **8. क्षेत्रीय केन्द्र उज्जैन,** विशाला विकास खण्ड ''स''-भवन प्रथम तल, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर भरतपुरी, उज्जैन-458010 (म.प्र.) फोन नं. - 0734-2526993, **9. क्षेत्रीय केन्द्र छिन्दवाड़ा,** शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा-480001 (म.प्र.) फोन नं. - 07162-243716, **10. क्षेत्रीय केन्द्र नर्मदापुरम्,** शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, नर्मदापुरम्-481001 (म.प्र.), फोन नं. - 07574-254096, **11. क्षेत्रीय केन्द्र बड़वानी,** शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)-451551 (म.प्र.) फोन नं. - 07290-222099, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट - **www.mpbou.edu.in**

म.प्र. माध्यम/113547/49431/2024

कुलसचिव

हिन्दू महाविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय

नॉर्थ कैम्पस, दिल्ली–110007, फोन. नं : 011-27667184, फैक्स : 27667284

ई–मेल : principal@hinducollege.org, वेबसाइट : www.hinducollege.ac.in

विज्ञापन क्रमांक एचसी–1/3079 दिनांक 20.01.2024

विभिन्न गैर-शिक्षण पदों के लिए स्थायी आधार पर वेब लिंक **https://hinducollegerecuitments.in** पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन की पूरी जानकारी कॉलेज की वेबसाइट **www.hinducollege.ac.in** पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 09 फरवरी, 2024** है। कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल कॉलेज की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसकी निगरानी करना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी।

क्र. सं.	पद	समूह	पे लेवल	आयु सीमा	पदों की संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	पीडब्ल्यूबीडी
1	प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति विज्ञान)	सी	लेवल 04	30	01	00	00	00	00	01	00
2	प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)	सी	लेवल 04	30	03	00	00	01	00	02	00
3	प्रयोगशाला सहायक (भौतिकी)	सी	लेवल 04	30	04	00	00	01	01	01	01 (एलवी)
4	प्रयोगशाला सहायक (प्राणी विज्ञान)	सी	लेवल 04	30	01	00	01	00	00	00	00
5	कनिष्ठ सहायक	सी	लेवल 02	27	03	00	01	01	00	01	00
6	प्रयोगशाला परिचारक	सी	लेवल 01	30	33	07	02	11	01	11	01 (एलडी)
7	पुस्तकालय परिचारक	सी	लेवल 01	30	03	00	01	02	00	00	00

संक्षिप्त रूपः यूआर–अनारक्षित, ओबीसी–अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एसटी–अनुसूचित जनजाति, एससी–अनुसूचित जाति, एलवी–अंधता/कम दृष्टि, एलडी–**दिव्यांगता.**

प्रयोगशाला सहायक (भौतिकी/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ

अनिवार्यः

1. प्रासंगिक विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

या

प्रासंगिक विषय के साथ स्नातक।

कनिष्ठ सहायक

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ

अनिवार्यः

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (10+2) या इसके समकक्ष योग्यता।
2. टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर के माध्यम से टाइपराइटिंग।

प्रयोगशाला परिचारक

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ

अनिवार्यः

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्रासंगिक विज्ञान विषयों के साथ 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

पुस्तकालय परिचारक

1. किसी भी राज्य शिक्षा बोर्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रमाणपत्र।

वांछितः

किसी भी संस्थान से कंप्यूटर में माध्यमिक स्तर या बुनियादी पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर।

प्राचार्य

केंद्रीय योग और प्राकृतिक-चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058

वेबसाइट: www.ccryn.gov.in, फोन: 011-285204329, 30, 31, 32, 28522002, फैक्स: 011-28520435

विज्ञा.सं. 4-6/2023-24/सीसीआरवाईएन/स्था./भर्ती II/

केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक-चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (कें.यो.प्रा.अ.प.) आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है.

2. अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से नियमित आधार पर विभिन्न पदों की सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं. **आवेदन जमा करना शुरू करने की तिथि और अंतिम तिथि नीचे दी गयी हैं:**

आवेदन करना शुरू करने की तिथि	**15.01.2024**	**सुबह 10:00 बजे**
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**रोजगार और निर्माण में विज्ञापन प्रकाशन से 25 दिन**	**11:59 बजे**

क्र. सं.	पदों के नाम और दिए गए पदों के लेवल, पदों की संख्या	पदों की संख्या					
		अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	अना	कुल
1.	**अनुसंधान अधिकारी** (योग एवं प्राकृतिक-चिकित्सा) पे लेवल-10 (रु. 56100-177500/-)	01	-	02	01	06	10
2.	**अनुसंधान अधिकारी** (स्नायु शरीर विज्ञान) पे लेवल-10 (रु. 56100-177500/-)	-	-	01	-	01	02
3.	**अनुसंधान अधिकारी** (जीवन विज्ञान) पे लेवल-10 (रु. 56100-177500/-)	-	01	-	-	01	02
4.	**अनुसंधान अधिकारी** (नैदानिक मनोविज्ञान) पे लेवल-10 (रु. 56100-177500/-)	01	-	01	-	-	02
5.	**चिकित्सा अधिकारी** (एलोपैथी) पे लेवल-10 (रु. 56100-177500/-)	-	-	-	-	02	02
6.	**सांख्यिकीय सहायक**, पे लेवल-7 (रु. 44900-142400/-)	01	-	01	-	-	02
7.	**सहायक/सहायक अनुभाग अधिकारी**, पे लेवल-7 (रु. 44900-142400/-)	-	-	-	01	01	02
8.	**कनिष्ठ हिंदी अनुवादक**, पे लेवल-6 (रु. 35400-112400/-)	-	-	01	-	01	02
9.	**कार्यालय अधीक्षक**, पे लेवल-6 (रु. 35400-112400/-)	01	01	-	-	-	02
10.	**लेखाकार**, पे लेवल-6 (रु. 35400-112400/-)	-	-	01	01	01	03
11.	**कनिष्ठ स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)**, पे लेवल-5 (रु. 29200-92300/-)	-	-	-	-	01	01
12.	**बहुकार्य स्टाफ**, पे लेवल-1 (रु. 18000-56900/-)	-	-	01	-	01	02
	कुल	**04**	**02**	**08**	**03**	**15**	**32**

अनिवार्य अर्हताएं और अनुभव

क्रम सं.	पदों के नाम	अनिवार्य अर्हता	अनुभव	पे लेवल	अधिकतम आयु सीमा
1.	**अनुसंधान अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक-चिकित्सा)**	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योग/प्राकृतिक-चिकित्सा में बीएनवाईएस और पीएच.डी. या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योग/प्राकृतिक-चिकित्सा में बीएनवाईएस और एम.डी. या योग या विषय से संबंधित योग चिकित्सा में एम.एससी. (योग) और पीएच.डी.	-	लेवल-10	40 वर्ष
2.	**अनुसंधान अधिकारी**	(किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शरीर विज्ञान में एमबीबीएस और एम.डी./पीएच.डी. **वांछनीय:** योग और स्नायु शरीर विज्ञान में प्रकाशित रचना कार्य.	-	लेवल-10	40 वर्ष
3.	**अनुसंधान अधिकारी (जीवन विज्ञान)**	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैविक रसायन विज्ञान/प्रतिरोधक विज्ञान/आणविकजीव-विज्ञान/साइटोजेनेटिक्स में एमबीबीएस और एम.डी./पीएच.डी. या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैविक रसायन विज्ञान/प्रतिरोधक विज्ञान/आणविकजीव-विज्ञान/साइटोजेनेटिक्स में एम.एससी., पीएच.डी. **वांछनीय:** योग और जीवन विज्ञान में प्रकाशित रचना कार्य.	-	लेवल-10	40 वर्ष
4.	**अनुसंधान अधिकारी (नैदानिक मनोविज्ञान)**	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक मनोविज्ञान/स्नायु मनोविज्ञान में एमबीबीएस और एम.एससी./एम.फिल./पीएच.डी. या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक मनोविज्ञान/स्नायु मनोविज्ञान में एम.ए./एम.एससी., पीएच.डी.	-	लेवल-10	40 वर्ष
5.	**चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथी)**	1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग II (लाइसेंसधारी अर्हताओं के अतिरिक्त) में शामिल मान्यताप्राप्त अर्हता. 2. अनिवार्य घूर्णित अन्तःशिक्षुता पूरी की हो. **टिप्पणी:** तृतीय अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता धारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन 3 में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए. 3. राज्य/केंद्र के चिकित्सा परिषदों में पंजीकरण कराया होना चाहिए.	किसी स्वास्थ्यरक्षक संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव.	लेवल-10	40 वर्ष
6.	**सांख्यिकीय सहायक**	सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी सहित एक विषय के रूप में गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य आदि जैसे अन्य किसी विषय में मास्टर डिग्री. या सांख्यिकी या एक विषय के रूप में सांख्यिकी सहित गणित में डिग्री और डाटा के कार्य करने में 3 वर्ष का अनुभव.	-	लेवल-7	30 वर्ष
7.	**सहायक/सहायक अनुभाग अधिकारी**	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री.	-	लेवल-6	30 वर्ष
8.	**कनिष्ठ हिंदी अनुवादक**	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री. या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय या दो में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और अन्य अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी सहित हिंदी/अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री. या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी और हिंदी सहित बैचलर डिग्री और हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र या भारत सरकार के उपक्रमों सहित केंद्र/राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य में 2 वर्ष का अनुभव.	-	लेवल-6	35 वर्ष
9.	**कार्यालय अधीक्षक**	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री. (2) सरकारी नियमों, विनियमों और कार्यविधियों की पर्याप्त जानकारी और स्वतंत्र रूप से पत्र-व्यवहार कार्य करने की योग्यता.	किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों या किसी बड़े संस्थान में वरिष्ठ लिपिक या समतुल्यपद पर कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव.	लेवल-6	35 वर्ष
10.	**लेखाकार**	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम या उससे उच्चतर अर्हता. या 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक. 2. भारत के सीएजी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो.	सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/स्वायत्त निकायों/किसी बड़े सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में बजट, लेखा के देख-रेख, बिल तैयार करने आदि के कार्य में कम-से-कम 05 (वर्ष) का अनुभव. किसी लेखा-परीक्षा कार्यालय/केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों/उपक्रमों आदि में लगभग 5 वर्ष का अनुभव.	लेवल-6	35 वर्ष
11.	**कनिष्ठ स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)**	1. मैट्रिक या समतुल्य. 2. स्टेनोग्राफी में 80 श.प्र.मि. की गति और क्रमशः अंग्रेजी/हिंदी टंकण में 30/25 श.प्र.मि. की गति. **वांछनीय:** 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री. 2. किसी सरकारी/वाणिज्यिक उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी/बड़े संस्थान में स्टेनोग्राफर के रूप में पूर्व का अनुभव.	-	लेवल-4	30 वर्ष
12.	**बहुकार्य स्टाफ**	1. माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की हो. 2. सरल अंग्रेजी/हिंदी या अन्य कोई क्षेत्रीय भाषा पढने और लिखने की योग्यता.	-	लेवल-1	25 वर्ष

टिप्पणी:

1. अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक आवेदकों हेतु आरक्षण/छूट भारत सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार दिए जाएंगे. आरक्षित पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को अपनी संबंधित श्रेणी स्पष्ट लिखनी चाहिए.
2. किसी आवेदक के बदले या उसके द्वारा किसी भी रूप में सिफारिश करने पर पद हेतु विचार किये जाने के योग्य नहीं माना जाएगा.
3. विज्ञापन और सामान्य शर्तों के विवरण वेबसाइट: **www.naturopathyday.in** पर देखे जा सकते हैं.
4. अधिसूचना और चयन प्रक्रिया में सुधार नियमों के अनुसार दूर किये जाएंगे.
5. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पद हेतु निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता निर्धारण के लिए सावधानीपूर्वक विस्तृत विज्ञापन पढ़ लेना चाहिए. पद हेतु आवेदन करने की **अंतिम तिथि** रोजगार और निर्माण **में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 25 दिन होगी.** ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक एनआईईएलआईटी के कार्यालयीय वेबसाइट: **https://recruit.nielit.in** पर उपलब्ध है.

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

खड़कवासला, पुणे- 411023

रोज़गार सूचना

निम्नांकित ग्रुप 'सी' रिक्तियों (बकाया रिक्तियों सहित) को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं और विवरण नीचे दिए गये हैं:

क्र. सं.	पद	आयु	पदों का वेतनमान (सातवें सीपीसी के पे मैट्रिक्स के अनुसार)	आरक्षण					कुल पद	कुल पदों में से आरक्षण	
				अना (सामा)	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस		पीडब्ल्यूबीडी	भूपूसै
1.	**अवर श्रेणी लिपिक**	18-27 वर्ष	पीएमएल-2 (रु. 19900-63200)	06	02	01	05	02	**16**	03 1-श्रदि, 1-अदि, (बीएल/ओएल) 1-एमडी	02
2.	**स्टेनोग्राफर**	18-27 वर्ष	पीएमएल-4 (रु. 25500-81100)	01	00	00	00	00	**01**	--	--
3.	ड्राफ्ट्समैन	18-27 वर्ष	पीएमएल-4 (रु. 25500-81100)	02	00	00	00	00	02	--	--
4.	**सिनेमाप्रोजेक्शनिस्ट-II**	18-25 वर्ष	पीएमएल-2 (रु. 19900-63200)	01	00	00	00	00	**01**	--	--
5.	**रसोइया**	18-25 वर्ष	पीएमएल-2 (रु. 19900-63200)	10	00	01	01	02	**14**	--	01
6.	**कम्पोजीटर-सह-प्रिंटर**	18-25 वर्ष	पीएमएल-2 (रु. 19900-63200)	01	00	00	00	00	**01**	--	--
7.	**सिविलियन मोटर ड्राइवर (ओजी)**	18-27 वर्ष	पीएमएल-2 (रु. 19900-63200)	02	00	01	00	00	**03**	--	--
8.	**बढ़ई**	18-25 वर्ष	पीएमएल-2 (रु. 19900-63200)	02	00	00	00	00	02	--	--
9.	**फायरमैन**	18-27 वर्ष	पीएमएल-2 (रु. 19900-63200)	02	00	00	00	00	**02**	--	--
10.	**टीए-बेकर एवं कन्फेक्श**	18-25 वर्ष	पीएमएल-1 (रु. 18000-56900)	01	00	00	00	00	**01**	--	--
11.	**टीए- साईकल मरम्मतकर्ता**	18-25 वर्ष	पीएमएल-1 (रु. 18000-56900)	02	00	00	00	00	**02**	--	--
12.	**टीए-प्रिंटिंग मशीन प्रचालक**	18-25 वर्ष	पीएमएल-1 (रु. 18000-56900)	01	00	00	00	00	**01**	--	--
13.	**टीए- बूट मरम्मतकर्ता**	18-25 वर्ष	पीएमएल-1 (रु. 18000-56900)	01	00	00	00	00	**01**	--	--
14.	**बहुकार्य स्टाफ-कार्यालय एवं प्रशिक्षण (एमटीएस-ओएवंटी)**	18-25 वर्ष	पीएमएल-1 (रु. 18000-56900)	78	01	05	52	15	**151**	**07** 2-दृदि (एलवी), 1-श्रदि, 1-अदि (ओएल/ओए), 3-एमडी	**16**
	कुल पद			110	03	08	58	19	198	10	19

(**अना**-अनारक्षित (सामान्य), अजा-अनुसूचित जाति, **अजजा**-अनुसूचित जनजाति, **अपिव**-अन्य पिछड़ा वर्ग, **ईडब्ल्यूएस**-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, **पीडब्ल्यूबीडी**-विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति, **भू.पू.सै.**-भूतपूर्व सैनिक, **अदि**-अस्थि दिव्यांग, **बीएल**-दोनों पैर प्रभावित किंतु, बाजू नहीं, **ओएल**-एक पैर प्रभावित, **ओए**-एक बाजू प्रभावित, **एलवी**-कमजोर दृष्टि, **श्रदि**-श्रवण दिव्यांग और **एमडी**-बहुदिव्यांगता).

टिप्पणी 1: अकादमी कार्यबल पर जोर देती है, जोलैंगिक संतुलन को परिलक्षित करता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

टिप्पणी 2: बहुकार्य स्टाफ- कार्यालय एवं प्रशिक्षण (उपरोक्त क्रम सं. 14) हेतु निर्दिष्ट ड्यूटीः एमटीएस-ओएवंटी के पद की शैक्षिक अर्हता दसवीं/मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण होगी और उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गये कार्य के अनुसार सफाईवाला/साईस (घोड़ों एवं अस्तबलों की सफाई)/ कैडेट आदेशपाल/फैटिगमैन/मसालची/ मेस वेटर/चौकीदार/ग्राउंड्समैन/माली/स्टोरमैन/ संदेशवाहक/वितरक/ नाव निर्माता/ टिंडल/ डोज़र ड्राइवर/प्रयोगशाला परिचर/कार्यशाला परिचर/पुस्तकालय परिचर/गैलरी परिचर आदि की ड्यूटी करनी होगी. **शैक्षिक अर्हता के संदर्भ में एमटीएस-ओएवंटी के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इस टिप्पणी में दी गयी एमटीएस-ओएवंटी की ड्यूटी करनी होगी.**

टिप्पणी 3: आरक्षित पदों हेतु आयु में छूटः अजा/अजजा=5 वर्ष, अपिव=3 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी/भूपूसै हेतु लागू अनुसार

टिप्पणी4 : विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तिः

	पदों के नाम	पीडब्ल्यूबीडी हेतु आरक्षित
(i)	**अवर श्रेणी लिपिक (03)**	01-एमडी (बहुदिव्यांगता) 01-अदि (अस्थि दिव्यांग) (अर्थात बीएल- दोनों पैर/ ओएल-एक पैर) 01-श्रदि (श्रवण दिव्यांग)
(ii)	**बहुकार्य स्टाफ-कार्यालय एवं प्रशिक्षण (एमटीएस-ओएवंटी) (07)**	02-दृदि (दृष्टि दिव्यांग) (अर्थात एलवी-कमजोर दृष्टि-दिव्यांगता की प्रतिशतता 40% से 80% के बीच) 01-श्रदि (श्रवण दिव्यांग) 01-अदि (अस्थि दिव्यांग) (अर्थात ओएल-एक पैर/ओए-एक बाजू) 03-एमडी (बहुदिव्यांगता)

उम्मीदवारों हेतु निर्देश :

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइटः **https://ndacivrect.gov.in** पर ऑनलाइन भरा जाना चाहिए और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रोजगार और निर्माण **में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 10 दिन होगी.**
2. केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाएंगे. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करना चाहिए और भविष्य के कार्यों के लिए आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए. उम्मीदवारों को रा.र.अ. के पास डाक द्वारा किसी भी आवेदन का प्रिंटआउट/ प्रमाण-पत्र/प्रतियां नहीं भेजनी चाहिए.
3. उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, जो वेबसाइटः **https://ndacivrect.gov.in** पर उपलब्ध हैं.
4. अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को उनके हित में अंतिम तिथि से पर्याप्त पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है, चूंकि, अंतिम कुछ दिनों/ घंटों के दौरान इंटरनेट पर अधिक लोड या वेबसाइट जाम के कारण वेबसाइट पर लॉग-ऑन कर सकने में अक्षमता/असफलता की संभावना हो सकती है.
5. रा.र.अ. उक्त कारणों या अन्य किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हो पाने पर उम्मीदवारों के किसी दायित्व को स्वीकार नहीं करता है.
6. उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये विवरण (अर्थात नाम, जाति/श्रेणी, प्राप्त अंक/ प्रतिशतता आदि) सही होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर आवेदक की उम्मीदवारी भर्ती के किसी भी चरण में अयोग्य मानी जाएगी. ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी/जमा की गयी सभी जानकारी प्रमाणित करने की जिम्मेदारी एकमात्र उम्मीदवारों की होगी.
7. केवल ऑनलाइन आवेदन जमा करने मात्र से उम्मीदवार चयन परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं होंगे. प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या पदों हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता में प्राप्त अंकों पर आधारित चयन परीक्षा के लिए कम की जाएगी, जिसकी संख्या अनंतिम रूप से लिखित परीक्षा हेतु इस विज्ञापन की प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या से 10 गुणा या उससे अधिक और लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित कौशल परीक्षा हेतु चार गुणा या उससे अधिक हो सकती है. इस संदर्भ में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के निर्णय अंतिम होंगे.
8. उम्मीदवारों को अपने नामों के चयन/ ताजा जानकारियों आदि से संबंधित अपनी वस्तुस्थिति के लिए नियमित वेबसाइट देखना और मोबाइल चेक करना चाहिए. **चयन परीक्षाओं के लिए केवल चुने गये उम्मीदवारों को ही सूचित किये जाएंगे.**
9. कोविड-19 की जोखिम से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय-समय पर कोविड-19 से बचाव हेतु केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी निर्देशों/नियमों का पालन करना चाहिए.
10. चयन परीक्षाओं हेतु चुने गये उम्मीदवारों को डबल वैक्सीन लिया होना चाहिए. किसी भी उम्मीदवार को चयन परीक्षाओं के दौरान वैक्सीनेशन प्रमाण-पत्र दिए बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
11. नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अपेक्षित होने पर किसी या सभी पदों को नहीं भरने के अधिकार सुरक्षित रखते हैं. भर्ती प्रक्रिया कोई भी कारण बताए बिना किसी भी चरण में रोकी जा सकती है.

श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय न्यास मन्दसौर, म.प्र.

तीर्थंकर भगवान महावीर मार्ग (संजीत मार्ग), मन्दसौर, (म.प्र.) 458001
(बी.सी.आई. से मान्यता प्राप्त एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से सम्बद्ध)

प्राचार्य के एक पद हेतु विज्ञप्ति

(शासकीय विधि महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राध्यापक या प्राचार्य भी आवेदन कर सकते हैं।)

(क) योग्यता -

1. पी.एच.डी. की उपाधि (विधि विषय में)
2. प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा उच्च शैक्षणिक संस्थान में अध्यापन एवं शोध कार्य का पंद्रह वर्ष का अनुभव।
3. न्यूनतम दस शोध कार्य का प्रकाशन जो कि यू.जी.सी. द्वारा सूचीबद्ध जर्नल्स में हो।
4. यू.जी.सी. रेगुलेशन्स 2018 के एपेन्डिक्स II टेबल 2 के अनुसार न्यूनतम 110 रिसर्च स्कोर के अनुसार शोध कार्य का प्रकाशन हो।

(ख) अवधि -

1. प्राचार्य पद पर पांच वर्ष के लिए नियुक्ति की जावेगी जिसमें से प्रारंभ के दो वर्ष परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर आगे तीन वर्ष और बढ़ाए जावेंगे तथा इसके बाद का कार्य संतोषप्रद होने पर आगामी पांच वर्ष की अवधि और भी बढ़ायी जा सकती है।

(ग) 1. आवेदक को साक्षात्कार के समय अपने सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
2. वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थी को अपना आवेदन योग्य माध्यम से प्रेषित करना होगा।
3. अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी पूर्ण जानकारी स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ सचिव, श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय न्यास, तीर्थंकर भगवान महावीर मार्ग (संजीत मार्ग), मन्दसौर (म.प्र.) 458001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन से एक माह में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(घ) वेतनमान - रूपये 37,400 - 67,000/- के वेतनमान में रुपये 10,000/- ग्रेड पे तथा न्यास द्वारा समय-समय पर स्वीकृत/देय भत्तों के साथ। आरंभ में वेतन तथा ग्रेड पे और अन्य भत्ते मिलाकर कुल सकल वेतन 75000/- रुपये देय होगा।

(ङ) शासकीय विधि महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राध्यापक अथवा प्राचार्य भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन की राशि में से पेंशन की राशि घटाकर वेतन दिया जावेगा।

(च) महाविद्यालय परिसर में आवास सुविधा भी प्रदान की जावेगी।

(छ) सेवा शर्तें - यू.जी.सी. बी.सी.आई., विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों तथा श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय न्याय द्वारा निर्मित नियमावली के अनुसार होगी।

सचिव

आर-49415/2024 **श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, मन्दसौर**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 ग्वालियर

फोन नं. 0751-2371231, ईमेल : eepwd1gwl@mp.nic.in

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 45/टी.सी./डी-1 ग्वा./2023-24 **दिनांक : 15.01.2024**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु नवीन निविदा प्रपत्र 2.10 पर आमंत्रण की सूचना क्र. 41 ग्वालियर दिनांक 29.12.2023 द्वारा प्रचलित भवन/सड़क कार्यों की दर अनुसूची दिनांक 15.09.22/25.03.2022 पर निविदायें लो.नि.वि. में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार श्रेणी हेतु आमंत्रित की जाती हैं जिसका सम्पूर्ण विवरण **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। विभाग तकनीकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा एवं किन्हीं कारणों से की जाने वाली परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर ही देखें पृथक से प्रकाशित नहीं की जावेगी।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– लोक निर्माण संभाग ग्वालियर अंतर्गत बेटी बचाओ तिराहे से लोहार की पुलिया सिकंदर कम्पू लंबाई 2.20 कि.मी. फोरलेन मार्ग का निर्माण कार्य।

टेण्डर आई.डी.	(1) ठेके की अनु. लागत राशि रु. (2) अमानत राशि	टेण्डर फार्म की राशि (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	पंजीयन श्रेणी
2024_PWDRB_326584_1	1. 672.84 लाख 2. 672840/-	20000/- + (पोर्टल चार्ज)	12 माह वर्षाकाल सहित	लो.नि.वि. में पंजीकृत ठेकेदार

कुल कार्य संख्या - 01(एक)
ऑनलाइन निविदा जारी व डाउनलोड करने की आरंभ तिथि - 16.01.2024 प्रातः 10.30
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - **05.02.2024 सायं 17.30**
ऑनलाइन निविदा दर खुलने की तिथि - 07.02.2024 प्रातः 11.00

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं तथा सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री

जी-23424/49409/2024 **लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1 ग्वालियर**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग रायसेन (म.प्र.)

ईमेल :- eepwdraisen@mp.nic.in, दूरभाष/फैक्स क्रमांक :– 07482-222051

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 26/व.ले.नि./रायसेन/2023-24 **रायसेन, दिनांक : 18.01.2024**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर आई.डी.	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1.	2024_PWDRB_326094_1	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण कार्य	खरगौन से जामगढ़ मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य लंबाई 6.00 कि.मी.	द्वितीय	129.53	
2.	2024_PWDRB_327399_1	रायसेन	बी.टी. नवीनीकरण कार्य	महेश्वर से छिंद मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य। लंबाई 4.20 कि.मी.	द्वितीय	70.50	
3.	2024_PWDRB_327408_1	रायसेन	मरम्मत कार्य	पलकाश्री से गुरैला मार्ग कि.मी. 1/6 एवं 2/6 में पुलिया मरम्मत कार्य।	प्रथम	15.00	
4.	2024_PWDRB_327418_1	रायसेन	मरम्मत कार्य	कूटनासिर से शिवतला पलकाश्री मार्ग पर कि.मी. 3/4 एवं 4/8 में पुलिया मरम्मत कार्य।	प्रथम	15.00	
				योग		**230.03**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **07.02.2024, (17.30) बजे** अंतिम तिथि निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-23421/49408/2024 **लोक निर्माण विभाग, रायसेन संभाग रायसेन**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 37/मु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2023-24 **भोपाल, दिनांक : 24.01.2024**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. हरदा जिले में खिरकिया शहर के अंदर खिरकिया बरूआ एम.डी.आर. मार्ग पर एल.सी. क्रमांक-195 पर रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु
2024_PWDRB_327890_1	हरदा	पुल कार्य	तृतीय	3072.97	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. नर्मदापुरम जिले में सिवनी मालवा से शिवपुर मार्ग के इटारसी खण्डवा रेल सेक्शन पर एल.सी. क्रमांक-218 पर रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य।

2024_PWDRB_327891_1	नर्मदापुरम	पुल कार्य	तृतीय	2775.55	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. अशोकनगर जिले में मल्हारगढ़ बीना-मार्ग में बेतवा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।

2024_PWDRB_328083_1	अशोकनगर	पुल कार्य	तृतीय	2293.26	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. खरगोन जिल में कसरावद पीपलगांव मार्ग पर कि.मी. 6/10 से 7/2 में वेदा नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।

2024_PWDRB_328084_1	खरगोन	पुल कार्य	पंचम	1581.87	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. हरदा जिले के अंतर्गत बिचोला से खरदाना मार्ग में अजनाल नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।

2024_PWDRB_327892_1	हरदा	पुल कार्य	द्वितीय	1267.52	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. हरदा जिले में आदमपुर से सुरजना मार्ग में बाकुड नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।

2024_PWDRB_327894_1	हरदा	पुल कार्य	तृतीय	682.96	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 7. हरदा जिले में झुगरिया से मनोहरपुरा मार्ग में बाकुड नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।

2024_PWDRB_327895_1	हरदा	पुल कार्य	तृतीय	582.86	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 8. हरदा जिले में नीमगांव से झाडपा मार्ग पर अजनाल नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।

2024_PWDRB_327896_1	हरदा	पुल कार्य	तृतीय	582.31	केवल ऑन-लाइन
		कुल योग -		**12839.30**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 14.02.2024 (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

जी-23463/49412/2024 **लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल**

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम् मण्डल नर्मदापुरम्

Office Email ID seresnarmda@mp.gov.in, Office Phone No. 07574-250166

क्र. 85/निविदा/ग्रा.यां.से./2024 **नर्मदापुरम, दिनांक : 17.10.2024**

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 03/2023-24 (प्रथम आमंत्रण)

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से ऑनलाइन मोहरबंद प्रतिशत दर पर निविदायें फार्म ''ए'' (Appendix-2.10) पर ग्रायांसे संभाग बैतूल जिला बैतूल की म.प्र. लोक निर्माण विभाग के केंद्रीयकृत प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत सी श्रेणी ठेकेदारों से 3 कवर पद्धति में ग्रायांसे में सिविल कार्य हेतु प्रचलित एस.ओ.आर. दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर अनुसूची एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रचलित एस.ओ.आर. दिनांक 11.11.2022 से प्रभावशील (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) दर के आधार पर अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम मंडल नर्मदापुरम के कार्यालय में ऑनलइन आमंत्रित की जाती है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. आजीविका प्लाजा निर्माण कार्य बैतूल जिला बैतूल, (विद्युतीकरण कार्य सहित)

सिस्टम टेण्डर नं.	निविदा की अनु. लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि (रुपये में)	कार्य अवधि वर्षाकाल सहित (माह में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
2024_RES_326585	32708188/-	327082/-	12 माह	15000/-
योग -	**32708188/-**	**शब्दों में तीन करोड़ सत्ताईस लाख आठ हजार एक सौ अठासी रुपए मात्र।**		

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रण की निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैं :–

क्र.	विवरण	तिथि	समय
1.	निविदा ऑनलाइन प्रकाशित होने की तिथि	27.01.2024	17.30
2.	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की प्रारंभिक तिथि	29.01.2024	17.30
3.	ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	29.01.2024	17.30
4.	ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**12.02.2024**	13.30
5.	ऑनलाइन निविदा खुलने की तिथि	15.02.2024	13.30

निविदा प्रपत्र (Tender Document) वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन प्रकाशित एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किए जाएंगे। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

अधीक्षण यंत्री

जी-23405/49407/2024 **ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम मण्डल नर्मदापुरम**

गरीब और पिछड़े समुदायों का उत्थान करने वाले प्रयासों में संवेदनशीलता जरूरी

भोपाल, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की डिजाइन और सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सहयोग किया जाना चाहिए। आवास में प्रकाश, हवा और स्वच्छता की व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए। योजना के तहत आवास निर्माण में सबसे गरीब परिवार को प्राथमिकता दी जाये। प्रथम किश्त प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के आवास बरसात से पहले पूरे हो जायें, इसमें भी सहयोग किया जाना चाहिए। ये बातें राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने भोपाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन और जनजातीय कार्य विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य समाज के वंचित और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले गरीब और पिछड़े समुदायों का उत्थान है। इन वर्गों का योजनाओं के माध्यम से विकास हो, उनका जीवन बेहतर बने। बैठक में बताया गया कि पेसा नियम के क्रियान्वयन के संबंध में 20 जिलों में 11 हजार 595 ग्राम सभाओं के 13 हजार 753 फलियों, मजरों, टोलों एवं बसाहटों तक प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश के 18 चिन्हित जिलों के विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 198 वन-धन केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य की तुलना में 201 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से बेहतर

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नई शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में तो अग्रणी रहा ही है, नामांकन के स्तर पर भी प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। सकल पंजीयन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय औसत 28.4 प्रतिशत रहा जबकि मध्यप्रदेश 28.9 प्रतिशत के साथ विद्यार्थी नामांकन संख्या में वृद्धि की उपलब्धि अर्जित कर चुका है। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं। मध्यप्रदेश ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा। प्रदेश ने इस दिशा में निरंतर प्रगति की। कोविड की चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मध्यप्रदेश में 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं का ग्रास एनरॉलमेंट रेशो (जीईआर) 28.9 है। यह राष्ट्रीय औसत 28.4 से अधिक है। उच्च शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा, विधि, पशु चिकित्सा शिक्षा और कृषि शिक्षा से जुड़े संस्थानों की सक्रियता से यह संभव हुआ। ए.आई.सी.टी.ई. से संचालित समस्त संस्थानों और एम.सी.आई. द्वारा संचालित संस्थाओं का भी सहयोग रहा। इस संबंध में निरंतर प्रयास किए गए। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय सहित 54 नए महाविद्यालय खुले।

स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज के निर्माण से बनेगा आत्मनिर्भर भारत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जबलपुर में सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए

जबलपुर, स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकेगा। जबलपुर मध्यप्रदेश का ग्रोथ इंजन है। यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम पूरे देश में जाना जाता है। जबलपुर में सड़कों-पुलों के निर्माण और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के लिये सरकार कार्य कर रही है। ये बातें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

श्री गडकरी ने कहा कि सड़कों के निर्माण से उद्योगों का विकास होता है। पर्यटन में वृद्धि होती है। कृषि एक्सपोर्ट बढ़ता है और इस तरह सड़क प्रदेश के विकास की धुरी बन जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का विजन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का ध्येय गांव और किसानों के विकास से सीधा जुड़ा है।

श्री गडकरी ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और रिंग रोड निर्माण के दौरान जमीन से खोदी गई मिट्टी की जगह पर पानी का स्टोरेज टैंक और तालाब बनाया जा सकता है। इससे वाटर कंजर्वेशन तो होगा साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा।

श्री गडकरी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन, बायो एविएशन फ्यूल, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी निर्माण की दिशा में कार्य करके अन्नदाता से आगे बढ़कर ऊर्जा दाता बन सकता है। कृषि से उपजे बायोमास को एनर्जी क्रॉप्स में परिवर्तित करें।

प्रदेश की सड़कें दुनिया में बढ़ा रहीं देश का मान - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की सड़कें देश का मान दुनिया में बढ़ा रही हैं। पहले प्रदेश में सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे लेकिन अब देश और प्रदेश की सड़कें सुगम और त्वरित परिवहन का नया अध्याय लिख रही हैं। वर्ष 2013-14 तक देश में केवल एक हजार किलोमीटर के लगभग सड़कें थीं। जो 10 साल में बढ़कर 1 लाख 61 हजार किलोमीटर तक निर्मित की गई हैं। प्रतिदिन 11.6 किलोमीटर सड़क निर्माण की गति अब बढ़कर 29.6 किलोमीटर हो गई है। इसकी गति किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरी दुनिया भारत के विकास की गति से हतप्रभ है।

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी को मिला पुरस्कार

भोपाल, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री रघुराज राजेन्द्रन और मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनजीत सिंह ने वर्ष 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स के लिए सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी को 3 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए वर्ष 2022-23 का पुरस्कार संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर के विद्युत गृह क्रमांक तीन को दिया गया। पुरस्कार के रूप में बिरसिंगपुर के विद्युत गृह क्रमांक तीन को 2 लाख रुपये प्रदान किए गए। वर्ष 2022-23 में जल विद्युत गृहों में मरहीखेड़ा जल विद्युत गृह शिवपुरी को सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए 1 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।

सेडमैप द्वारा उद्यमिता पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण

भोपाल, उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) द्वारा ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) पोर्टल सह एंड्रॉइड एप का निर्माण किया गया है। जो ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ प्रमाण पत्र देगा।

सेडमैप स्किल्स डॉट इन (cedmap skills.in) एप को डाउनलोड कर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक विषय पर जानकारी के साथ हर वीडियो के अंत में प्रश्नोत्तरी अंक भी रखे गए हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट पेपर देना होता है। एक टेस्ट पेपर पास करने के उपरांत अगले मॉड्यूल पर जा सकते हैं और अंत में प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डीआईसी) अंतर्गत संचालित शासकीय स्वरोज़गार योजनाओं की सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडीपी सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। इसके लिये 24 घण्टे के ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद डाउनलोड किया गया प्रमाण पत्र भी मान्य है।

सेडमैप द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सामग्री का निर्माण कर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऑनलाइन लाइव कक्षाओं के द्वारा भी अधिकाधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की योजना को साकार किया जा रहा है। ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पोर्टल सह एंड्रॉइड एप के निर्माण से अधिक से अधिक युवा लाभान्वित होंगे।

ईडीपी एक व्यापक कार्यक्रम है जो इच्छुक और छोटे व्यवसाय उद्यमियों के लिए व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और मौजूदा व्यावसायिक इकाइयों के विकास के साथ क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। पाठ्यक्रम में पठन सामग्री, वीडियो आधारित ट्यूटोरियल, मूल्यांकन और लाभार्थी को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए अपने व्यावसायिक विचार को परिपक्व करने में सहायता करने के लिए केस आधारित दृष्टिकोण भी पाठ्यक्रम में प्रदान किया जाता है।

विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करती है संस्कृत

रीवा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में संस्कृत भारती द्वारा जनपद संस्कृत सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा है कि देवभाषा संस्कृत को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करती है।

श्री शुक्ल ने कहा कि संस्कृत भाषा को पुनः जनमानस में स्थापित कर व्यवहार भाषा बनाने के लिए संकल्पित संस्कृत भारती की सक्रियता सराहनीय है। संस्कृत भारती से जुड़े विद्वानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी संस्कृत भाषा को स्थापित रखा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में चार संकायों में विद्यार्थियों ने प्रवेश लेकर अध्ययन शुरू कर दिया है।

राजस्व विभाग

समय-सीमा में होगा प्रकरणों का निराकरण

ग्वालियर, नामांकन, सीमांकन एवं बंटवारा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर करें। निराकरण के लिए पटवारी के साथ नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम भी गांव-गांव पहुंचें। गांव में आम आदमी के द्वार पर बैठकर किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करें। यह निर्देश राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने ग्वालियर में हुई संभागीय समीक्षा बैठक में दिये। मंत्री श्री वर्मा ने राजस्व महाअभियान एवं राजस्व विभाग की गतिविधियों की समीक्षा भी की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि रजिस्ट्री होने के 30 दिन के भीतर किसी तहसीलदार-नायब तहसीलदार ने नामांतरण नहीं किया तो वह अपने आप को निलंबित समझे।

राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि प्रदेश के किसी भी किसान को राजस्व संबंधी समस्या

राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ग्वालियर में विभागीय बैठक को संबोधित करते हुए

के लिये भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नामांतरण एवं नामांकन व बंटवारा के प्रकरणों में अधिकतम समय-सीमा का इंतजार न करें। सभी राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच एवं किसानों की मदद के भाव के साथ जल्द से जल्द प्रकरणों का निराकरण करें, जिससे आम आदमी का विभाग के प्रति विश्वास और आप सबके प्रति सम्मान बढ़े। उन्होंने कहा सीमांकन प्रकरणों का निराकरण सभी पक्षों की मौजूदगी में करें, जिससे आगे कोई विवाद की स्थिति न रहे। श्री वर्मा ने राजस्व महाअभियान के दौरान राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को दुरुस्त (नक्शे पर तरमीम) और प्रमुखता के साथ बी-1 का वाचन करने पर विशेष बल दिया। श्री वर्मा ने बैठक में कहा कि शहरी क्षेत्र में एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय से पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण किया जायेगा।

आयुक्त भू-अभिलेख श्री विवेक पोरवाल ने राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश संभाग के सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में महाअभियान में प्रगति कम है, वहां विशेष मुहिम चलायें।

प्रदेश में श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये सांकेतिक भाषा की सुविधा

भोपाल, मध्यप्रदेश में श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुविधा के लिये आधारभूत कौशल कोर्स तैयार किया गया है। यह कोर्स 30 से 40 घंटे का भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र ने ऑनलाइन तैयार किया है।

श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को यह कोर्स प्रशिक्षण केन्द्र की वेबसाइट www.islrtc.nic.in पर, यू-ट्यूब चैनल की लिंक पर तथा क्यू-आर कोड से डाउनलोड किया जा सकता है। जिला शिक्षा, जनपद और जनशिक्षा केन्द्रों के माध्यम से सभी स्कूलों में यह कोर्स बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे उन्हें अध्ययन में सुविधा हो सके। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला परियोजना समन्वयक राज्य शिक्षा केन्द्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 5 व 8 के दृष्टिबाधित छात्रों के लिये गणित विषय के स्थान पर संगीत विषय का विकल्प चयन करने का प्रावधान है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने परीक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा में तृतीय भाषा के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं। तृतीय भाषा अशासकीय शालाओं में मांग के अनुसार पंजाबी, गुजराती, उड़िया और संस्कृत है।

कक्षा 8 में तृतीय भाषा के रूप में पंजाबी, गुजराती और उड़िया भाषा एवं राजगढ़ तथा बुरहानपुर जिलों के अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 5 में शालाओं की मांग के क्रम में अतिरिक्त भाषा के रूप में संस्कृत विषय का बच्चों को अध्ययन कराया गया है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

उद्योगविहीन इलाकों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर करें फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में जनसंपर्क विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए

भोपाल, मध्यप्रदेश के ऐसे इलाके जहां अपेक्षाकृत उद्योग कम हैं, वहां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर फोकस किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर उद्योग संवर्धन संगोष्ठियां करके उद्योगपतियों एवं निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने नर्मदा घाटी विकास की विभागीय समीक्षा करते हुए जल उपयोग के मामले में श्रेष्ठ परिणाम लाने वाले राज्यों विशेषकर गुजरात में हुए कार्यों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान सिंचाई प्रतिशत, सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों, आगामी वर्षों में सिंचाई प्रतिशत में वृद्धि के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों, किसानों के लिए सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से जल उपलब्ध करवाने, विभिन्न बांधों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन, जलाशयों और बांधों की उपलब्ध जल क्षमता और उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे स्थानों पर उद्योग स्थापना की ठोस पहल की जाए, जहां उद्योग कम हैं। उन्होंने धार, झाबुआ जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्रों एवं सागर, जबलपुर जैसे नगरीय क्षेत्रों में उद्योग संवर्धन संगोष्ठियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए।

डॉ. यादव ने कहा कि अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। इसके लिए संभागीय टास्क फोर्स का उपयोग किया जाए। खनिजों से राजस्व प्राप्ति के संबंध में विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाए।

इवेंट आधारित गतिविधियों की रूपरेखा बनाए जनसंपर्क विभाग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसंपर्क विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे प्रचार कार्य के साथ ही विषय केन्द्रित और इवेंट आधारित गतिविधियों की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जनसंपर्क आयुक्त श्री संदीप यादव ने विभाग के कार्यों की जानकारी दी। प्रकाशन, पत्रकार कल्याण, विभागीय प्रशिक्षण, मीडिया प्रशिक्षण गतिविधियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रकाशन की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के साथ ई-प्रकाशन के भी निर्देश दिए। उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रोत्साहन और पुरस्कार योजना प्रारंभ करने और राज्यों में अध्ययन दल भेजकर नवाचारों को अपनाने के लिए कहा।

शिक्षा के पाठ्यक्रमों में मानवीय मूल्यों का समावेशन जरूरी - राज्यपाल

भोपाल, विश्वविद्यालय श्रेष्ठ मानव का विकास करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ज्ञान के विस्तार के साथ ही श्रेष्ठ मानव तैयार करना है। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि वे उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को ज्ञान, विज्ञान के साथ ही नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक परम्पराओं, संस्कारों और व्यवहारिक जीवन के गुणों को भी रोपित करें। ये बातें राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 101वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में मानवीय मूल्यों का समावेशन जरूरी है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य समर्पित, संवेदनशील और कर्मठ नागरिक बनाना है। यह समझना जरूरी है कि मात्र ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विकास समग्र शिक्षा नहीं है। विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता, पर्यावरणीय चेतना और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक सरोकारों के प्रति सजगता और सक्रियता का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि विद्यार्थियों को हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परम्पराओं और विरासत के संस्कारों से दीक्षित करें ताकि विद्यार्थी भावी जीवन में हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रह कर, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करे।

श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सामान्यतः विद्यार्थी 4 से 5 वर्ष अध्ययन करते हैं। इस अवधि में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

विक्रम व्यापार मेला, इन्वेस्टर्स समिट और विक्रमोत्सव एक मार्च को उज्जैन में होगा

उज्जैन, उज्जैन जिले में एक मार्च को विक्रम व्यापार मेला, इन्वेस्टर्स समिट एवं विक्रमोत्सव का आयोजन किया जायेगा। उज्जैन में इन आयोजनों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री पी. नरहरि ने समीक्षा तैयारियों की जानकारी ली।

विक्रमोत्सव, व्यापार मेला एवं इन्वेस्टर्स समिट में प्रस्तावित गतिविधियों की सूची बनाई जा रही है। इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित उद्योगपतियों और उनकी उद्योग इकाइयों की जानकारी अपडेट की जा रही है। इन्वेस्टर्स का फोकस विशेष तौर पर उज्जैन होगा। आयोजन का एक पार्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा। उज्जैन एवं मालवा की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जायेगी। मालवा का फूड एवं अन्य विशेषताएं प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेंगी। सभी सम्बन्धित विभागों को तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिये।

एमपीआईडीसी के एमडी श्री नवनीत कोठारी ने इन्वेस्टर्स समिट के लिये चयनित स्थान, बैठक की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिये।

आयुष्मान भारत के क्लेम को समय से उपलब्ध करायें - उप मुख्यमंत्री

भोपाल, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिये हैं कि आयुष्मान भारत योजना के मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के क्लेम का प्राथमिकता से भुगतान सुनिश्चित करें। क्लेम में दोनों घटक दवा और चिकित्सकों की प्रोत्साहन राशि दोनों का भुगतान किया जाये। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के क्लेम और प्रोत्साहन राशि के भुगतान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। श्री शुक्ल ने आयुष्मान भारत योजना के क्लेम, कुल मांग, विभाग ने प्रतिपूर्ति की गयी राशि और उसकी उपयोगिता की समीक्षा की।

मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में लगेंगे वन मेले - वन मंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में वन मेलों का आयोजन होगा। वन मेले में 50 हजार से अधिक लोगों ने भागीदारी की और सिर्फ चार दिनों में ही हर्बल उत्पादों की बिक्री लगभग 60 लाख तक पहुंच गई। मेले में जानकार वैद्यों द्वारा लगभग 10 हजार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ये बातें वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने भोपाल में वन मेला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।

वन मंत्री ने कहा कि मेले के माध्यम से लोगों को जड़ी-बूटियों की जो जानकारियां प्राप्त हुईं उससे आयुर्वेद अपनाने के प्रति रुझान बढ़ेगा। साथ ही जनजातीय परिवारों को जीविका चलाने के लिये सतत अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय, उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि दूर अंचलों के वनों से जड़ी-बूटियां संग्रहित करने वाले जनजातीय परिवारों को कठिन मेहनत करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा जड़ी-बूटियों का परीक्षण और प्रसंस्करण कर औषधियां बनाई जाती हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये लाभकारी होती हैं।

वन, पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि वन मेले में आये आदिवासी संग्राहकों को पहचान मिलती है और उन्हें वनौषधि विक्रय के लिये एक मंच उपलब्ध होता है।

श्री अहिरवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में गरीबों के कल्याण का जो सपना है, वह ऐसे मेलों से मूर्त रूप लेता है। उन्होंने कहा कि स्टॉलों में कलाकृतियों और चित्रकला को देखकर मन प्रसन्न हो गया। श्री अहिरवार ने कहा कि महत्वपूर्ण आयोजनों से प्रदेश विकास के नये रास्ते तय करेगा और सफलता के शीर्ष तक पहुंचेगा।

वन मेला समापन समारोह में वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये, जिनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी सर्वश्रेष्ठ विक्रेता एवं सर्वश्रेष्ठ सजावट थे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी में एमएफपी पीएआरसी, सोशल फॉरेस्ट्री एवं बायोडायवर्सिटी बोर्ड को पुरस्कार दिया गया।

सर्वश्रेष्ठ विक्रेता में जिला यूनियन सतना एवं बीडीवीके उत्तर सिवनी को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ सजावट में जिला यूनियन सीहोर एवं बीडीवीके अलीराजपुर को पुरस्कृत किया गया।

विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के लिए लगायें शिविर

भोपाल, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों का चिन्हांकन करने के लिये शिविर लगाये जायें। ये निर्देश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने भोपाल में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए।

श्रीमती गौर ने कहा कि विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जातियों के कल्याण के लिये योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है कि प्रदेश में निवासरत विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जातियों का चिन्हांकन किया जाये।

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं प्राचीन पुस्तकें

भोपाल, मध्यप्रदेश में संस्कृत भाषा के विस्तार के लिये स्कूल शिक्षा विभाग के अतंर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान लगातार प्रयास कर रहा है। संस्थान संस्कृत भाषा के अनुसंधान के लिये भी शोधार्थियों को हर संभव मदद दे रहा है। संस्थान में समेकित वेबसाइट https://www.mpssbhopal.org शुरू की गई है।

संस्थान की वेबसाइट पर संस्कृत की 538 प्राचीन पुस्तकें, प्रश्न बैंक और पाठ्यक्रम सामग्री अपलोड की गई है। इसके साथ ही कक्षा एक की पाठ्यपुस्तकें एवं नवीन पाठ्यक्रम अनुसार गुजरात राज्य शाला पाठ्य-पुस्तक मंडलम से प्राप्त कक्षा 9वीं से 12वीं तक की प्राच्य संस्कृत विषयों की 22 पाठ्यपुस्तकें वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की 3 संदर्भ पुस्तकों का प्रायोगिक संस्करण पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराया गया है।

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का नवीन भवन भोपाल के तुलसी नगर में 10 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही बालक आवासीय माध्यमिक संस्कृत विद्यालय डिंडोरी के भवन का रिनोवेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। विद्यालय में कक्षा 6 से ऊपर की पढ़ाई संस्कृत माध्यम में कराई जा रही है। रतलाम जिले के ग्राम सोहनगढ़ में करीब 3 हेक्टेयर भूमि विद्यालय के लिये प्राप्त की जा चुकी है। इसके साथ ही टीकमगढ़ में लगभग 3 हेक्टेयर भूमि संस्कृत विद्यालय भवन के निर्माण के लिये आरक्षित की जा चुकी है। प्रदेश का पहला शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय भोपाल में संचालित हो रहा है।

संरक्षित खेती

नई तकनीक से फसल उत्पादन होगा दोगुना

भोपाल, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि किसान संरक्षित खेती की नवीन तकनीक के इस्तेमाल से फसल उत्पादन को दोगुना कर सकते हैं। किसान समृद्ध होगा, तभी देश और प्रदेश समृद्ध बनेगा। मध्यप्रदेश में गत वर्षों में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में इनका उत्पादन साढ़े चार लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 390 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। ये बातें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने भोपाल में राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 'संरक्षित खेती की तकनीकी और फसल प्रबंधन' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर कहीं।

श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं और मार्गदर्शी कार्यक्रमों का संचालन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब शिक्षित युवाओं द्वारा भी कृषि को रोज़गार के रूप में अपनाना प्रारंभ किया गया है। युवा किसान फसल की बोनी से पूर्व मिट्टी के परीक्षण, मिट्टी की मांग के अनुसार उर्वरकों का उपयोग और पॉली हाउस जैसे संरक्षित फसल तकनीक से अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। संरक्षित खेती की नवीन तकनीक को और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। किसान शासन की अनुदान व प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने हॉर्टिकल्चर के साथ-साथ फ्लोरीकल्चर को भी अपनाने की सलाह किसानों को दी।

उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

चंबल क्षेत्र में उद्योगों के माध्यम से रोज़गार देना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना में संभागीय बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए

मुरैना, जरूरतमंदों को रोज़गार देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर में रोज़गार देने की कार्ययोजना बनाई जाए। चंबल संभाग असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। यहां रोज़गार और विकास के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जायेगा। कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता और सूक्ष्म, लघु उद्योग विभाग कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कार्ययोजना में हर सेक्टर से जरूरतमंदों को रोज़गार मिले, इसकी जिलेवार तैयारी करें। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना में आयोजित हुई संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबल-मुरैना क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां ऐतिहासिक इमारतें, जलाशय एवं अकूत वन संपदा उपलब्ध है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये रोज़गारपरक योजना तैयार करें। जिले से लेकर संभाग तक ऐसी बैठकें निरंतर की जायेंगी।

डॉ. यादव ने कहा कि हर जिले में ऐसे सक्षम लोग मौजूद हैं, जो थोड़े से प्रोत्साहन और सरकारी मदद से उद्यम स्थापित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीक बसे गांवों को नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी अनिवार्यतः मिले। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन हैं, वहां विशेष ध्यान देकर संबंधित ग्रामों को मुख्य सड़क मार्ग से जुड़वाएं। राजधानी दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों से निकट होने के कारण क्षेत्र में उद्योगों की असीम संभावना हैं, इसके लिये बड़े उद्योग, कपड़ा क्लस्टर, फर्नीचर, ग्रामोद्योग और खाद्य प्रंसस्करण उद्योगों को बढ़ावा देंगे। बड़े उद्योग समूह को बुलाकर औद्यौगिकीकरण के लिये काम हों। चंबल संभाग में पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। डॉ. यादव ने कहा कि कैलारस शक्कर कारखाने पर किसानों की बकाया राशि का भुगतान कराया जाएगा। लगभग 54 करोड़ की शेष राशि का भुगतान कार्ययोजना बनाकर किया जायेगा। इसके साथ ही लघु और सूक्ष्म उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग के साथ रोज़गारोन्मुख उद्योग लगाने के लिए कार्ययोजना बनाएगा।

सोलर परियोजना के निर्माण की बढ़ाएं गति

विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बैठक में पार्वती-कालीसिंध लिंक परियोजना के लिये चम्बल संभाग की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सोलर परियोजना के निर्माण की गति बढ़ाई जाये। भू-तल परिवहन मंत्री के साथ चर्चा हुई। नैनागढ़ से अम्बाह तक एलिवेटेड रोड की घोषणा अनुरूप प्रस्ताव मंजूरी के लिये केन्द्र सरकार को बनाकर भेजना है। श्योपुर में लिफ्ट सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इसको अन्य विभागों के साथ मिलकर शुरू करना है। आलू रिसर्च केन्द्र के लिये पेरू के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाई है। मुरैना जिले को इसमें जोड़ा गया है। श्योपुर में गिर गाय के संवर्धन अनुसंधान केन्द्र और परियोजना पर कार्य किया जाना है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है - मुख्यमंत्री

मुरैना, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अहमदाबाद-ग्वालियर हवाई सेवा से ग्वालियर गुजरात से व्यापारिक रिश्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। उड्डयन के क्षेत्र में देश को नई गति मिली है। बेंगलुरु के बाद अहमदाबाद के लिए मिली हवाई सुविधा प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अकासा एयर फ्लाइट की ग्वालियर-अहमदाबाद विमान सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम को मुरैना से वर्चुअली संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 26 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 22 राज्य शासन की तथा 4 निजी क्षेत्र की हैं। हमारा प्रयास है कि संभाग स्तर के बाद सभी जिलों में भी हवाई पट्टियां हों। इस दिशा में हम केन्द्र सरकार के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। दतिया और रीवा में हवाई अड्डा विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। इसके साथ ही उज्जैन में केन्द्र शासन के सहयोग से एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने एवं प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में पर्यटन को विकसित करने में भी हवाई सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सहजता, कर्मठता और प्रगति तथा विकास के प्रति उनकी संकल्पबद्धता से मध्यप्रदेश में नया दौर आरंभ हुआ है। प्रधानमंत्री की हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा के अनुरूप देश में आम आदमी को हवाई यात्रा सुविधा का लाभ देने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर अब देश के सात प्रमुख शहरों क्रमशः बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, मुम्बई और अयोध्या से हवाई मार्ग से जुड़ा है।

स्कूल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये 2.50 लाख साइकिलें वितरित

भोपाल, मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये पिछले वर्ष चयनित विद्यार्थियों को 2 लाख 50 हजार साइकिलें नि:शुल्क वितरित की हैं। ग्रामीण क्षेत्र के चयनित उन विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की गई हैं, जिनके ग्राम में शासकीय हाईस्कूल संचालित नहीं होता है।

इस योजना का लाभ इन विद्यार्थियों को कक्षा-6वीं अथवा 9वीं में प्रवेश लेने पर एक ही बार दिया जा रहा है। योजना का लाभ उन छात्राओं को भी दिया जा रहा है, जो कन्या छात्रावास में अध्ययनरत हैं और उन्हें छात्रावास से 2 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर अध्ययन करने के लिये शासकीय शाला जाना पड़ रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि प्रदेश के सीएम राइज़ विद्यालयों से जिन शिक्षकों के स्थानांतरण दिसम्बर-2023 एवं जनवरी-2024 में ऑनलाइन जारी किये गये हैं, उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये।

श्रम कानूनों का होगा प्रभावी क्रियान्वयन

इंदौर, मध्यप्रदेश में श्रमिकों के हितों की चिंता की जाये। उनके कल्याण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। श्रमिकों के कल्याण के लिये संवेदनशील होकर सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्य करें। प्रदेश में श्रम कानूनों तथा अधिनियमों का प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जाये। श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक रूप से जन-जागरूकता लायी जाये, जिससे कि सभी पात्र श्रमिकों तक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सरलता से पहुंच सके। ये बातें श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने इंदौर में श्रमायुक्त कार्यालय के निरीक्षण के पश्चात आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कहीं।

देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में सभी सहभागिता करें

सतना, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने सतना में आयोजित रोज़गार दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कार्यक्रम में 17 हजार 580 हितग्राहियों को स्व-रोज़गार के लिये 66 करोड़ रुपये की ऋण राशि के चैक वितरित किये।

श्रीमती बागरी ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये प्रोत्साहित करें। महिलाएं घर पर रहकर ही स्व-सहायता समूह में सक्रिय भागीदारी से आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन सकती हैं। समूह की महिलाएं ऋण लेकर उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित कर अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकती हैं।

श्रीमती बागरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में सभी सक्रियतापूर्वक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

सहकारिता आंदोलन को बनाया जायेगा मजबूत

इंदौर, सहकारिता आंदोलन समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। समाज, परिवार, प्रदेश और देश समन्वय और परस्पर सहयोग के बगैर नहीं चल सकते हैं। सहकारिता की समाज में अहम भूमिका है। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। रोज़गार के नए अवसर सृजित किये जायेंगे। ये बातें सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने इंदौर में सहकारिता और इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक में कहीं।

श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उसे विस्तारित करने के लिये सहकारिता विभाग अब नए कलेवर और सोच के साथ कार्य करेगा। इसके लिये बहुवर्षीय रोडमैप बनाकर सहकारिता आंदोलन में नई तकनीक को शामिल करते हुए प्रक्रिया सुधार के कार्य किये जायेंगे।

सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग संभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए

सहकारिता मंत्री ने कहा कि अधिकारी विभाग में नवाचार करते हुए नई सोच, पारदर्शिता एवं पूर्ण ईमानदारी से निष्ठावान होकर कार्य करें। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें। को-ऑपरेटिव बैंकों को प्रायवेट बैंकों के अनुरूप बनायें।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश के
शहडोल, गुना, झाबुआ, खंडवा, कटनी,
छतरपुर, पिपरिया, बैतूल, सागर,
विदिशा एवं इटारसी में
एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालीन समय में संपर्क करें

0755-2760006,
0755-2551330

प्रमुख आकर्षण

- कॅरियर की खबरें
- सम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय खबरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें
प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयनित

संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल,

उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2024 के लिए चुना गया है। 1942 में स्थापित यह हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। इसने उत्तराखंड बाढ़ (2013), ऑपरेशन 'मैत्री' (2015) के तहत नेपाल भूकंप और इंडोनेशियाई सुनामी के दौरान ऑपरेशन समुद्र मैत्री (2018) और फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान की थी।

अभ्यास 'खंजर'

हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ

भारत और किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल

अभ्यास खंजर 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना के दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के सैनिकों द्वारा और किर्गिस्तान दल का प्रतिनिधित्व स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया गया।

श्री नीतीश कुमार

रिकॉर्ड नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने

जनता दल-यूनाइटेड के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार ने

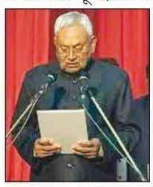

रिकॉर्ड नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में श्री नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

श्री रंजन गोगोई

असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित होंगे

पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई को असम

के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'असम वैभव' से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले वह पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति हैं। वे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। वहीं तैराक एल्विस अली हजारिका, धाविका हिमा दास, सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन विशेषज्ञ किशन चंद नौरियाल और तिवा नर्तक नंदीराम देउरी सहित 17 लोगों को 'असम सौरव' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

अभ्यास 'सदा तनसीक'

भारत और सऊदी अरब के बीच शुरू हुआ

भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सदा

तनसीक' राजस्थान के महाजन में शुरू हुआ। यह अभ्यास 29 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी 2024 तक चलेगा। अभ्यास में सऊदी अरब के सैन्य दल का नेतृत्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य अर्ध-रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना है।

फिल्म 'टू किल अ टाइगर'

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नामित

ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए फिल्म 'टू किल अ टाइगर' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को निशा पाहुजा ने डायरेक्ट किया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड के एक बाप-बेटी की सच्ची कहानी है। यह फिल्म एक किसान पिता के न्याय की लड़ाई को दिखाती है, जो अपनी 13 साल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है। फिल्म में बेटी के दुष्कर्मियों को सजा दिलाने से कहीं अधिक यह लड़ाई बेटी का साथ देने की है।

डॉ. ऋतु और उद्यमी नवीन तिवारी

उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित

उत्तर प्रदेश सरकार ने वैज्ञानिक डॉ. ऋतु करिधल और उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। डॉ. ऋतु ने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह इस मिशन की उप संचालन निदेशक थीं। वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी रही हैं। वहीं नवीन ने मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म से जोड़ता है।

जीएम कादिर

बांग्लादेश संसद में बने विपक्ष के नेता

बांग्लादेश के नवनिर्वाचित संसदीय अध्यक्ष डॉ. शिरीन

शर्मिन चौधरी ने जातीय पार्टी के अध्यक्ष जीएम कादिर को विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार किया। संसद सचिवालय के अनुसार अध्यक्ष डॉ. शिरीन शर्मिन चौधरी ने जातीय पार्टी के अध्यक्ष और रंगपुर-3 निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक जीएम कादिर को 12वीं जातीय संसद में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है।

चिल्का पक्षी महोत्सव

ओडिशा में हुआ आयोजित

ओडिशा में चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का

आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने किया। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कई प्रजातियों के दस लाख से अधिक पक्षी यहां पहुंचते हैं। उद्घाटन समारोह में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स का पोस्टर और वीडियो लॉन्च किया गया। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स वीडियो में उस वैज्ञानिक रिपोर्ट को शामिल किया गया है, जो भारत के पक्षियों का आकलन करती है।

एआई स्टार्टअप कृत्रिम

देश का पहला AI यूनिकॉर्न बना

ओला के फाउंडर और चेयरमैन भाविश अग्रवाल की

एआई स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम देश की पहली AI यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल 'कृत्रिम' को भाविश अग्रवाल ने 15 दिसंबर, 2023 को लॉन्च किया था। 'कृत्रिम' को 22 भारतीय भाषाओं की समझ है। यह एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम वाला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। कंपनी 'कृत्रिम' के लिए डेटा सेंटर भी डेवलप कर रही है।

श्री हिमंत बिस्व सरमा

असम का राजनीतिक इतिहास पुस्तक का पहला खंड जारी किया

असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्व सरमा ने असम

का राजनीतिक इतिहास पुस्तक का पहला खंड जारी किया। इस पुस्तक को इतिहासकार राजेन सैकिया द्वारा संपादित किया गया है। यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1971 तक असम के राजनीतिक इतिहास को कवर करती है। यह पुस्तक असम के सामाजिक और आर्थिक जीवन को आकार देने वाली घटनाओं से परिचित कराएगी।

दलीप सिंह

विरासत के लिए दो लाख पाउंड का अनुदान

ब्रिटेन के एक संग्रहालय को नेशनल लॉटरी हेरिटेज फंड

की ओर से लगभग 2 लाख पाउंड का अनुदान दिया गया है। यह अनुदान सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह की विरासत को चिह्नित करने के लिए दिया गया है। नॉरफॉक के थेटफोर्ड में प्राचीन हाउस संग्रहालय को उसकी 100वीं वर्षगांठ पर यह धनराशि प्रदान की गई। संग्रहालय दलीप सिंह के आकर्षक इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए परियोजना शुरू कर रहा है।

कार्टर डलास

2 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचा

स्कॉटलैंड में रहने वाला 2 साल का कार्टर डलास माउंट

एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया। पहले यह रिकॉर्ड चेक रिपब्लिक के एक चार साल के बच्चे के नाम था। कार्टर ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का सफर मां जेड और पिता रॉस की पीठ पर बैठकर पूरा किया। स्कॉटलैंड के रहने वाले रॉस और जेड अपने बेटे के साथ एक साल के लिए एशिया की यात्रा पर निकले हुए हैं।

तुर्किये ने

स्वीडन की नाटो सदस्यता को दी मंजूरी

तुर्किये ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में

मतदान किया। स्वीडन के प्रति नाटो का समर्थन आधिकारिक राजपत्र प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होगा। तुर्किये के समर्थन के बाद हंगरी अब एकमात्र नाटो सदस्य देश बन गया है, जिसने स्वीडन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। नाटो सदस्य तुर्किये एक साल से अधिक समय से स्वीडन की सदस्यता में देरी कर रहा था। उसने स्वीडन पर उन समूहों के प्रति बहुत उदार होने का आरोप लगाया था, जिन्हें अंकारा सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।

नवाज शरीफ की रैली में

असली टाइगर लेकर पहुंचा समर्थक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की रैली में

एक समर्थक असली टाइगर लेकर पहुंच गया। शेर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इलेक्शन सिम्बल भी है। जैसे ही नवाज को रैली में समर्थक के टाइगर लाने की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन इसे वापस भेजने को कहा। रैली में लाया गया टाइगर लोहे के पिंजरे में कैद था। लेकिन, इसको देखने के लिए भीड़ जुटने लगी।

श्री कर्पूरी ठाकुर को

मरणोपरांत मिलेगा भारत रत्न

भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी

ठाकुर को मरणोपरांत 'भारत रत्न' देने की घोषणा की है। जननायक के रूप में मशहूर श्री ठाकुर दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका 17 फरवरी 1988 को निधन हो गया था। श्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों, दलितों, गरीबों और किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और लंबे समय तक संघर्ष किया।

अमेरिका

दो शासकीय स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का फैसला

अमेरिकी स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में पढ़ाने

का फैसला लिया गया है। फ्रेमोंट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हिंदी की पढ़ाई के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। कैलिफोर्निया के दो सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई पर अहम फैसला हुआ है। अगस्त में शुरू होने वाले 2024-25 सत्र में हॉर्नर मिडिल स्कूल और इरविंगटन हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल किया जाएगा।

इमरान खान और महमूद को

कोर्ट ने सुनाई 10 साल जेल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के लीडर शाह महमूद कुरैशी को सायफर केस में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया। पिछले साल से केस की सुनवाई अदियाला जेल में चल रही है। कुरैशी और इमरान से धारा 342 के तहत सवाल पूछे गए थे।

स्मृति शेष

श्रीलंका के राज्यमंत्री शनत निशंता का सड़क हादसे में निधन

श्रीलंका के राज्य मंत्री शनत निशंता का एक सड़क

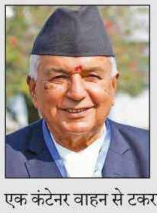

हादसे में निधन हो गया। यह घटना कटुनायके एक्सप्रेस-वे के पास हुई। जीप में राज्य मंत्री निशंता के साथ सुरक्षा अधिकारी और चालक सवार थे। उनकी जीप एक कंटेनर वाहन से टकराने के बाद सड़क की बाड़ से टकरा गई। वह कटुनायके से कोलंबो की तरफ जा रहे थे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 38/मु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2023-24 **भोपाल, दिनांक : 25.01.2024**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. नीमच जिले के रेलवे समपार क्रमांक-120 (रतलाम चन्देरिया के रेल सेक्शन के कि.मी. 241/15-16) नीमच छोटी सादडी मार्ग पर इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग कार्य सहित रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु।
2024_PWDRB_328321_1	नीमच	पुल कार्य	तृतीय	3453.15	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. दमोह जिले के नरयावली-मंगोला मार्ग में ग्राम सीतानगर के पास सुनार नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य एवं एच.पी. कलवर्ट सहित कार्य।

2024_PWDRB_328322_1	दमोह	पुल कार्य	पंचम	1358.06	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. मंदसौर जिले के नहारगढ़ बिल्लौद मार्ग के कि.मी. 3/6-8 में शिवना नदी पर एच.टी./लाइन विद्युत पोल शिफ्टिंग हॉय रेन्जिंग कार्य पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।

2024_PWDRB_328323_1	मंदसौर	पुल कार्य	तृतीय	1075.48	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. सागर जिले के बडगान-पर्राका मार्ग के कि.मी. 2/2 में देहार नदी (सत्तीघाट) पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य सहित।

2024_PWDRB_328324_1	सागर	पुल कार्य	चतुर्थ	913.61	केवल ऑन-लाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. पन्ना जिले के उमरहट मेंहा मार्ग में केन नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य एवं एच.पी. कलवर्ट सहित कार्य।

2024_PWDRB_328325_1	पन्ना	पुल कार्य	पंचम	842.48	केवल ऑन-लाइन
		कुल कार्य -		**7642.78**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 16.02.2024 (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

जी-23453/49411/2024 **लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग वि/यॉ संभाग ग्वालियर-474011
ईमेल - eepwdelecgwl@mp.nic.in, फोन नंबर - 0751-2340749
निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 18/व.ले.लि./टेण्डर/2023-24 **ग्वालियर, दिनांक : 23.01.2024**

म.प्र. राज्यपाल की ओर से कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग वि/यॉ संभाग ग्वालियर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेण्डर के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करते हैं। विवरण निम्नानुसार है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. लोक निर्माण विभाग वि/यां. उपसंभाग भिंड के अंतर्गत मुख्यालय एवं आउटर अनुभाग में ए.आर./एस.आर./डिपोजिट/मूल कार्य अनुरक्षण मद में आवासीय/गैर आवासीय भवनों का विद्युतीकरण/नवीनीकरण कार्य।

ई-टेण्डर आई.डी. क्र.	अनुमानित लागत रु.	अमानत राशि रु. + पोर्टल चार्ज	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2024_PWDRB_324346_1	19.50 लाख	39000/- + 2000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार	12 माह वर्षाकाल सहित

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. लोक निर्माण विभाग वि./यां. उपसंभाग ग्वालियर के अंतर्गत मेडीकल, जेल एवं अन्य अनुभाग में ए.आर./एस.आर./डिपोजिट/मूल कार्य अनुरक्षण मद में आवासीय/गैर आवासीय भवनों का विद्युतीकरण/नवीनीकरण कार्य।

2024_PWDRB_324347_1	19.50 लाख	39000/- + 2000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार	12 माह वर्षाकाल सहित

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. लोक निर्माण विभाग वि./यां. उपसंभाग ग्वालियर के अंतर्गत डबरा एवं अन्य अनुभाग में ए.आर./एस.आर./डिपोजिट/मूल कार्य अनुरक्षण मद में आवासीय/गैर आवासीय भवनों का विद्युतीकरण/नवीनीकरण कार्य।

2024_PWDRB_324348_1	10.00 लाख	20000/- + 2000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार	12 माह वर्षाकाल सहित

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. जिला भिंड के ग्राम हिलगंवा-टेहनगुर मार्ग पर स्थित सिंध नदी ब्रिज पर 11 के.व्ही. की पोल शिफ्टिंग एवं 1/6-10 पंप लाइन का कार्य।

2024_PWDRB_324349_1	28.33 लाख	50000/- + 5000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार "A" क्लास ठेकेदार	02 माह वर्षाकाल सहित

क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज पड़ाव ग्वालियर के द्वितीय तल पर विद्युतीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य।

2024_PWDRB_324350_1	8.35 लाख	16700/- + 2000/-	म.प्र. लोनिवि में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार	02 माह वर्षाकाल सहित

निविदा आमंत्रण की सम्पूर्ण शर्तें एवं अन्य जानकारी का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर दिनांक 24.01.2024 समय सुबह 10.30 से **दिनांक 12.02.2024** समय सायं 1730 तक देखी जा सकती है। निविदा हेतु ऑनलाइन बिड सबमिशन दिनांक 12.02.2024 समय सायं 17.30 तक प्रस्तुत की जा सकती है।

1. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
2. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा, सिर्फ वेबसाइट पर ही किया जावेगा। आवंटन आने पर ठेकेदार का भुगतान किया जावेगा।
3. मूल धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र राशि ऑनलाइन ही मान्य की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री

जी-23475/49413/2024 **लोक निर्माण विभाग वि/यॉ. संभाग ग्वालियर**

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, इंदौर परिक्षेत्र, इंदौर
गायत्री मंदिर के पास, ओल्ड पलासिया, इंदौर
E-mail ID :- cepwdwest@mp.nic.in, Phone No. :- 0731-2491825

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 21/सा/40/निविदा/2023-24 **इंदौर, दिनांक : 23.01.2024**

''निविदा आमंत्रण सूचना''

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा तीन लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है :–

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. उसारणी से तारापाटी चिल्लारा पहुंच मार्ग लंबाई 6.50 कि.मी. का निर्माण कार्य।

पोर्टल क्रमांक	जिला	अनुमानित राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र की राशि (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
2024_PWDRB_325893_1	बुरहानपुर	1054.35	1000000/-	30,000/-	14 माह वर्षाकाल सहित

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. काबरी झांगटा मार्ग का निर्माण कार्य मय एल.टी./एच.टी. पोल शिफ्टिंग सहित।

2024_PWDRB_325895_1	खरगोन	1310.95	1000000/-	30,000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
महायोग -		**2365.30 लाख**			

निविदा प्रपत्र उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा का निर्धारित मूल्य ऑनलाइन भुगतान कर क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 06.02.2024 17.30 तक** निर्धारित है। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं नियम उपरोक्त दर्शित पोर्टल पर देखी जा सकती है।

निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन, यदि हो तो उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाकर केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

सभी दस्तावेज केवल ऑनलाइन वेबसाइट पर ही प्रस्तुत करें। भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय में न भेजें जावें।

मुख्य अभियंता

जी-23446/49410/2024 **लो.नि.वि. इंदौर परिक्षेत्र, इंदौर**

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल
ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1048/2023-24/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 24.01.2024**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 16.02.2024** को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2024_WRD_328178	**टर्न की पद्धति पर :–** कबूलपुर (कमरदीपुर) मध्यम परियोजना अंतर्गत प्रेशराईज्ड पाइप सिस्टम द्वारा 3100 हेक्टेयर सिंचाई प्रणाली का निर्माण संबंधी सभी कार्य एवं लखुन्दर नदी पर गागोरनी बैराज (गेट सहित) का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	शाजापुर	5568.02

जी-23522/49416/2024 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

DHAR COLLEGE OF EDUCATION, DHAR (M.P.)
Affilated to DAVV & MP Board, Bhopal (M.P.)
Recognized by NCTE (New Delhi) & Higher Education (Bhopal)

REQUIRES FOR D.EL.ED. & B.ED.

H.O.D., PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR & ASSISTANT PROFESSOR

Eligibility: B.Ed., M.Ed., PG with 55% Marks & Ph.D./NET
Salary : As per Govt. Norms.
Interested Candidates may apply within 7 days between 10 A.M.- 5 P.M.

City Office - Sundarvan Colony, Magajpura Road, Behind Jat Dharmshala, Dhar Campus - 156-160, Gyanpura, Dhar (M.P.)
Phone - 7000803171, 9993009369
Email - dharcollegebedded@gmail.com

R-49417/2024

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग नरसिंहपुर (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक32/वर्ष 2023-24/कार्य.यं. **नरसिंहपुर, दिनांक : 29.01.2024**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. गाड़रवारा उपसंभाग के अंतर्गत (1) सूखा से झिरिया माता मार्ग लंबाई 1.70 कि.मी., (2) बनवारी एप्रोच मार्ग लंबाई 0.80 कि.मी., एवं (3) एस.एच.-22 बेलखेड़ी मोहपा पहुंच मार्ग लंबाई 2.70 कि.मी. का बी.टी. रिन्युवल कार्य। (दसवां आमंत्रण)

टेण्डर आई.डी.	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	धरोहर राशि	निविदा फार्म की राशि	आमंत्रण क्र.	कार्य समयावधि	भौतिक रूप से लिफाफा प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज)
2023_PWDRB_282300_8	नरसिंहपुर	बी.टी. रिन्युवल	53.48	53,500	10,000	दसवां आमंत्रण	3 माह वर्षाऋतु रहित	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. नरसिंहपुर उपसंभाग के अंतर्गत मदार टेकरी मंदिर करेली में पुजारी कक्ष का निर्माण कार्य।

2023_PWDRB_328746_1	नरसिंहपुर	निर्माण	4.24	8,500	2,000	प्रथम आमंत्रण	01 माह वर्षाऋतु रहित	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।
		योग -	**57.72**					

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 10.02.2024, (17.00) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। मूल धरोहर (ई.एम.डी.) राशि एवं अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत दिनांक 10.02.2024, (17.30) बजे तक उपरोक्तानुसार संबंधित पोर्टल में प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री

जी-23602/49419/2024 **लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर**

Request for application to fill the Project Management Unit (PMU) Position of Madhya Pradesh Skills Development Project

Date : 29.01.2024

Madhya Pradesh Skills Development Project (MPSDP), Department of Techincal Education, Skill Development & Employment, Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Skills Development Project (MPSDP) is an Asian Development Bank (ADB) supported program, to reinforce efforts by the Government of Madhya Pradesh (GOMP) to modernize and reform the state's technical and vocational education and training (TVET) system so that its workforce can be equipped with the skills required by the growing development needs of the state.

The Project Director, Madhya Pradesh Skills Development Project (MPSDP), invites eligible individuals to submit their application for the position of **Support Consultant Finance-01**

Interest individuals may submit their application online at ADB Consulting Services Recruitment Notice (CSRN) website **http://csrn.adb.org.in** accordance with the instructions contained there in the CSRN. All other form of submissions including hard copy will not be considered for evaluation. MP Government employees who are interested in joining the project may send application to **mpsdp.dsd@gmail.com** through proper channel with NOC from the parent department for advertised post. The project details and Terms of Reference for the positions are available on the CSRN. the deadling for the submission of applications is **19.02.2024**.

Project Director,

G-23580/49418/2024 **Madhya Pradesh Skills Development Project (MPSDP)**

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)

खेल परिसर के सामने सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष - 07592-297254

E-mail : dean.vds@mp.gov.in, Website : www.gmcvidisha.org

क्रमांक/490-91/स्था./राज/विज्ञप्ति-14 (शैक्षणिक)/24 **विदिशा, दिनांक 01.02.2024**

विज्ञप्ति सूचना

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति वर्तमान में संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 416/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 22.04.2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची एवं एन.एम.सी. के नवीन मापदण्ड/आवश्यकतानुसार, प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक/490-91/स्था./राज/विज्ञप्ति-14 (शैक्षणिक)/24 विदिशा, दिनांक 01.02.2024 के तहत आवेदन पत्र कार्यालय अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में **दिनांक 22.02.2024** सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाने हैं।

ASSOCIATE PROFESSOR/ASSISTANT PROFESSOR (Direct Recruitment)

S. No.	Subject/ Department	ASSOCIATE PROFESSOR				ASSISTANT PROFESSOR			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	Microbiology	-	-	-	-	-	-	-	1
2	General Medicine	-	-	-	-	1	-	1	1
3	General Surgery	-	-	-	-	-	1	1	-
4	Orthopedics	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Anesthesia	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Obs & Gyne	1	-	-	-	-	-	1	1
7	Pediatrics	-	-	-	-	-	-	1	-
8	ENT	-	-	-	-	-	-	-	1
Total Departments - 08 Total Posts -13		**Total UR-1**				**(UR-1, SC-1, ST-6, OBC-4) Total-12**			

PORFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR/ASSISTANT PROFESSOR (Promotion/Direct Recruitment)

S. No.	Subject/ Department	PROFESSOR				ASSOCIATE PROFESSOR				ASSISTANT PROFESSOR			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	General Medicine	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Obs & Gyne	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Dermatology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Radiodiagnosis	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Psychiarty	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Anesthesia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Community Medicine	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total Departments - 07 Total Posts - 08		**Total UR-4**				**UR-2, ST-1, Total-3**				**Total UR-1**			

Process of Direct Recruitment will be followed for below posts Advertised if no Eligible candidate is available (समय-समय पर जारी म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के एवं शासन के अन्य आदेश)

2. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संचालक, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट **www.medicaleducation.mp.gov.in** एवं अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की वेबसाइट **www.gmcvidhisha.org** पर उपलब्ध है।
3. आवेदकों द्वारा अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता कार्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की आवक शाखा में जमा कराये जावेंगे।
4. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और अनारक्षित (UR)/आरक्षित (SC/ST/OBC) श्रेणी का उल्लेख स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जी-23690/49438/2024 **अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा**

कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन), जिला-बैतूल (म.प्र.)

कक्ष क्रमांक-एस-5, कलेक्टर कार्यालय, जिला-बैतूल (म.प्र.)

मो. - +91-9406874542, E-mail - loksevabet@mp.gov.in

क्रमांक/1234/लो.से.प्र./2024 **बैतूल, दिनांक : 01.02.2024**

विज्ञप्ति

राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 493/2023/रालोसेअ/प्रशासन, दिनांक 03.05.2023 के परिपालन में बैतूल जिले में 10 लोक सेवा केंद्रों (आमला, आठनेर, बैतूल, भैंसदेही, भीमपुर, चिचोली, घोड़ाडोंगरी, मुलताई, प्रभातपट्टन तथा शाहपुर) के संचालन के लिए पी.पी.पी. मॉडल के तहत प्रायवेट ऑपरेटर चयन हेतु ऑनलाइन निविदाएं **https://mptenders.gov.in/** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं लोक सेवा केंद्रों की सूची वेबसाइट **https://mptenders.gov.in/** एवं **https://betul.nic.in/** पर उपलब्ध है। निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1.	टेंडर (RFP) का प्रकाशन एवं डाउनलोड प्रारंभ	02.02.2024 (12.00 बजे से)
2.	निविदा प्रपत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि	**23.02.2024** (सायं 5.00 बजे तक)

अधिक जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर/जिला प्रबंधक, लोक सेवा प्रबंधक विभाग, कक्ष क्रमांक-5, द्वितीय तल, कलेक्टर कार्यालय, बैतूल में संपर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर

जी-23627/49420/2024 **जिला-बैतूल (म.प्र.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग बुधनी जिला सीहोर (म.प्र.)

मेन रोड बुधनी फोन नं. 07564-235305

निविदा सचना क्रमांक 19/2023-24/व.ले.लि./बुधनी **दिनांक : 30.01.2024**

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

स. एवं कार्य का नाम :– 1. ग्राम सेमरी से खनपुरा, रतनपुर, में आंतरिक मार्ग सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 3.50 कि.मी.।

टेण्डर क्रमांक	कार्य का प्रकार	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि (EMD)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	आमंत्रण क्र.	ई.एम.डी. एवं निविदा से संबंधित अन्य दस्तावेज
2024_ PWDRB_ 328840_1	योजना कार्य	448.77	448770/-	12 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय	निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं ई.एम.डी. केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे।
2. बुधनी में सी.एम. राइज स्कूल तक सी.सी. पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 1.50 कि.मी.।						
2024_ PWDRB_ 328841_1	योजना कार्य	213.62	213620/-	10 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय	निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं ई.एम.डी. केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे।
3. ग्राम पंचायत मगरिया में ग्राम मंजाखेड़ी मार्ग से पहाड़ी मोहल्ला मगरिया तक मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 0.50 कि.मी.।						
2024_ PWDRB_ 328842_1	खनिज मद	62.11	62110/-	06 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय	निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं ई.एम.डी. केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे।
4. ग्राम इटावा भब्बड धामंदा मार्ग से मायनर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य लंबाई 1.00 कि.मी.।						
2024_ PWDRB_ 328843_1	मंडी मद	74.23	74230/-	06 माह वर्षाकाल सहित	द्वितीय	निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं ई.एम.डी. केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे।
कार्य की अधिकतम लागत (रु. लाख में)	**448.77**					

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय (Document Download/Sale End Date) करने की **अंतिम तिथि 17.02.2024 (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल का पत्र क्र. 401/सा./ई-टेण्डरिंग/09/1088/भोपाल/दिनांक 05.11.2020 द्वारा निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं ई.एम.डी. केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे।

कार्यपालन यंत्री

जी-23635/49421/2024 **लो.नि.वि.सं. बुधनी म.प्र., फोन नं. - 07564-235305**

मध्यप्रदेश में 1277.97 करोड़ रुपये की लागत से दो राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे अपग्रेड

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी का मध्यप्रदेश में दो राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में अपग्रेड करने के लिए कुल 1277.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर आभार माना है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-543 के शहडोल-सागरटोला खंड को एचएएम मोड के तहत पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में अपग्रेड करने के लिए 852 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्वीकृति दी है।

यह स्ट्रेच डिंडोरी और मंडला के पिछड़े इलाकों को शहडोल से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भीड़-भाड़ वाले कस्बों, गांवों में बाईपास, रिअलाइनमेंट के प्रावधान और पहाड़ी, घाट खंडों में सुधार के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-543 पर यातायात का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित होगा। इस परियोजना से क्षेत्र का सामाजिक तथा आर्थिक विकास होगा। साथ ही कोयला और कृषि उत्पादों का परिवहन सुगम हो सकेगा।

दूसरी परियोजना के तहत मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-346 के पिछोर-दिनारा खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में अपग्रेड करने के लिए 425.97 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्वीकृति दी है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। जिसकी मध्यप्रदेश में लम्बाई 334.55 किलोमीटर है।

यह राजमार्ग प्रसिद्ध चंदेरी किले को जोड़ता है। यह परियाजना झांसी के पास दिनारा (अंतिम बिंदु) पर राष्ट्रीय राजमार्ग 527 को पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल

E-mail - dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/स्था./24/10 बैतूल, दिनांक 30.01.2024

विज्ञापन

1. मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-7/2018/छब्बीस-1 दिनांक 26.07.2019 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8 2/2013/आ.प्र./एक दिनांक 04.07.2022 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 8 2/2013/आ.प्र./एक, दिनांक 04.01.2024, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/क्षे.स्था.2/दिव्यां./4030 दिनांक 25 जुलाई 2022 एवं मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त बैतूल का पत्र पृ. क्रमांक/स्था./2927 दिनांक 28.07.2022 के अनुपालन में वन वृत्त बैतूल जिला बैतूल के अंतर्गत निःशक्तजनों के रिक्त पद चतुर्थ श्रेणी के पद पर ''वॉक-इन-इन्टरव्यू'' के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान के तहत पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में निःशक्त उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. संबंधित निःशक्तजन आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.02.2024 तक कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल कालापाठा बैतूल म.प्र. में व्यक्तिगत रूप से शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. संबंधित निःशक्तजन आवेदन **दिनांक 23.02.2024** को 11.00 बजे प्रातः कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल में अपने शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों के साथ ''वॉक-इन-इन्टरव्यू'' के लिए उपस्थित होवें। रिक्त पद का विवरण, शैक्षणिक योग्यताएं एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :–

क्र.	पदनाम	कुल पद संख्या	वेतनमान	श्रेणीवार रिक्त पद श्रवण बाधित (बहरे और कम सुनने वाले) 1.5%	शैक्षणिक योग्यता एवं आयु-सीमा
01	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी)	01	15500-49000	01	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण/18 वर्ष से 40 वर्ष की अतिरिक्त छूट सहित 45 वर्ष अधिकतम।

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें :–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
3. आयु सीमा भृत्य के लिए दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभागों/निगमों/मंडलों/आयोगों/शासकीय निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शासकीय रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों का शासन के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
5. चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात भी आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन समाप्त किया जा सकेगा।
6. जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम (आयु पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया होगा उसे उक्त पदों हेतु अयोग्य माना जावेगा।
7. म.प्र. शासन के नियम अनुसार जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, तथा उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 के पश्चात हुआ हो तो वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
8. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से भेजें, सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटि पूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
10. बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल के पास होगा। चयन नियुक्ति में वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) का निर्णय अंतिम होगा।
11. आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा आवेदन पत्र ए-4 साइज पेपर पर कम्प्युटर पर मुद्रित या टाइप कराया जाये तथा उसकी समस्त प्रविष्टियां हस्तलिपि में करें एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें, निर्धारित स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा करें।
12. आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल निवास, जन्मतिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग आदि) से संबंधित प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंकसूची/अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां (स्वयं के द्वारा प्रमाणित संलग्न की जाये)।
13. निःशक्त आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल/चिकित्सक निःशक्तजनों के लिए रोज़गार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14. मेरिट के आधार पर ''वॉक-इन-इन्टरव्यू'' के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल

प्रति,
वनमण्डलाधिकारी,
उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल
कालापाठा बैतूल (म.प्र.)

स्वयं का वर्तमान का फोटो चिपकाएं (जो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो)

उम्मीदवार का विवरण :– .....

1. आवेदक का नाम (सुस्पष्ट अक्षरों में) :–.....
2. पिता/पति का नाम :– .....
3. आवेदक की जन्मतिथि (अंकों में) :–.....
   (शब्दों में) :– .....
4. जन्मस्थान :– .....
5. 01.01.2024 को आयु :– वर्ष.....माह .....दिन.....
6. स्थाई पता:– .....
   .....
7. वर्तमान पता :– .....
   .....
8. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई-टेंडरिंग/406/1464

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

ईमेल- mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in

फोन : 0755-2553402 फैक्स : 0755-2552406

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक- 564/2715001/ई.डी.पी./2021-22/प्र.अ./ई-टेंडरिंग **भोपाल, दिनांक: 29.01.2024**

निम्न कार्यों हेतु निविदा **वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक **14.02.2024** को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य का नाम	जिला	राशि रु. लाख में
1	2024_WRD_309879	दुमदुमा तालाब की पोषक नहर के वार्षिक रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य।	निवाड़ी	3.91
2	2024_WRD_323767	बंधी जलाशय के स्लूस वेल प्लेटफार्म का सुधार कार्य एवं उसके रैम्प का निर्माण व बांध की ऊपरी सतह पर मिट्टी डालने का कार्य।	जबलपुर	3.71
3	2024_WRD_323782	डोली जलाशय की नहर की आर.डी. 180 मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का सुधार एवं मरम्मत कार्य।	जबलपुर	6.97
4	2024_WRD_325549	रेहटी मध्यम परियोजना के बांध की सुरक्षा हेतु बंदूकधारी प्रायवेट गार्ड का प्रदाय कार्य।	विदिशा	8.13
5	2024_WRD_325550	सगड़ मध्यम परियोजना के बांध की सुरक्षा हेतु बंदूकधारी प्रायवेट गार्ड का प्रदाय कार्य।	विदिशा	16.26
6	2024_WRD_325551	गंजबासौदा के स्टापडेम एवं बैराजों के गेट खोलने एवं बंद करने का कार्य।	विदिशा	6.50
7	2024_WRD_325553	उपसंभाग कुरवाई के स्टापडेम एवं बैराजों के गेट खोलने एवं बंद करने का कार्य।	विदिशा	9.11
8	2024_WRD_325555	उपसंभाग सिरोंज एवं शमशाबाद के स्टापडेम एवं बैराजों के गेट खोलने एवं बंद करने का कार्य।	विदिशा	8.99
9	2024_WRD_328067	मिठौरी जलाशय के जलद्वार का पानी के अन्दर का मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य।	रीवा	1.81
10	2024_WRD_328068	गोदहा उद्वहन सिंचाई योजना में स्थापित विद्युत यांत्रिक उपकरणों का मरम्मत एवं रखरखाव कार्य।	रीवा	4.23
11	2024_WRD_328078	केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई, भोपाल हेतु उच्च कुशल वेल्डर का प्रदाय।	भोपाल	2.21
12	2024_WRD_328079	विभिन्न जलद्वारों हेतु हेड स्टाक का प्रदाय, कास्टिंग, मशीनिंग एवं असेम्बली का कार्य।	भोपाल	9.75
			कुल	81.59

जी-23669/49436/2024 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

9. यदि आप शासकीय सेवक हैं, तो :–
   कार्यालय/विभाग का नाम :– .....
   पदनाम :– .....
   कार्यरत अवधि :– .....
   (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण संलग्न करें)
10. रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, तो जाति/उपजाति का नाम :–.....
    .....
    (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
12. मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त :–.....
    (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
13. विकलांगता का प्रतिशत :– .....
    (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
14. विवाहित/अविवाहित :– .....
15. विवाहित होने की दशा में :–
    (1) विवाह का दिनांक :– .....
    (2) जीवित बच्चों की संख्या :– .....
    (3) अंतिम बच्चे का जन्म दिनांक :– .....
16. अन्य अनुभव कोई हो तो अंकित करें :– .....
17. संलग्न दस्तावेजों का विवरण :– .....

आवेदक के हस्ताक्षर :– .....
नाम :– .....
मो. नंबर :– .....

घोषणा-पत्र

मैं.....पिता/पति श्री.....
उम्र.....वर्ष, जाति.....निवासी.....
जिला.....राज्य.....यह घोषणा करता/करती हूं, कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाई गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है, कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर जांच में जानकारी सही नहीं पाई जाने तथा मूल दस्तावेजों के मिलान/जांच में सही नहीं पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र पर की गई समस्त कार्यवाही बिना सुनवाई का अवसर दिए निरस्त/समाप्त कर दी जावें, तथा मेरे विरुद्ध अपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी वापस किया जावेगा।

स्थान :–..... **आवेदक के हस्ताक्षर :– .....**
दिनांक :–..... **नाम :– .....**
जी-23684/49437/2024 **मो. नंबर :– .....**

उत्तराखंड हाईकोर्ट

पद का नाम - जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर/पर्सनल असिस्टेंट
पदों की संख्या - 139
योग्यता – हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से कंप्यूटर पर टाइपिंग। स्टेनोग्राफर/पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन के साथ हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से शॉर्टहैंड और 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से कंप्यूटर टाइपिंग। इंग्लिश में 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्टहैंड और 35 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए।
अंतिम तिथि - 22 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://highcourtofuttarakhand.gov.in/

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

पद का नाम – लॉ क्लर्क/रिसर्च एसोसिएट
पदों की संख्या - 90
योग्यता - उम्मीदवार कानून द्वारा स्थापित और मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थान से लॉ में ग्रेजुएट हो।
अंतिम तिथि - 15 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://main.sci.gov.in/

एनटीपीसी लिमिटेड

पद का नाम – असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव
पदों की संख्या - 223
योग्यता - आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली हो।
अंतिम तिथि - 08 फरवरी 2024
वेबसाइट- https://careers.ntpc.co.in/

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

पद का नाम - प्रोजेक्ट इंजीनियर/प्रोजेक्ट ऑफिसर/प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट/प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट/ऑफिस असिस्टेंट
पदों की संख्या - 361
योग्यता - उम्मीदवारों के पास बीई/बीटेक/बीएससी (4 वर्ष)/एमई/एमटेक की डिग्री होनी चाहिए।
अंतिम तिथि - 14 फरवरी 2024
वेबसाइट - https://onlinereg.co.in/senareg24/Home.aspx

राजस्थान लोक सेवा आयोग

पद का नाम – प्रोग्रामर
पदों की संख्या - 216
योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बी.ई./बीटेक/एमएससी या एमसीए की डिग्री या एमटेक/एमबीए की डिग्री होनी चाहिए।
अंतिम तिथि - 01 मार्च 2024
वेबसाइट - https://rpsc.rajasthan.gov.in/

संघ लोक सेवा आयोग

पद का नाम – स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड, साइंटिस्ट बी, असिस्टेंट डायरेक्टर
पदों की संख्या - 69
योग्यता - स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस, पीजी डिग्री। साइंटिस्ट बी के लिए बैचलर, मास्टर्स डिग्री और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मास्टर्स डिग्री।
अंतिम तिथि - 15 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://upsc.gov.in/

आरईसी लिमिटेड

पद का नाम – डिप्टी जनरल मैनेजर (इंजीनियरिंग), चीफ मैनेजर (इंजीनियरिंग), मैनेजर (इंजीनियरिंग), डिप्टी मैनेजर (इंजीनियरिंग), असिस्टेंट मैनेजर (इंजीनियरिंग), ऑफिसर (इंजीनियरिंग), मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर
पदों की संख्या - 127
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 09 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://recindia.nic.in/

एडसिल

पद का नाम – पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स)
पदों की संख्या - 100
योग्यता - संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास हो। इसके साथ ही उम्मीदवारों ने बीएड पास किया हो।
अंतिम तिथि - 15 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://edcilteacherrecruitment.com/

झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023

पद का नाम - डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में राज्य कर पदाधिकारी, जेल अधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा, जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, उत्पाद निरीक्षक
पदों की संख्या - 342
योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए।
अंतिम तिथि - 29 फरवरी 2024
वेबसाइट - https://www.jpsc.gov.in/

एडमिशन अलर्ट

निफ्ट प्रवेश 2024

पाठ्यक्रम का नाम - डिजाइन स्नातक
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 29 फरवरी 2024
वेबसाइट - https://nift.ac.in

स्कॉलरशिप अलर्ट

नरोत्तम सेखसरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम

किनके लिए - योग्यता आधारित छात्रवृत्ति है। मेधावी भारतीय छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
योग्यता - भारत या विदेश में किसी शीर्ष रैंकिंग संस्थान में मास्टर्स डिग्री में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो। फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
क्या मिलेगा - चयनित छात्रों को ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन और मेंटरशिप गाइडेंस प्राप्त होगा।
अंतिम तारीख - 14 मार्च 2024
वेबसाइट - http://pg.nsfoundation.co.in/

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा अन्न योजना का वरदान

मनुष्य को जीने के लिए पहली आवश्यकता है भोजन। भारत के संविधान में देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है। इस अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीब व्यक्ति अपना भोजन जुटाने में सक्षम नहीं था। वह अपनी आधारभूत जरूरत को पूर्ण न कर पाने से व्यथित भी था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर गरीब के भोजन की समस्या का समाधान किया। इसके परिणामस्वरूप देश के 80 करोड़ से अधिक निर्धनजनों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2014 में दायित्व ग्रहण करते ही प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था। उसी क्रम में कई योजनाओं को लागू भी किया और क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित की गयी। देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को अन्न के लिए खर्च किये जाने वाले पैसों की चिंता से मुक्त करना साधारण कार्य नहीं है। इतने बड़े फलक पर किसी योजना को धरातल पर ले जाने का असाधारण कार्य केन्द्र सरकार ने कर दिखाया।

निःशुल्क अन्न के वितरण की शुरुआत कोरोना काल में की गयी थी। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के समय जब सब कुछ बंद था। तब प्रधानमंत्री ने हर दिन हाथ से कमा कर खाने वालों की सबसे पहले चिंता की और गरीब के भोजन की व्यवस्था की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से घर-घर मुफ्त अन्न पहुँचाया और काम-काज बंद होने की स्थिति में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। कोरोना काल में केन्द्र सरकार की इस योजना ने करोड़ों लोगों को भूख से बचाया और लोकहित में केन्द्रीय नेतृत्व की अनूठी मिसाल कायम की। वर्तमान चरण में इस योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वर्ष 2028 तक देश के गरीब हितग्राहियों को भोजन के लिए निःशुल्क अन्न प्रदान किया जायेगा। केन्द्र सरकार का यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक कदम है। इससे हर गरीब के भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित है। ताकि इस श्रेणी के लोग आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकें।

नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने 1 जनवरी, 2023 से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी। इससे लाखों पात्र परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। इस योजना में 80 करोड़ से अधिक अत्यंत निर्धन लोगों को लाभांवित किया जा रहा है। यह एकीकृत योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों तक खाद्यान्न की पहुँच, वहनीयता और उपलब्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी कदम है।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की स्थिति

प्रदेश में यह योजना खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 28 श्रेणियों के 127.69 लाख परिवारों के 5.37 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। जिसमें प्रतिमाह अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार तथा प्राथमिक परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

देश के 6 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंड़ीगढ़, दिल्ली और गुजरात में गेहूं प्रदान किया जाता है तथा शेष राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में चावल उपलब्ध कराया जाता है।

क्या है पात्रता

अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।

योजना में विशेष

प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखण्डों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों को आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक परिवार को एक रुपये किलो की दर से डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण 33 जिलों में किया जा रहा है।

इसमें सम्मिलित पात्र परिवारों को आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए माह जनवरी 2023 से प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना

इस योजना से जहां ग्रामीणों के गांव तक राशन पहुंचाया जाता है वहीं राशन पहुंचाने के कार्य में लगे अनुसूचित जनजाति के युवाओं को रोज़गार प्राप्त होता है।

योजना के तहत मध्यप्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय विकासखण्डों में शामिल ग्रामों में राशन सामग्री पहुंचाने के साथ गांव में ही वितरित की जाती है। यह कार्य अनुसूचित जनजाति के युवकों द्वारा किया जाता है। इसमें विकासखण्डों में आने वाले 6 हजार 575 गांवों में लगभग 7.13 लाख परिवारों को गांव में ही राशन वितरित किया जा रहा है। राशन सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन के लिए प्रति हितग्राही 2 से 3 लाख रुपये मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है। वितरण कार्य करने वाले हितग्राहियों को 1 टन वाहन क्षमता के लिए 24 हजार तथा 2 टन वाहन क्षमता के लिए 31 हजार रुपये मासिक किराया का भुगतान किया जा रहा है। इस तरह इस योजना से 472 सेक्टरों में जनजाति वर्ग के बेरोज़गारों को वाहन प्रदान कर वितरण का कार्य किया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को अपने गांव में ही राशन मिलने से उनके समय और श्रम की बचत हो रही है तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। जिन वाहनों से राशन वितरित किया जा रहा है इसकी मानिटरिंग के लिए वाहनों में जीपीएस लगाए गए हैं। गांव में वितरित किये गये राशन की जानकारी पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

कम्प्यूटरीकरण और राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था

इसके अन्तर्गत शामिल हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीन लगाई गई है। इसके द्वारा हितग्राही की ई-केवाईसी की जाती है। अभी तक 3.31 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण के समय पीओएस मशीन से जारी होने वाली पावती एवं प्रदाय सामग्री का वितरण प्राप्त होता है। साथ ही हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा वितरित सामग्री की जानकारी भी दी जा रही है। अभी तक प्रदेश के 113.58 लाख (89 प्रतिशत) परिवारों के डेटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज किये जा चुके हैं।

कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित कर राशन वितरण करने के लिए बॉयोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरित किया जा रहा है। यदि किसी वृद्धजन अथवा निःशक्तजन या फिर मजदूर हितग्राही को बायोमेट्रिक सत्यापन करने में समस्या आती है तो उनके मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से या फिर नॉमिनी के माध्यम से राशन वितरण की व्यवस्था की गई है।

वन नेशन वन राशन कार्ड

प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल सभी परिवार प्रदेश की लगभग 26 हजार 767 तथा अन्य राज्यों की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। वर्ष 2022 से अभी तक राज्य अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से लगभग 1.99 करोड़ परिवारों को एवं अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से 4.30 लाख परिवारों को (अन्य राज्य एवं प्रदेश में) राशन प्रदाय किया गया है।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सामग्री के परिवहन का कार्य अब ठेकेदारों से नहीं करवाया जा रहा है। अन्न परिवहन का कार्य युवाओं के द्वारा करवाने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू की गई है। इसके तहत लगभग 900 बेरोज़गार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत ऋण स्वीकृति से 7.5 मेट्रिक टन क्षमता के वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे। अभी तक 752 हितग्राहियों को वाहन उपलब्ध करवा दिये गये हैं। इनके द्वारा राशन सामग्री का परिवहन किया जा रहा है। सरकार द्वारा रुपये 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिनमनी 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर दिया गया है। योजना के तहत बेरोज़गार युवकों को रोज़गार मिलने के साथ-साथ सामग्री का परिवहन भी त्वरित गति से किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण से गरीब तथा निर्धन परिवार को आधारभूत खर्च के बोझ से मुक्त किया है। योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए किये जाने वाले प्रयासों में से एक है। इससे जहां देश के हर गरीब और निर्धन के लिए भोजन की व्यवस्था हुई है वहीं आत्मनिर्भरता की और बढ़ते कदमों में इस वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

- हितेश शर्मा
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

भारत सरकार का अंतरिम बजट

गरीब, युवा, किसान, महिला सशक्तिकरण, परिवहन स्वरोज़गार और अनुसंधान को प्राथमिकता

विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में एक और कदम

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में वर्ष 2024-25 के लिये भारत सरकार का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट के प्रावधान भारत को विश्व का उन्नत राष्ट्र बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की प्रतिभा विकास से स्वरोज़गार, यातायात की सुविधाएं बढ़ाना और शोध एवं अनुसंधान पर जोर दिया गया है। नि:संदेह यह विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दस वर्षीय कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। लोकसभा चुनाव संभवतः अप्रैल-मई में होंगे। इसलिए यह पूर्ण बजट नहीं है, अंतरिम बजट है। सामान्यतः अंतरिम बजट में नीतिगत कोई बड़े निर्णय कम होते हैं। यद्यपि अंतरिम बजट में बड़ी घोषणा न करने का कोई बंधन नहीं है फिर भी इस अंतरिम बजट में मर्यादा का ध्यान रखा गया है और चुनाव सिर पर होने के बाद भी कोई बड़ी लोकलुभावन घोषणा नहीं की गई। न कोई नया कराधान हुआ और न किसी पुराने कराधान में कोई राहत दी गई। पिछले बजट की तुलना में कुछ मदों के प्रावधान को बढ़ाकर अपनी आगामी यात्रा और लक्ष्य पूर्ति का संकेत दिया गया है। जो भी परिवर्तन किये गये हैं, वे समय की आवश्यकता और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर किये गये हैं। वह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सदैव प्रगति करता है जो आने वाले समय की आवश्यकता और चुनौती को ध्यान में रखकर लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है। मोदी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विश्व के विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में अग्रणी बनाना है। इस अंतरिम बजट में उसकी स्पष्ट झलक है। इस बजट में ही नहीं मोदी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में इसी दिशा में कदम बढ़ाया है। जिसके परिणाम भी आने लगे। जिनका उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रस्तुति में किया है, इसे विकसित भारत के लिये 'मोदी की गारंटी' कहा जा सकता है। बजट में मोदी जी के उस कथन की पूरी झलक है जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी कमजोरियों को दूर करके और विशेषताओं के उपयोग से ही भारत विश्व स्पर्धा में अग्रणी होगा। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी गरीबी है और युवा प्रतिभाओं को समुचित विकास के अवसरों की तलाश है। यदि युवा अपनी क्षमता प्रतिभा का पूरा उपयोग करें, गरीबी दूर हो, खेतों में अन्न का भरपूर उत्पादन हो और गृहणियां प्रसन्न हों तो कौन है जो भारत की प्रगति को रोक पायेगा। बजट प्रावधानों में यह संदेश बहुत स्पष्ट है और इसी दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट भाषण में पांच बातों पर बहुत जोर रहा। पहला समाज और राष्ट्र के विकास के लिये गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रावधान, दूसरा आंतरिक परिवहन सुविधा वृद्धि, तीसरा भविष्य के भारत निर्माण के लिये शोध एवं अनुसंधान पर जोर, चौथा प्रतिभा विकास से स्वरोज़गार के अवसर एवं पांचवा सीमा सुरक्षा को मजबूत करना।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के लिये दो मंत्र दिये थे। एक 'सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' एवं दूसरा 'ज्ञान का सम्मान'। मोदी सरकार की योजनाएं इन मंत्रों के आसपास ही रही हैं। इस बजट में इन दोनों मंत्रों की झलक है और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र ज्ञान (Gyan) का आशय गरीब, युवा, अन्नदाता अर्थात किसान और नारी हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस सिद्धांत का उल्लेख किया। सबसे पहले इन सभी वर्गों की प्रगति का विवरण दिया, बजट को आंकड़ों में समझाया और भविष्य की संकल्पना प्रस्तुत की-

अंतरिम बजट : एक दृष्टि

अंतरिम बजट में न तो कोई नया कराधान है और न किसी पुराने कर में राहत। इसलिये यह बजट बाजार को अधिक प्रभावित नहीं करेगा। फिर भी यदि बाजार के मूल्य सस्ते या मंहगे होते हैं तो यह बजट के कारण नहीं बाजार की अपनी व्यवस्था से होंगे। इस बिना घटा बढ़ी के बावजूद आय बढ़ने और घाटा कम होने की उम्मीद है। करदाताओं की यह बढ़ती संख्या और कर प्रणाली के सुधार के कारण होगा।

अंतरिम बजट में कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये के हैं। इसमें उधारी को छोड़कर कुल संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपये और प्राप्तियों के 23.24 लाख करोड़ रुपये हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह आशा व्यक्त की है कि 30.03 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर का प्रतीक है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2024-25

- उधारी से कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान यथावत रखा गया है।
- वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

भविष्य की संकल्पना : लक्ष्य और प्रावधान

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में विकसित भारत अभियान के अंतर्गत किये जाने वाले भविष्य के प्रावधानों का भी उल्लेख किया। इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रावधान है शोध और अनुसंधान पर एक लाख करोड़ का प्रावधान। जिस प्रकार दुनिया आगे बढ़ रही है, उसमें भारत को अग्रणी होने के लिये शोध और अनुसंधान पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यह भारत की अपनी तकनीक थी कि भारत का चन्द्र अभियान संसार में सबसे किफायती रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस पक्ष पर सदैव ध्यान दिया और आगामी वर्ष के लिये एक बड़ी राशि का प्रावधान किया। यह प्रावधान दोनों प्रकार का होगा, संस्थागत भी और व्यक्तिगत भी। इससे तकनीकी विकास भी होगा और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस मद में 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है।

रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके लिये बुनियादी ढांचा के विकास और रोज़गार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है।

यातायात की सुगमता और कम लागत पर लॉजिस्टिक्स कुशलता बेहतर बनाने के लिए तीन प्रमुख आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है। इन पर तेजी से काम होगा और 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। यातायात सुगमता के लिये रेल मार्ग के साथ विमानन क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। देश में हवाई अड्डे दोगुने हुये हैं और यह संख्या 149 हो गई है। भविष्य में नये हवाई मार्ग और विमानतल विकसित होंगे। देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए।

वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।

परिवहन के लिए कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र में राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पर्यटन केन्द्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा।

इस अंतरिम बजट में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान वैकल्पिक ऊर्जा के विकास का है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि छत पर सौर प्रणाली लगाने का अभियान छेड़ा जायेगा। इससे 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। हरेक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान है।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में अब सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण को बल मिलेगा।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय योजनाओं की सहायता से राज्यों की प्रगति का भी विवरण दिया और बताया कि राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया है।

प्रगति के आयाम और उपलब्धियां

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार यह इस सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि पिछले दस वर्षों में भारत के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आये हैं। प्रधानमंत्री जनधन खातों में लगभग 34 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता दी गई और 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ चार करोड़ किसानों को मिला। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपये के क्रय विक्रय के साथ 1.8 करोड़ किसानों की सहायता की गई।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महिलाओं के विकास का भी विवरण दिया। उनके अनुसार 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा, स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन हुआ, जो दुनिया में सबसे अधिक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को ही दिए गए।

अब इस नये बजट में तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की कि अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोज़गार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिली।

देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हुई

पिछले दस वर्षों में 517 नए हवाई मार्गों पर 1.3 करोड़ लोगों ने यात्रा की। वहीं पिछले दस वर्षों में एफडीआई का अंतर्प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले दोगुना हुआ।

प्रत्यक्ष कर प्रक्रिया में सुधार

इस अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया है। लेकिन प्रक्रिया में कुछ सुधार हुये हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना हुआ है। यह रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वृद्धि से हुआ। इन दस वर्षों में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। यह सरकार द्वारा करदाता प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार के कारण संभव हुआ। इस प्रक्रिया में सरकार और सुधार ला रही है तथा वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इससे रिटर्न प्रक्रिया और सरल होगी। इसके साथ ही अब वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इससे एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया जायेगा।

आईएफएससी इकाईयों की कुछ आय पर कर रियायत को एक साल बढ़ाकर 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया है।

अप्रत्यक्ष कर

इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर की भाँति अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को भी यथावत रखा है। लेकिन प्रक्रिया में सुधार किया है। अप्रत्यक्ष करों में सरकार को सबसे अधिक लाभ जीएसटी से हुआ। इस कर प्रणाली ने देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया है। इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ

जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ

- राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात (राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित) जीएसटी से पहले की अवधि (2012-13 से 2015-16) के 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि (2017-18 से 2022-23) के दौरान 1.22 हो गया
- उद्योग जगत के 94 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफी कुछ सकारात्मक रही है। सरकार ने जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला को अपेक्षाकृत अधिक युक्तिसंगत बनाया है। इससे व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ।

- रमेश शर्मा

(लेखक- वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं)

मध्यप्रदेश की चार प्रतिभाओं को मिला पद्मश्री सम्मान

देश के पिचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की घोषणा की।

इस साल एक सौ चौंतीस पद्म सम्मानों की घोषणा हुई है, जिनमें पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री सम्मान शामिल हैं। पद्मश्री के घोषित सम्मानों में से मध्यप्रदेश की चार प्रतिभाओं- माच लोकनाट्य के सिद्धहस्त कलाकार उज्जैन के ओमप्रकाश शर्मा, कबीर के भजनों के लोकगायक देवास के कालूराम बामनिया, हिन्दी, संस्कृत और इतिहास के अध्येता और विद्वत डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित और ग्वालियर के पैरा स्विमर सत्येन्द्र लोहिया को इस वर्ष के पद्मश्री सम्मान के लिये चुना गया है। श्री ओमप्रकाश शर्मा और कालूराम बामनिया को कला अनुशासन में, डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित को साहित्य व शिक्षा अनुशासन में और सत्येन्द्र लोहिया को खेल अनुशासन के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है।

माच के सुदीर्घ साधक हैं पण्डित ओमप्रकाश शर्मा

मध्यप्रदेश के पण्डित ओमप्रकाश शर्मा को वर्ष 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन के

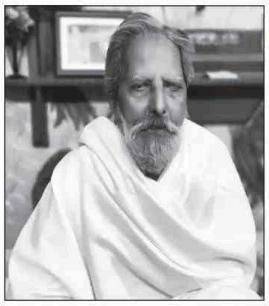

रहने वाले पण्डित ओमप्रकाश शर्मा को भारत में माच लोक रंगमंच का पर्याय माना जाता है। उन्होंने माच के लिए मालवी भाषा में कई नाटक लिखे हैं। उन्होंने माच की थिएटर प्रस्तुतियों के लिए संगीत भी तैयार किया और युवा कलाकारों को इस लोक कला का प्रशिक्षण भी दिया। पिच्यासी वर्षीय ओमप्रकाश शर्मा ने अपनी जिंदगी के सत्तर साल मालवा की दो सौ साल पुरानी इस पारम्परिक लोक नृत्य कला को दिए हैं। माच गायन के अलावा उन्होंने अट्ठारह नाटक लिखे। मालवी माच गीत और नाटकों के साथ उन्होंने देशभर में कई प्रस्तुतियां दीं। माच लोकनाट्य के विलक्षण कलाकार उस्ताद कालूराम उनके दादा थे। पण्डित ओमप्रकाश शर्मा बचपन से ही माच लोक कला का अभ्यास करते रहे हैं। उन्होंने पांच वर्ष की छोटी उम्र से माच का अध्ययन और शास्त्रीय गायन की शिक्षा अपने पिता पंडित शालीग्राम से लेना शुरू कर दी थी। वर्तमान में वे कालूराम लोक कला केन्द्र के डायरेक्टर हैं। सौ-डेढ़ सौ साल पहले मालवा क्षेत्र के अखाड़ों में माच का प्रदर्शन मनोरंजन के लिए होता था। माच गीतों में बड़े ढोलक, सारंगी व अन्य वाद्ययंत्रों का उपयोग होता है। हालांकि अब कुछ कलाकार हारमोनियम का भी उपयोग करने लगे हैं। माच हिन्दी शब्द मंच का अनुवाद है।

विलक्षण भजन गायक हैं कालूराम बामनिया

मध्यप्रदेश के कालूराम बामनिया को कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने वर्ष 2024 के लिये पद्मश्री अवॉर्ड देने की घोषणा की है। कालूराम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कबीर भजन गायक हैं, जो अपने अनूठे तरीके के गायन के लिए जाने जाते हैं। देवास के कालूराम बामनिया ने अपनी विलक्षण भजन गायकी के माध्यम से कबीर के दर्शन को विदेशों तक पहुंचाया है। कालूराम बामनिया मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में कबीर, गोरखनाथ, बन्नानाथ और मीरा जैसे भक्ति कवियों के भजन गाते हैं। कालूराम का गायन भक्तिकाल के कवियों के भजन गायन की एक जीवन्त परम्परा से सम्बन्धित है। कालूराम बामनिया की कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। महज

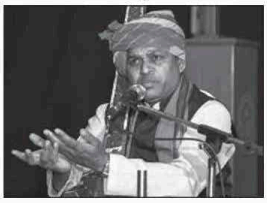

नौ साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता, दादा और चाचा के साथ मंजीरा बजाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। तेरह साल की उम्र में वे घर छोड़कर राजस्थान चले गए यहां उन्होंने गायन सीखा। इसके बाद करीब दो साल तक उन्होंने भ्रमणशील मिरासी गायक राम निवास राव के गीतों की एक विस्तृत सूची को समाहित किया। कालूराम अपने गायन को लेकर कहते हैं कि उनके लिए यह सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उनका कहना है कि कबीर को गाने से बहुत आत्मिक शक्ति मिलती है। आज कालूराम और उनकी मण्डली राज्य और देश-विदेश में प्रस्तुतियां देती हैं। कालूराम मानते हैं कि भजन गायकी विशेष रूप से भक्तिकाल के कबीर और मीरा के भजनों की गायकी अवसाद को भी दूर कर सकती है।

साहित्य, संस्कृति के अध्येता हैं डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित

डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित मध्यप्रदेश के धार जिले के चंदोड़िया गांव से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हिन्दी, संस्कृत और प्राचीन इतिहास में एम.ए. पीएच.डी. की है। वे साहित्य, संस्कृति और हिन्दी,

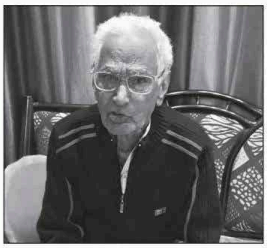

मालवी भाषा के विकास के लिए सतत लेखन करते हैं। उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय अभिलेख और इतिहास और राजा भोज जैसी शोधपरक पुस्तकें लिखी हैं। इतिहास के अध्येता पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउकृत के सम्पादन में भारत के प्राचीन राजवंश (तीन खण्ड) का लेखन भी किया। उन्होंने राजा भोज का रचना विश्व, प्रतिभा भोजराजस्य, भोजराज, कालिदास, कालिदास का वागर्थ, उज्जयिनी और महाकाल, विद्योत्तमा (उपन्यास), 'वीणावासवदत्ता' (हिन्दी में), 'पद्यप्राभृतक' (हिन्दी में), 'सेज को सरोज' (मालवी में), हलकारो बादल-मेघदूत' का मालवी में रूपान्तर और मालवी लोकगीत' (सम्पादन-अनुवाद) पुस्तकों का लेखन भी किया। डॉ. राजपुरोहित उज्जैन के सांदीपनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिन्दी विभाग में आचार्य और अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

डॉ. राजपुरोहित को वर्ष 1984 और वर्ष 1990 में मध्यप्रदेश संस्कृत अकादमी का भोज पुरस्कार , मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1990 और वर्ष 1992 में डॉ. राधाकृष्णन सम्मान और वर्ष 1988 में इन्हें मध्यप्रदेश साहित्य परिषद के बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

पैरा स्विमर सत्येन्द्र सिंह लोहिया के अवदान को मिली मान्यता

भारत सरकार ने वर्ष 2024 के लिये जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है उनमें मध्यप्रदेश के पैरा स्विमर सत्येन्द्र सिंह लोहिया भी शामिल हैं। यह सम्मान देकर भारत सरकार ने खेल जगत में उनके

अवदान को मान्यता दी है। सत्येन्द्र सिंह लोहिया एक ऐसे तैराक हैं जो सत्तर प्रतिशत विकलांग हैं। इनका जन्म वर्ष 1987 में मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के एक गांव में हुआ था। इनका जन्म सामान्य बच्चों की तरह हुआ था पर जन्म के पन्द्रह दिन के भीतर ही एक गम्भीर बीमारी का इलाज न मिलने के कारण उनके पैरों की नसों में सिकुड़न होने की वजह से वे शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी क्षमता और इच्छाशक्ति के बूते पर अपने नाम पर इतनी उपलब्धियां हासिल कीं कि वे कई लोगों के लिए मिसाल बन गये हैं। वे एशिया के पहले तैराक हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल पार कर इतिहास रचा है, जो कि एक रिले इवेण्ट था।। इसमें छत्तीस किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को चौदह घण्टे उन्तालीस मिनट में पार किया था। इस इवेण्ट के लिए इनका नाम एशियाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। अमेरिका में ग्यारह घण्टे चौंतीस मिनट में कैटलीना चैनल भी पार किया था। वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश सरकार का सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवॉर्ड और वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का राष्ट्रीय अवॉर्ड भी मिल चुका है।

- राजा दुबे

(लेखक, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक जनसंपर्क हैं)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सामान्य ज्ञान - खेल

1. इस वर्ष यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
(अ) फ्रांस (ब) जर्मनी
(स) क्रोएशिया (द) स्पेन

2. वर्ष 2014 में किस देश ने फीफा फुटबॉल वर्ल्डकप जीता था?
(अ) जर्मनी (ब) अर्जेंटीना
(स) ब्राजील (द) फ्रांस

3. इनमें से कौन-सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है?
(अ) बिम्बलडन
(ब) यूएस ओपन
(स) ऑस्ट्रेलियन ओपन
(द) फ्रेंच ओपन

4. वर्ष 2024 में आईपीएल में कितनी टीम हिस्सा लेंगी?
(अ) 6 (ब) 8
(स) 10 (द) 12

5. वर्ष 2023 में किस क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता था?
(अ) लिवरपूल
(ब) मैनचेस्टर यूनाइटेड
(स) चेल्सी
(द) मैनचेस्टर सिटी

6. हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुशीला चानु किस खेल की खिलाड़ी हैं?
(अ) हॉकी (ब) मुक्केबाजी
(स) तीरंदाजी (द) गोल्फ

7. इनमें से किस बल्लेबाज के नाम सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने का रिकॉर्ड है?
(अ) सचिन तेंदुलकर
(ब) मोहम्मद अशरफुल
(स) इमरान नजीर
(द) ब्रायन लारा

8. इस वर्ष फॉर्मूला-वन सत्र की पहली रेस किस देश में आयोजित होगी?
(अ) बहरीन (ब) सऊदी अरब
(स) इटली (द) अजरबैजान

9. भारत ने कितनी बार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्डकप जीता है?
(अ) एक बार (ब) दो बार
(स) चार बार (द) पांच बार

10. वर्ष 2023 में जूनियर मुक्केबाजी विश्व चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी?
(अ) अजरबैजान (ब) सर्बिया
(स) आर्मेनिया (द) क्यूबा

11. इस वर्ष खेले जाने वाले आईसीसी ट्वेंटी-20 वर्ल्डकप में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी?
(अ) 12 (ब) 14
(स) 16 (द) 20

12. यूरोपा लीग किस खेल से संबंधित एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है?
(अ) टेनिस (ब) फुटबॉल
(स) रग्बी (द) बास्केटबॉल

13. कनाडा की महिला खिलाड़ी ब्रूक हेंडरसन किस खेल से संबंधित हैं?
(अ) गोल्फ (ब) टेनिस
(स) आइस हॉकी (द) बास्केटबॉल

14. वर्ष 2023 में किस रेसर ने फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप जीती है?
(अ) मैक्स वर्स्टापेन
(ब) लुईस हैमिल्टन
(स) चार्ल्स लेकलर्क
(द) सर्जियो पेरेज

15. वर्ष 2025 में वर्ल्ड एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी?
(अ) हंगरी (ब) जापान
(स) आयरलैंड (द) मैक्सिको

16. इनमें से कौन-सा खेल विंटर ओलिंपिक का हिस्सा नहीं है?
(अ) ल्यूज (ब) स्कीइंग
(स) गोल्फ (द) आइस हॉकी

17. किस देश के नाम सबसे ज्यादा बार सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है?
(अ) दक्षिण कोरिया
(ब) डेनमार्क
(स) मलेशिया
(द) चीन

18. सुनील छेत्री को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है?
(अ) वर्ष 2019 (ब) वर्ष 2020
(स) वर्ष 2021 (द) वर्ष 2023

19. वर्ष 2023 में किस देश ने फीबा बास्केटबॉल वर्ल्डकप जीता था?
(अ) अमेरिका (ब) जर्मनी
(स) कनाडा (द) सर्बिया

20. इंग्लैंड के फुटबॉलर काइल वॉकर किस क्लब के लिए खेलते हैं?
(अ) मैनचेस्टर सिटी
(ब) मैनचेस्टर यूनाइटेड
(स) टॉटनहम हाटस्पर
(द) आर्सेनल

21. टोक्यो ओलिंपिक में किस देश ने हॉकी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है?
(अ) भारत (ब) जर्मनी
(स) ऑस्ट्रेलिया (द) बेल्जियम

22. इनमें से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने एक कैलेंडर वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं?
(अ) सेरेना विलियम्स
(ब) मार्टिना हिंगिस
(स) स्टेफी ग्राफ
(द) इनमें से कोई नहीं

23. भारत में खेली जाने वाली प्रतियोगिता कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
(अ) हॉकी
(ब) क्रिकेट
(स) एथेलेटिक्स
(द) इनमें से कोई नहीं

24. वर्ष 2026 में किस देश में एशियन गेम्स आयोजित किया जाना प्रस्तावित है?
(अ) जापान (ब) इंडोनेशिया
(स) कतर (द) कजाकिस्तान

25. फॉर्मूला वन रेसर सर्जियो पेरेज किस देश के खिलाड़ी हैं?
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) अमेरिका
(स) ब्रिटेन (द) मैक्सिको

उत्तर

1. (ब), 2. (अ), 3. (द), 4. (स), 5. (द), 6. (अ), 7. (ब), 8. (अ), 9. (द), 10. (स), 11. (द), 12. (ब), 13. (अ), 14. (अ), 15. (ब), 16. (स), 17. (द), 18. (स), 19. (ब), 20. (अ), 21. (द), 22. (स), 23. (ब), 24. (अ), 25. (द)

- पुष्पेंद्र कुमार सविता

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवच ने गरीबों को दिया संबल

किसी भी बीमारी का एक ही इलाज है कि उसका इलाज करवाया जाये। लेकिन गरीबी की स्थिति में इलाज करवाना बड़ी चुनौती है। गरीब व्यक्ति के लिए उपचार का खर्च वहन करना बहुत मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हर गरीब की पीड़ा को महसूस किया और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। योजना का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का मुफ्त इलाज करवाना। इस योजना से देश के हर निर्धन का इलाज संभव हुआ है।

आयुष्मान भारत योजना विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवच है। इस योजना ने हर वर्ग, हर श्रेणी के लोगों के स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित किया है। गरीबों के लिए यह बड़ा संबल है। इससे पहले गरीब जब बीमार होता था तो उसे दोहरी मार पड़ती थी, एक तो बीमारी की पीड़ा, दूसरा किसी से उधार लेकर जैसे-तैसे इलाज करवा भी लिया तो वह कर्ज के बोझ से परेशान रहता था। यह बोझ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों दबाव का कारण बनता था। इन परिस्थितियों में विकास की परिकल्पना मुश्किल थी। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब को इस दबाव से मुक्त किया है। अब वह स्वस्थ जीवन के साथ विकास की संभावनाओं से अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है।

आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गयी। आयुष्मान भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अंतर्गत पूरे देश में स्वास्थ्य अधोसंरचना निर्माण और विकास के लिये कार्य किये जा रहे हैं। यह मिशन देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। इस योजना के दूसरे घटक द्वारा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ा जा रहा है।

क्या लाभ मिलता है योजना में

इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारक हितग्राही को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा है। इसमें दवाईयां और उपचार में शामिल सभी व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। योजना के हितग्राही शासकीय के अतिरिक्त सूचीबद्ध किसी भी निजी अस्पताल में निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं।

किसे प्राप्त हो सकता है योजना का लाभ

इस योजना में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना में चिन्हित वंचित श्रेणी के परिवार, खाद्य सुरक्षा में प्रदाय पात्रता पर्चीधारी एवं असंगठित श्रेणी के मजदूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्थिति

मध्यप्रदेश में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर्चीधारकों, मुख्यमंत्री संबल योजना के हितग्राहियों, मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल में सम्मिलित परिवारों एवं भोपाल गैस पीड़ित परिवार को योजना की पात्रता प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को भी प्रतिवर्ष, प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं की अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण मानव संसाधन आपूर्ति, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध दवाओं की संख्या में वृद्धि, जांच सेवाओं में वृद्धि, चिकित्सकीय परिवहन तंत्र विकास, कीमोथैरेपी और डायलिसिस जैसी सुविधाओं के विकास के कार्य किये जा रहे हैं।

प्रदेश में इस योजना के पात्र परिवारों की संख्या 1.08 करोड़ है। कुल हितग्राही 4 करोड़ 70 लाख हैं, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 64 प्रतिशत हैं। राज्य में अभी तक 3.76 करोड़ से अधिक हितग्राहियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 1 करोड़ से अधिक पी.वी.सी. कार्ड तैयार किये जा चुके हैं। 99 प्रतिशत से ज्यादा पात्र परिवारों में कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है।

आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर

आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर अंतर्गत प्रदेश में 11 हजार 812 आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर क्रियाशील हैं। इन केन्द्रों में वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ 1 लाख 84 हजार 737 व्यक्तियों को उपचार एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं तथा 1 लाख, 47 हजार 476 व्यक्तियों को वेलनेस सेवाएं प्रदान की गई हैं। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर केन्द्र की 104 प्रतिशत क्रियाशील करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आईडी बनाने के लिए दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 में आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर केन्द्रों के माध्यम से अधिकतम संख्या में टी.बी. रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ।

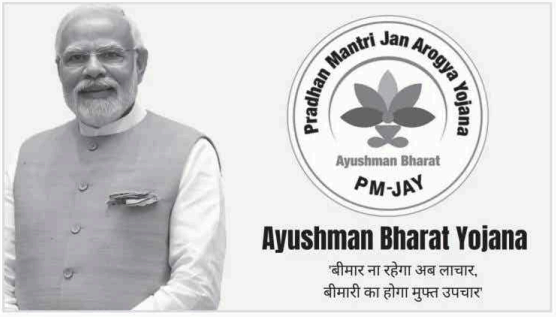

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

किडनी की गंभीर बीमारी से जूझते गरीबों के लिए डायलिसिस के सेशन करवाना बहुत मुश्किल होता है, बीमारी की एक स्टेज के बाद नियमित समयावधि में निरंतर डायलिसिस करवाना आवश्यक है जो काफी महंगा होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझते गरीबों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू किया। इसमें गरीबों को निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यदि हम मध्यप्रदेश की स्थिति देखें तो प्रदेश के 52 जिलों में 62 हेमोडायलिसिस इकाईयां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कुल 329 डायलिसिस मशीनें चालू हैं।

विगत एक वर्ष में लगभग 2 हजार 537 मरीजों का पंजीकरण किया गया और लगभग 88 हजार 394 डायलिसिस के सत्र आयोजित किये गए हैं। प्रतिदिन 40 सत्र आयोजित किये जा रहे हैं।

दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद 'निरामयम'

आयुष्मान भारत मिशन योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत, दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद का पंजीयन 07 जुलाई, 2018 को किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/34127/18 है । यह परिषद स्टेट हेल्थ एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। जिसके अंतर्गत इस योजना का सम्पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है। दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद निरामयम के वर्तमान में संचालन हेतु आई.ई.सी. ब्यूरो, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद में 3 काउंसिल का गठन किया गया है, जिसमें सलाहकार परिषद, गवर्निंग परिषद तथा कार्यकारी परिषद शामिल हैं।

जिला क्रियान्वयन इकाई

आयुष्मान भारत के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत शासन के निर्देशानुसार जिला क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है जिसमें जिला कलेक्टर - अध्यक्ष, जिला मलेरिया अधिकारी-जिला नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर-जिला संसूचना प्रणाली प्रबंधक, जिला मीडिया अधिकारी- जन शिकायत निवारण प्रबंधक, जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर - जिला कार्यक्रम सह-समन्वयक शामिल हैं।

इम्पेनलमेंट प्रक्रिया

इम्पेनलमेंट के लिए संचालक अस्पताल प्रशासन की अध्यक्षता में पैनल स्वीकृति बोर्ड का गठन किया गया है । समस्त शासकीय चिकित्सालयों, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, निजी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों आदि के इस योजना में इम्पेनलमेंट, पंजीयन संबंधी कार्यवाही भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ऑनलाइन संपादित की जाती है और पैनल प्रक्रिया का निर्धारण होता है।

निजी अस्पतालों के लिए मापदण्डों में राष्ट्रीय अस्पताल मानकीकरण बोर्ड, सम्बद्धता, न्यूनतम 10 बिस्तर, नर्सिंग होम, नियम 1972 का अनुपालन, सुपर स्पेशलिटी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा जारी सभी प्रासंगिक मानदंड शामिल हैं।

इलाज हेतु नियत पैकेज

किसी व्यक्ति के इलाज पर अस्पताल मनमाने तरीके से वसूली न कर सके और लागत पर नियंत्रण रखा जा सके इसके लिए इलाज संबंधी पैकेज रेट तय किए गए हैं। ये पैकेज रेट शासन द्वारा तय किये गये हैं। आयुष्मान भारत योजना की प्रस्तावित दरों में इलाज संबंधी सभी तरह के (दवाई, जांच, ट्रांसपोर्ट, इलाज पूर्व, इलाज पश्चात के खर्चे) व्यय शामिल हैं। जिसमें 23 स्पेशियलिटीज के कुल 1350 पैकेज शासकीय चिकित्सालय हेतु 472 आरक्षित पैकेज, साथ ही अतिरिक्त पैकेज की सुविधा और 10 दिन का फॉलोअप भी शामिल है।

क्लेम का भुगतान

शासकीय एवं निजी चिकित्सालय उपचार समाप्त होने के 10 दिवस के अंदर आवश्यक अभिलेखों एवं जांच रिपोर्टों सहित इम्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी को प्रस्तुत करेंगे एवं इम्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त सभी क्लेम का 15 दिवस के अंदर परीक्षण किया जाकर अपनी अंतिम अनुशंसा सहित स्टेट हेल्थ सोसायटी अर्थात 'दीनदयाल स्वाथ्य सुरक्षा परिषद-निरामयम' को प्रस्तुत किया जाता है। परिषद द्वारा 05 दिवस के अंदर संबंधित चिकित्सालयों को ऑनलाइन माध्यम से उनके बैंक खातों में क्लेम का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार क्लेम संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया 30 (तीस) दिवस में पूर्ण होती है।

हेल्प डेस्क

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन से संबंधित समस्त चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क बनाया गया है जिससे कि योजना में शामिल लाभार्थी परिवारों को एक ही स्थान पर समस्त जानकारी प्राप्त हो सके एवं उन्हें उपचार प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही के पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। इसके लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के परिणामस्वरूप हितग्राही आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आयुष्मान कार्ड बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

आयुष्मान कार्ड एप

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए आयुष्मान ऐप लॉन्च किया गया है। एप में स्व-सत्यापन की सुविधा है। एंड्राइड मोबाइल फोन का उपयोग करके सरल 4 चरणों में आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। हितग्राही को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति मदद कर सकता है। आयुष्मान एप के माध्यम से जनभागीदारी को सक्षम बनाया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना में अब तक 53 करोड़ लोगों के डिजिटल हेल्थ आई.डी. कार्ड जारी किये गये हैं। यह योजना देश के गरीब तथा पात्र हितग्राही के स्वस्थ जीवन की गारंटी को सुनिश्चित करती है। सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति का समय पर इलाज हो, वह स्वस्थ रहे। देश का हर नागरिक जब स्वस्थ रहेगा तभी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वस्थ आत्मनिर्भर भारत निर्माण का संकल्प पूर्ण होगा।

- देवेन्द्र गोरे
(लेखक, समसामयिक विषयों पर लेखन करते हैं।)

पीएम मित्र पार्क के लिये बनेगा स्पेशल पर्पज व्हीकल

नई दिल्ली, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल से सौजन्य भेंट कर उनके मंत्रालयों से संबंधित प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान धार स्थित पीएम मित्र पार्क, साड़ी वॉकैथन का आयोजन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रस्ताव, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जनजातीय महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रबी उपार्जन जैसे विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा धार स्थित पीएम मित्र पार्क के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने और भूमि स्थानांतरित करने जैसी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, और पीएम मित्र पार्क प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों से भूमिपूजन के लिए तैयार है।

डॉ. यादव ने श्री गोयल से प्रदेश में साड़ी वॉकैथन के आयोजन में सहयोग दिए जाने का अनुरोध किया जिससे प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी और बाग प्रिंट्स जैसे हैंडलूम उत्पादों का व्यापक प्रचार हो सके। केंद्रीय मंत्री ने कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रदेश शासन को साड़ी वॉकैथन के आयोजन के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण प्रस्तावों की रूपरेखा केंद्रीय मंत्री के सामने रखी।

व्यावसायिक शिक्षा में हो भारतीय ज्ञान

भोपाल, भारतीय पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग एवं व्यावसायिक पद्धति के साथ नवीन आयाम देने की आवश्यकता है। गांव के कारीगरों के पास परंपरागत प्रतिभा है, लेकिन तकनीक तथा व्यावसायिक कौशल के अभाव में काम की तुलना में उनकी आमदनी कम होती है। उन कारीगरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कार्य में तकनीक को शामिल करें, जिससे वे अपनी पारंपरिक प्रतिभा के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकें। ये बातें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने 'व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य एवं प्रथाएं' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर कही।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, केवल अध्यापन तक सीमित न होकर मानव जीवन को बेहतर बनाने की दिशामूलक हो जिससे लोगों की प्रगति और जीविकोपार्जन के लिए बेहतर स्रोत उपलब्ध हो सकें।

एम.पी. पी.एस.सी. प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न

विज्ञान एवं पर्यावरण

प्र. 1 मिजोरम में स्थित फौंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
(अ) काला पर्वत उद्यान
(ब) नीला पर्वत उद्यान
(स) पीला पर्वत उद्यान
(द) मिजोहिल्स उद्यान
उत्तर- (ब)

प्र. 2 वाटर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है?
(अ) राजेन्द्र सिंह
(ब) सलीम अली
(स) एम.एस. स्वामीनाथन
(द) वंगारी मथाई
उत्तर- (अ)

प्र. 3 निम्न में से कौन-सा एक सुमेलित नहीं है?
(अ) आंशी राष्ट्रीय उद्यान - कर्नाटक
(ब) बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान - मेघालय
(स) चंदोली राष्ट्रीय उद्यान - गुजरात
(द) हेमिस राष्ट्रीय उद्यान - लद्दाख
उत्तर- (स)

प्र. 4 भारत में आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है?
(अ) जाधव पायेंग
(ब) चेवांग नॉरफेल
(स) राजेन्द्र सिंह
(द) सलीम अली
उत्तर- (ब)

प्र. 5 मध्यप्रदेश में कुल कितने टाईगर रिज़र्व हैं?
(अ) 6 (ब) 7
(स) 8 (द) 5
उत्तर- (7)

प्र. 6 बन्नी घास के मैदान पाये जाते हैं?
(अ) कच्छ गुजरात में
(ब) कश्मीर घाटी में
(स) पश्चिमी घाट में
(द) पूर्वी हिमालय में
उत्तर- (अ)

प्र. 7 प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारम्भ किया गया?
(अ) 1972-73 (ब) 1975-76
(स) 1979-80 (द) 1982-83
उत्तर- (अ)

प्र. 8 मेघा पाटकर का सम्बंध किस आन्दोलन से है?
(अ) साईलेंट घाटी आन्दोलन
(ब) जंगल बचाओ आन्दोलन
(स) नर्मदा बचाओ आन्दोलन
(द) विश्नोई आन्दोलन
उत्तर- (स)

प्र. 9 ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है?
(अ) मॉट्रियल (ब) स्टॉकहोम
(स) रामसर (द) जिनेवा
उत्तर- (अ)

प्र. 10 वर्ष 1992 में प्रथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था?
(अ) ब्राजील (ब) भारत
(स) ऑस्ट्रिया (द) स्वीडन
उत्तर- (अ)

प्र. 11 वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता होता है?
(अ) A.D.R.I. (ब) C.I.T.E.S.
(स) रामसर (द) UNEP
उत्तर- (ब)

प्र. 12 भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र शांत घाटी किस राज्य में है?
(अ) केरल
(ब) प. बंगाल
(स) उत्तराखंड
(द) हिमाचल प्रदेश
उत्तर- (अ)

प्र. 13 विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस रेखा पर पायी जाती है?
(अ) भू-मध्य (ब) कर्क
(स) मकर (द) आर्कटिक
उत्तर- (अ)

प्र. 14 कौन सा सम्मेलन पारा (मर्करी) धातु के प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है?
(अ) मॉट्रियल (ब) मिनामाता
(स) क्योटो (द) कार्टाजेना
उत्तर- (ब)

प्र. 15 जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है?
(अ) एडवर्ड ओ. विल्सन
(ब) डार्विन
(स) हरगोविंद खुराना
(द) लैमार्क
उत्तर- (अ)

प्र. 16 अमृता देवी का सम्बंध किस आन्दोलन से है?
(अ) साईलेंट वेली आन्दोलन
(ब) पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन
(स) नर्मदा बचाओ आन्दोलन
(द) विश्नोई आंदोलन
उत्तर- (द)

प्र. 17 जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लाया गया?
(अ) 2000 (ब) 2001
(स) 2002 (द) 2003
उत्तर- (स)

प्र. 18 जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है?
(अ) 2003 चेन्नई में
(ब) 2003 बेंगलुरु में
(स) 2003 हैदराबाद में
(द) 2003 केरल में
उत्तर- (अ)

प्र. 19 कौन-सी ड्रग गिद्धों की जनसंख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है?
(अ) एस्पिरिन
(ब) क्लोरोक्विन
(स) डाइक्लोफेनाक
(द) पेनिसिलिन
उत्तर- (स)

प्र. 20 भारत में सबसे अधिक जैवविविधता सम्पन्न क्षेत्र है?
(अ) गंगा का मैदान
(ब) ट्रांस हिमालय
(स) पश्चिमी घाट
(द) मध्यभारत
उत्तर- (स)

प्र. 21 जैव विविधता शब्द की रचना किसने कि थी?
(अ) बी.पी. सिंह
(ब) कार्ल मोविअस
(स) ए.जी. टेंसले
(द) वाल्टर जी. रोसेन
उत्तर- (द)

प्र. 22 टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(अ) वंदना शिवा
(ब) आदर्श कुमार गोयल
(स) एम.एस. स्वामीनाथन
(द) मेघा पाटेकर
उत्तर- (अ)

प्र. 23 ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी?
(अ) सी.सी. पार्क ने
(ब) जे. एन. एन. जेसर्फ ने
(स) जोसेफ फोरियर ने
(द) एल. जाप्लर ने
उत्तर- (स)

प्र. 24 ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
(अ) गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना
(ब) अम्लीय वर्षा
(स) ओजोन परत से छिद्र होना
(द) वैश्विक ताप में कमी
उत्तर- (अ)

प्र. 25 कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ?
(अ) क्योटो प्रोटोकाल
(ब) अर्थ शिखर सम्मेलन
(स) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
(द) जी. 8 शिखर सम्मेलन
उत्तर- (अ)

प्र. 26 बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है?
(अ) उत्तरप्रदेश (ब) महाराष्ट्र
(स) झारखंड (द) बिहार
उत्तर- (स)

प्र. 27 यलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है?
(अ) कनाडा (ब) द. अफ्रिका
(स) श्रीलंका (द) यू.एस.ए.
उत्तर- (द)

प्र. 28 नीलगिरी की मेघ बकरियां (तारह) कहां पाई जाती है?
(अ) इरविकलमा राष्ट्रीय उद्यान में
(ब) मन्नार की खाड़ी में
(स) पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में
(द) बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में
उत्तर- (अ)

प्र. 29 शुक्लाफांटा वन्य जीव अभ्यारण स्थित है?
(अ) भूटान (ब) म्यानमार
(स) नेपाल (द) श्रीलंका
उत्तर- (स)

प्र. 30 राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण किस राज्य का हिस्सा नहीं है?
(अ) उत्तरप्रदेश (ब) मध्यप्रदेश
(स) राजस्थान (द) हरियाणा
उत्तर- (द)

प्र. 31 ब्लू मारमॉन तितली को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है?
(अ) महाराष्ट्र
(ब) छत्तीसगढ़
(स) अरुणाचल प्रदेश
(द) हिमाचल प्रदेश
उत्तर- (अ)

प्र. 32 निम्नलिखित में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है?
(अ) जिम कार्बेट
(ब) रणथम्बौर
(स) नागार्जुन सागर श्रीशैलम
(द) सुन्दरवन
उत्तर- (स)

प्र. 33 विश्व का सबसे बड़ा रॉयल वानस्पतिक उधान स्थित है?
(अ) क्यू - इग्लैण्ड में
(ब) पेसिर - फ्रांस में
(स) हावड़ा - भारत में
(द) टोक्यो - जापान में
उत्तर- (अ)

प्र. 34 पांच इंद्रियों का बाग (दि गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस) स्थित है?
(अ) डल झील कश्मीर के समीप
(ब) दिल्ली के मेहरौली में
(स) शांत घाटी केरल में
(द) नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में
उत्तर- (ब)

प्र. 35 भारत में मॉंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है?
(अ) केवलादेव राष्ट्रीय उधान
(ब) भोजताल झील
(स) यशवंत सागर
(द) जिम कार्बेट राष्ट्रीय उधान
उत्तर- (अ)

प्र. 36 रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया?
(अ) 1965 (ब) 1967
(स) 1970 (द) 1971
उत्तर- (द)

प्र. 37 इनमें से कौन-सा लैंटिक इकों सिस्टम है?
(अ) नदी (ब) झरना
(स) तालाब (द) जल प्रपात
उत्तर- (स)

प्र. 38 मध्यप्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट कौन-सी है?
(अ) भोजताल
(ब) यशवंत सागर
(स) साख्य सागर
(द) सिरपुर तालाब
उत्तर- (द)

प्र. 39 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में किस सम्मेलन के फलस्वरूप हुई थी?
(अ) वियना (ब) स्टॉकहोम
(स) रामसर (द) जिनेवा
उत्तर- (ब)

प्र. 40 कार्बेट टाइगर रिज़र्व किस भारतीय राज्य में स्थित है?
(अ) राजस्थान (ब) मध्यप्रदेश
(स) उत्तराखंड (द) महाराष्ट्र
उत्तर- (स)

प्र. 41 पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है?
(अ) संरचना (ब) जीवोम
(स) जलवायु (द) उप-प्रणाली
उत्तर- (ब)

प्र. 42 लेंटाना घास के मैदान कहां पाये जाते हैं?
(अ) मैक्सिको
(ब) दक्षिण अफ्रीका
(स) ऑस्ट्रेलिया
(द) फ्रांस
उत्तर- (अ)

प्र. 43 पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं?
(अ) रासायनिक चक्र
(ब) जैव भू- रासायनिक चक्र
(स) भू- वैज्ञानिक चक्र
(द) भू- रासायनिक चक्र
उत्तर- (ब)

प्र. 44 एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में उर्जा का प्रवाह होता है?
(अ) 10 प्रतिशत
(ब) 20 प्रतिशत
(स) 30 प्रतिशत
(द) 40 प्रतिशत
उत्तर- (अ)

प्र. 45 इनमें से कौन-सा अपघटक नहीं है?
(अ) जीवाणु (ब) कवक
(स) विषाणु (द) सूक्ष्मजीव
उत्तर- (स)

प्र. 46 सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन-सा है?
(अ) मरुस्थल (ब) पर्वत
(स) महासागर (द) वन
उत्तर- (स)

प्र. 47 दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है?
(अ) इकोटाइप
(ब) इकेड
(स) इकोस्फीयर
(द) इकोटोन
उत्तर- (द)

प्र. 48 इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रतिपादित किया था?
(अ) सलीम अली
(ब) सुनीता नारायण
(स) ए.जी. टेन्सले
(द) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (स)

- इमरतलाल खरते
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करते हैं।)

मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादों के निर्यात में मिली बड़ी सफलता

भोपाल, कृषि प्र-संस्कृत खाद्य निर्यात प्राधिकरण (एपीडा) ने प्रदेश के कृषि निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। एपीडा के सहयोग से मध्यप्रदेश के एक्सपोर्टर द्वारा ओमान के लिये शुष्क सोयाबीन दूध पावडर की पहली खेप की गाड़ी को हरी-झण्डी दिखाकर शुक्रवार को रवाना किया गया। इस अवसर पर एपीडा के जनरल मैनेजर डॉ. वी.के. विद्यार्थी, एपीडा के बोर्ड मेम्बर श्री संतोष गोयल, एक्सपोर्टर मेसर्स बॉयोनाइट्रेंट्स प्रायवेट लिमिटेड भोपाल के प्रतिनिधि और इम्पोर्टर मेसर्स इंटरनेशनल टूरिज्म रेस्टॉरेंट कम्पनी ओमान के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एपीडा निर्यातकों को अपने उत्पाद विदेशों में निर्यात करने में आवश्यक सहयोग मुहैया कराता है। एपीडा की मध्यस्थता से ओमान के साथ बॉयोन्यूट्रेंट (इण्डिया) प्रायवेट लिमिटेड के मध्य दीर्घकालिक अनुबंध हुआ है, जिसमें एक निश्चित मात्रा में शुष्क सोयाबीन मिल्क पावडर नियमित रूप से ओमान भेजा जायेगा। इसका प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलेगा तथा कृषि उत्पादों के निर्यात की नई संभावनाओं का उदय होगा। एपीडा का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुसूचित उत्पादों को बढ़ावा देना है। एपीडा के प्रयासों से देश के विभिन्न राज्यों से कई नये उत्पाद विदेशों में सफलतापूर्वक निर्यात किये जा रहे हैं।

स्थानीय निकायों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जायेगा

इंदौर, मध्यप्रदेश में नगर निगमों सहित अन्य स्थानीय निकायों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जायेगा। इससे विकास को नई गति और नई दिशा मिलेगी। स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के भी प्रयास किये जाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में नगर निगम के नवनिर्मित परिषद सभागृह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम के निर्माणाधीन भवन के कार्य को पूर्ण करने के लिये 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर शहरवासियों का सौभाग्य है कि उनका शहर दो ज्योतिर्लिंगों के मध्य स्थित है। इंदौर में अहिल्या माता जैसी कुशल प्रशासक रही हैं। उन्होंने इंदौर के विकास में अहिल्या माता तथा होल्कर वंश द्वारा दिये गये योगदान का उल्लेख भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्या माता का इंदौर के विकास में विशेष योगदान है। माता अहिल्या अन्य शहरों और धर्मस्थलों में भी विशेष विकास कार्य करवाये हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिये। डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर नगर निगम के नवनिर्मित परिषद सभागृह का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखना गौरव की बात है।

कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में नगर निगम द्वारा अत्याधुनिक सुर्वसुविधायुक्त सुंदर सदन का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन में सकारात्मक चर्चा हो। सभी जनप्रतिनिधि पूर्ण अध्ययन के साथ चर्चा में भाग लें। तथ्यों के साथ अपनी बात को रखें। पार्षदों को अध्ययनशील बनना चाहिये। पार्षद, विधायिका की पहली सीढ़ी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे पदों का निर्वहन पूर्ण मेहनत के साथ करें।

मध्यप्रदेश में तुअर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश में तुअर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार का प्रोत्साहन मिलने से प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

प्रतिनिधिमंडल में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रो. विजय पॉल शर्मा तथा आयोग के सदस्य डॉ. नवीन पी सिंह, श्री अनुपम मित्रा और श्री रतन लाल डागा शामिल थे।

तालाबों और जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया जाएगा - मुख्यमंत्री

इंदौर, तालाबों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए प्रदेश में जनभागीदारी से गतिविधियों को अभियान का रूप दिया जाएगा। इंदौर के तालाबों के साथ-साथ प्रदेश के अन्य वेटलैंड क्षेत्रों को रामसर साइट के रूप में घोषित कराने का प्रयास किया जाएगा। विश्व के सभी देशों में केवल भारत में ही देश को माता स्वरूप माना जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम् का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि संपूर्ण वसुधा हमारे लिए कुटुम्ब के समान है। हमारी संस्कृति में सभी प्रकार के जीव-जंतु, नदी-पहाड़-पर्वत में ईश्वर का स्वरूप माना गया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व वेटलैंड दिवस 2024 पर इंदौर के रामसर साइट सिरपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि काल के प्रवाह में आई विसंगतियों के परिणामस्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हुए। इंदौर में 300 साल पहले निर्मित हुआ सिरपुर तालाब पेयजल की आपूर्ति करता था। बदली जीवनशैली के परिणामस्वरूप घरों से निकलने वाले वेस्ट वॉटर के कारण हमारे कई जल स्त्रोत प्रदूषित हुए हैं। परिणामस्वरूप केवल जल ही नहीं खराब हुआ, अपितु सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आया है, पेड़-पौधे-पक्षी प्रभावित हुए हैं। इस परिस्थिति में इन जल स्त्रोतों को बचाने की बहुत आवश्यकता है। यशवंत सागर, रामसर साइट पहले से ही था और सिरपुर भी रामसर साइट बना है। अब इंदौर को रामसर सिटी बनाने की बात स्वागत और बधाई योग्य है।

डॉ. यादव ने कहा कि जल स्त्रोतों में परस्पर संबंध होने के परिणामस्वरूप इंदौर के तालाबों की परिस्थिति में सुधार से क्षिप्रा नदी में भी सुधार आएगा। जल का बढ़ता दुरुपयोग हम सभी के लिए चिंता का विषय है। इसमें सुधार के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वित रूप से कार्ययोजना बनाकर समाज को साथ लेते हुए इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुओं, तालाबों और जल स्त्रोतों का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा भाव हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं और यह हमारे संस्कार से जुड़े हैं। उनकी बर्बादी के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, लेकिन अब जल स्त्रोतों के संरक्षण और उन्हें साफ-सुथरा रखने के लिए समाज में जागरूकता आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में हुए कार्यों से लोगों की सोच बदली है। जल स्त्रोतों के संरक्षण में जनभागीदारी को निरंतर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

रामसर सचिवालय की महासचिव डॉ. मुसोंदा मुम्बाशा ने कहा कि भारत में 1982 में मात्र दो रामसर साइट्स थीं, जो अब बढ़कर 80 हो गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जल संरक्षण और जैव विविधता को बचाने के लिए जारी कार्य सराहनीय और प्रेरणास्पद हैं।

जनजातीय समाज के लिए संचालित अभियान और योजनाएं

जनजातीय समाज की अपनी क्षमता, मेधा और विशेषता होती है। स्वतंत्रता के लंबे समय तक जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग का उत्थान हो रहा है। हर परिवार का अपना घर हो, सभी को स्वच्छ पानी और भोजन मिले। सभी समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसके लिए हर गरीब और पात्र व्यक्ति को मुफ्त में घर, इलाज, शिक्षा और अनाज दिया जा रहा है। जनजातीय कल्याण सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए जनजातीय समुदायों को भी मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय के संस्कार, संस्कृति और परंपराओं को यथावत रखते हुए उनका समग्र विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 10 सालों में जनजातीय समुदाय के आर्थिक विकास में गति आई है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार के विशेष प्रयासों से अनुसूचित जनजातियों का विकास तथा सशक्तिकरण हो रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जनजातीय समूहों के इतिहास, मान्यताओं और संस्कृति में विशेष आस्था है। भगवान बिरसा मुंडा स्वत्व, स्वाभिमान, शौर्य, संघर्ष और स्वराज्य के प्रतीक हैं, वह जनजातियों और देश के गौरव हैं। इसलिए वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। यह दिन वीर, पराक्रमी और महान जनजातीय नायक बिरसा मुंडा को समर्पित किया गया है। इससे आने वाली पीढ़ियों को देश के लिये किए गए उनके बलिदान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इससे प्रेरित होकर वे भविष्य निर्माण के बेहतर लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना, लोक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, उनके शौर्य और भारतीय मूल्यों के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है।

पीएम जन-मन योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। फिर भी जनजातीय समुदाय में कुछ ऐसे समूह हैं, जो आज भी बुनियादी लाभों से वंचित हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे समुदायों का भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए पीएम जन-मन योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य 18 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समुचित विकास करना है। यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के सामाजिक आर्थिक संकेतकों में लगातार पिछड़ रहे हैं। इसके लिए 24 हजार 104 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

रियायती दर पर ऋण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनजातीय समुदायों के रोज़गार और स्वरोज़गार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोज़गार और अन्य कार्यों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) पात्र जनजातियों के व्यक्तियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत पिछले नौ साल के दौरान 8 लाख 71 हजार 101 लोगों ने लाभ प्राप्त किया है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना हर स्तर पर जनजातीय वर्ग का विकास करना है। इसके लिए सरकार जनजातीय बाहुल्य गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 4.22 करोड़ जनसंख्या (कुल आदिवासी जनसंख्या का करीब 40 प्रतिशत) वाले गांवों का कायापलट करना है। इसके तहत 2025-26 तक अधिसूचित जनजाति वाले राज्यों के कम से कम 50 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या और 500 एसटी वाले 36 हजार 428 गांवों को कवर किया जायेगा।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

जनजातीय वर्ग की आजीविका के अवसरों को बढ़ाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य एजेंडे में शामिल है। इसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय वर्ग के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) द्वारा इस मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल के समर्थन पर जोर दिया गया है।

एकलव्य आवासीय विद्यालय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि गरीब हो या अमीर, गांव का हो या शहर का, सभी को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में जनजातीय छात्रों को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। 2011 की जनगणना के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक एसटी और कम से कम 20 हजार जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। करीब 694 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से देशभर में लगभग 401 एकलव्य विद्यालय काम कर रहे हैं, इससे 1 लाख 18 हजार 982 छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।

समग्र शिक्षा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के स्तर पर लैंगिक और सामाजिक अंतर को भी कम किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर लैंगिक और सामाजिक अंतर को पाटना है। योजना के तहत पहचान किये गये विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें इन जिलों में स्कूलों में नामांकन, पढ़ाई में बने रहने और लैंगिक समानता के साथ-साथ एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों पर ध्यान देने जैसे विभिन्न संकेतकों के आधार पर प्रतिकूल प्रदर्शन पर भी गौर किया जाता है।

साक्षरता दर में सुधार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के 59 प्रतिशत से सुधरकर आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) की जुलाई 2021-जून 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 72.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2013-14 के 91.3 से बढ़कर 2021-2022 में 98.0 पर पहुंच गया, वहीं एसटी छात्रों के मामले में जीईआर सेकेंडरी स्तर (नौवीं-दसवीं) पर 2013-14 के 70.2 से बढ़कर 2021-2022 में 78.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्तर (11वीं - 12वीं) की पढ़ाई में एसटी छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 2013-14 के 35.4 से बढ़कर 2021-2022 में 52.0 पर पहुंच गया। उच्च शिक्षा की यदि बात की जाये तो एसटी छात्रों का जीईआर 2013-14 के 11.3 से बढ़कर 2020-2021 में 18.9 प्रतिशत हो गया है।

डीएपीएसटी कोष

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) लागू की गई है। केन्द्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 42 मंत्रालय और विभाग हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत डीएपीएसटी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवासन, विद्युतीकरण, रोज़गार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिये आवंटित कर रहे हैं। केन्द्रीय बजट 2023-24 में 42 मंत्रालयों तथा विभागों के कुल योजना बजट आवंटन में से 1 लाख 17 हजार 943.73 करोड़ रुपये डीएपीएसटी कोष के तौर पर आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा जनजाति समुदाय को कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) आदि योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है।

- निशा त्यागी

(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं)

ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने बोपन्ना

मेलबर्न, भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने टेनिस में इतिहास रच दिया है। बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ रोहन बोपन्ना टेनिस के इतिहास में ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।

बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी ने सेमीफाइनल में थॉमस माचाक और झांग झिंझेन की जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी का सामना सिमोन बोलेली और आंद्रिया वावासोरी की इटैलियन जोड़ी से हुआ। फाइनल मुकाबले का पहला सेट बेहद रोमांचक रहा। मैच का पहला सेट टाइब्रेकर तक गया। टाइब्रेकर में बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी ने 7-0 से बाजी जीती। इसके बाद दूसरे सेट में बोपन्ना और एब्डेन ने इटैलियन जोड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और 7-5 से सेट जीतकर खिताबी जीत दर्ज की।

ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने अपने नाम किया। सबालेंका ने चीन की झांग किनवेन को महिला एकल वर्ग में 6-3, 6-2 से हराकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता।

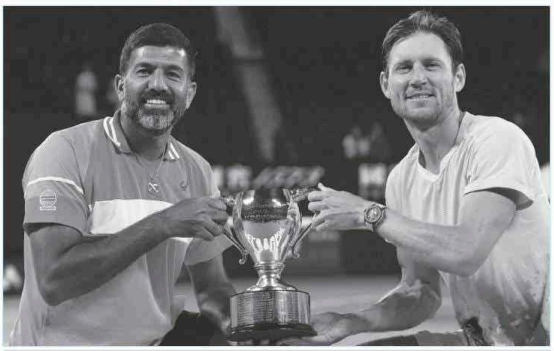

- रोहन बोपन्ना युगल ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं।
- बोपन्ना से पहले लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीता है।
- बोपन्ना इससे पहले वर्ष 2017 में कनाडा की गैब्रिएला दाब्रोवस्की के साथ फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल खिताब जीत चुके हैं।
- टेनिस की पुरुष युगल रैंकिंग में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी हैं बोपन्ना।

जेनिक सिनर ने जीता पहला ग्रैंड स्लैम खिताब

इटली के 22 वर्षीय खिलाड़ी जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन के नए चैम्पियन बन गए हैं। सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में रूस के डेनिल मेदवेदेव को 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। ये सिनर के कॅरियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। फाइनल मैच में मेदवेदेव ने शुरुआत में दो सेट जीतकर सिनर को दबाव में ला दिया। इसके बाद सिनर ने जबरदस्त वापसी की और अगले तीनों सेट 6-4 के अंतर से जीतकर खिताब अपने नाम किया।

वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 27 वर्ष बाद हराया

ब्रिस्बेन, युवा गेंदबाज शमार जोसफ के शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 27 वर्ष बाद टेस्ट क्रिकेट में मात दी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ब्रिस्बेन में खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच को वेस्टइंडीज ने 8 रन से जीता। मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 311 रन बनाये, इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम ने 9 विकेट पर 289 रन बनाकर पारी घोषित की। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 193 रन ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया को 216 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियन पारी को स्टीव स्मिथ (91) ने संभाला, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके। वेस्टइंडीज के लिए शमार जोसफ ने दूसरी पारी में 68 रन देकर 7 विकेट लिए। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने अब तक 12 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं, इनमें पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम को हार का सामना करना पड़ा है।

मंदीप ने मुक्केबाजी में जीता इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब

वाशिंगटन, भारतीय मुक्केबाज मंदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन में खेले गए इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल फाइट में अमेरिकी मुक्केबाज गेरार्डो एसक्विवेल को हराकर नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (एनबीए) का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब अपने नाम किया है। मंदीप यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। मंदीप के लिए यह मुकाबला आसान नहीं था। वे 75 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लेते थे, लेकिन इस मुकाबले के लिए उन्होंने पिछले छह महीने में अपना वजन कम किया और 59 किलोग्राम भारवर्ग में उतरे। मंदीप ने पेशेवर मुक्केबाजी में अब तक 6 फाइट लड़ी हैं और सभी जीती हैं।

एंटोनसेन ने जीता इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब

जकार्ता, डेनमार्क के अनुभवी शटलर एंडर्स एंटोनसेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैम्पियन बन गए हैं। एंटोनसेन ने टूर्नामेंट के फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को 18-21, 21-13, 21-18 से हराया। एंटोनसेन ने मैच में पहला गेम 18-21 से हारने के बाद जबरदस्त वापसी की और दूसरा गेम 21-13 से तथा तीसरा गेम 21-18 से जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया। एंटोनसेन वर्ष 2019 में भी यह खिताब जीत चुके हैं। टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब चीन की वांग झीयी ने जीता।

पहला टेस्ट मैच

इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से हराया

हैदराबाद, ओली पोप के शानदार शतक और स्पिनर टॉम हार्टले की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने भारत को पहले टेस्ट मैच में 28 रन से हराया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय स्पिनरों के सामने इंग्लिश बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आये। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अकेले संघर्ष करते हुए 70 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाये। पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। इसके बाद के.एल. राहुल (86) और रविंद्र जडेजा (87) ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने पहली पारी में 436 रन बनाये और 190 रनों की विशाल बढ़त हासिल की।

दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज लय में दिखे। जैक क्राउले (31) और बेन डकेट (47) ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। ओली पोप ने बेहतरीन पारी खेली और एक छोर पर टिके रहे और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर इंग्लैंड को 420 रन तक पहुंचाया। जीत के लिए मिले 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम अपने ही मैदान पर इंग्लैंड के अनुभवहीन स्पिनरों के सामने संघर्ष करती नजर आयी। भारत का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं बना सका, भारतीय टीम की पारी 202 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए स्पिनर टॉम हार्टले ने 7 विकेट लिए।

अक्षदीप ने 20 किलोमीटर रेस में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

चंडीगढ़, भारतीय एथलीट अक्षदीप सिंह ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल स्पर्धा में पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अक्षदीप सिंह ने स्पर्धा में एक घंटा 19 मिनट 38 सेकेंड का समय निकाला और स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले 20 किलोमीटर रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अक्षदीप के ही नाम था। अक्षदीप ने वर्ष 2023 में एक घंटा 19 मिनट और 55 सेकेंड में रेस पूरी कर पेरिस ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई किया था।

विष्णु सरवनन ने पेरिस ओलिंपिक में बनाई जगह

एडिलेड, एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता और सेलर (पाल नौकायन खिलाड़ी) विष्णु सरवनन ने इस वर्ष पेरिस में आयोजित होने वाले ओलिंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विष्णु लगातार दूसरी बार ओलिंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले सेलर बन गए हैं।

विराट कोहली बने

आईसीसी वन-डे प्लेयर ऑफ द ईयर

दुबई, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ वन-डे क्रिकेटर पुरस्कार से नवाजा है। कोहली ने आईसीसी वन-डे विश्वकप-2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। कोहली ने इस विश्वकप में 11 मैचों में 95.62 की शानदार औसत से 765 रन बनाये, इनमें 3 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं।

इसके अलावा कोहली के लिए वर्ष 2023 बेहद शानदार रहा है। कोहली ने वर्ष 2023 में वन-डे क्रिकेट में इतिहास रचा। कोहली ने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा (49) शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा और अपना 50वां वन-डे शतक लगाया। विराट कोहली ने अब तक 292 वन-डे मैच खेले हैं। इन मैचों में कोहली ने 13848 रन बनाये हैं। इसके अलावा कोहली ने टेस्ट और ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है।

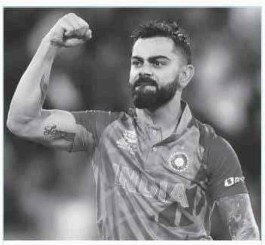

- कोहली ने चौथी बार जीता है आईसीसी वन-डे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार।
- कोहली इससे पहले वर्ष 2012, 2017 और 2018 में वन-डे प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं।
- कोहली तीन बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर और एक बार टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन चुके हैं।

हॉकी 5 एस विश्वकप

नीदरलैंड्स बना हॉकी के छोटे प्रारूप का चैम्पियन

मस्कट, नीदरलैंड्स की महिला हॉकी टीम हॉकी के सबसे छोटे और रोमांचक प्रारूप हॉकी 5 एस की पहली चैम्पियन बन गई है। नीदरलैंड्स ने ओमान में खेले गए एफआईएच हॉकी 5 एस महिला विश्वकप का खिताब अपने नाम किया। नीदरलैंड्स टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को 7-2 से हराकर विश्व चैम्पियन बना।

फाइनल मैच में नीदरलैंड्स की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। नीदरलैंड्स के लिए वान डि वेन , वान डर वेल्ड और लाना केल्स ने दो-दो तथा सोशा बेनिंगा ने एक गोल किया, वहीं भारत के लिए ज्योति छेत्री और रुतुजा पिसल ने एक-एक गोल किया। मैच में नीदरलैंड्स की टीम पूरे समय हावी रही। हॉफ टाइम तक नीदरलैंड्स ने 6 गोल दागे जबकि भारतीय टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। दूसरे हॉफ में भारतीय टीम ने बेहतर खेल दिखाया लेकिन नीदरलैंड्स को हराने में सफल नहीं हो सकी।

- एफआईएच ने पहली बार किया है हॉकी 5 एस विश्वकप का आयोजन।
- नीदरलैंड्स ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में जीता है यह विश्वकप।
- 5 एस हॉकी का नवीनतम और छोटा फॉर्मेट है।
- 5 एस प्रारूप में प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं।
- इस प्रारूप में 15-15 मिनट के दो हाफ होते हैं।

भारतीय पुरुष टीम भी हुई बाहर

एफआईएच हॉकी 5 एस विश्वकप में भारतीय पुरुष टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष टीम को नीदरलैंड्स के हाथों 7-4 से हार का सामना करना पड़ा। मैच में पहला गोल भारत के मोहम्मद राहील ने किया, लेकिन भारतीय टीम अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख पाई। नीदरलैंड्स ने जबरदस्त पलटवार किया और जीत दर्ज की। इसके बाद नीदरलैंड्स की टीम ने फाइनल में मलेशिया को 5-2 से हराकर हॉकी 5 एस विश्वकप भी जीता। भारतीय पुरुष टीम इस विश्वकप में पांचवें स्थान पर रही।

जय शाह तीसरी बार बने | एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष

बाली, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह को लगातार तीसरी बार एशियन क्रिकेट परिषद (एसीसी) का अध्यक्ष चुना गया है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित एसीसी की वार्षिक महासभा में जय शाह को तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शमी सिल्वा ने एसीसी की बैठक में जय शाह के कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव रखा। इसके बाद एसीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से शाह के नामांकन का समर्थन किया। जय शाह सबसे पहले जनवरी 2021 में एसीसी के अध्यक्ष बने थे। तब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह ली थी। जय की अगुवाई में एसीसी ने वर्ष 2022 में ट्वेंटी-20 प्रारूप में और वर्ष 2023 में वन-डे प्रारूप में एशिया कप का सफल आयोजन किया था।

बैठक में जय शाह ने आभार जताते हुए कहा कि मैं एसीसी बोर्ड का मुझ पर विश्वास बनाये रखने के लिए आभारी हूं। एसीसी पूरे एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

केंद्र ने सोलहवें वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त किया

भारत सरकार ने सोलहवें वित्त आयोग का गठन 31.12.2023 को किया था और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी से आयोग के सदस्य नियुक्त किये गये हैं। आयोग में श्री अजय नारायण झा, पूर्व सदस्य, 15वां वित्त आयोग एवं पूर्व सचिव, व्यय, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, पूर्व विशेष सचिव, व्यय, डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अर्थ ग्लोबल और डॉ. सौम्य कांति घोष, भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है।

अंटार्कटिका में वायरस, पेंग्विन की मौत पर वैज्ञानिक अलर्ट

अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित साउथ जॉर्जिया द्वीप में एक किंग पेंग्विन की मौत हुई है। ऐसी आशंका है कि पेंग्विन की मौत बर्ड फ्लू वायरस से हुए संक्रमण से हुई है। अगर वायरस से मौत की पुष्टि होती है तो यह पहली बार होगा, जब किंग प्रजाति की पेंग्विन की बर्ड फ्लू से मौत हुई है। अंटार्कटिका में पेंग्विन की एच5एन1 वायरस से मौत की आशंका से वैज्ञानिकों ने गहरी चिंता जताई है। वैज्ञानिकों को डर है कि अभी पेंग्विंस का ब्रीडिंग का सीजन है। ऐसे में अगर पेंग्विन में बर्ड फ्लू फैला तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती समारोह

आज की आर्थिक नीतियां और कानून उज्ज्वल भारत के आधार की मजबूती

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया

भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय-सोशल जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सात दशकों से भी लंबी यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडीविजुअल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने देश के सोश्यो पॉलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी है।

आर्थिक नीतियां, कल के उज्ज्वल भारत का आधार बनेंगी- प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े-बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां, कल के उज्ज्वल भारत का आधार बनेंगी। भारत में बनाए जा रहे कानून, कल के उज्ज्वल भारत को और मजबूत करेंगे।

बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने ना दें। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लीविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रेवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है।

कोर्ट की एक्सेसबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो

देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अदालतों में फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। 2014 के बाद से 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 800 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद खड़ा हो गया था। अब नई दिल्ली से माले जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। तीन हफ्तों के बाद पर्यटकों के मामले में चीन भारत से आगे निकल गया है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

सबसे अधिक पर्यटक भारत से

पहले भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव जाते थे। लेकिन अब यह पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में हर वर्ष दो लाख से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की, जो कोरोना महामारी के बाद किसी भी देश से अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक, मालदीव में इस साल 28 जनवरी तक 1.74 लाख पर्यटक आए, जिनमें से केवल 13,989 भारतीय थे। रूस से सबसे ज्यादा 18,561 पर्यटक मालदीव पहुंचे। इसके बाद इटली से 18,111, चीन से 16,529 और ब्रिटेन से 14,588 पर्यटकों ने देश का दौरा किया। जर्मनी छठवें स्थान पर है जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान है।

17 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे थे

पिछले साल 17 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया, जिनमें से सबसे ज्यादा (2,09,198) भारतीय थे। इसके बाद रूसी (2,09,146) और चीनी (1,87,118) थे। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2022 में 2.4 लाख से ज्यादा थी। इसी तरह 2021 में 2.11 लाख से ज्यादा थी। कोरोना महामारी के दौरान मालदीव अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खुला था। उस अवधि के दौरान करीब 63,000 भारतीयों ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया था। 2018 में द्वीप राष्ट्र आने-जाने वाले पर्यटकों का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत भारत था। तब भारत से 90,474 पर्यटक पहुंचे थे।

लोकसभा में वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र और 'सबका प्रयास' के संपूर्ण दृष्टिकोण के साथ संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं -

सामाजिक न्याय

- चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस।

'गरीब कल्याण, देश का कल्याण'

- पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की।
- पीएम-जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।
- पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ।
- पीएम-जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर।
- पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद।

'अन्नदाता' का कल्याण

- पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- पीएम-फसल बीमा योजना में चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया।
- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध।

नारी शक्ति पर जोर

- 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए।
- उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा।
- स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
- पीएम-आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

- पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा।
- अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।
- छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और निशुल्क बिजली।
- छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रत्येक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान।

आयुष्मान भारत

- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है।
- 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा में मदद मिली है।
- आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार।
- 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

बुनियादी ढांचा

- बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगी।

रेलवे

- लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
- ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा।
- पत्तन संपर्कता गलियारा।
- अधिक यातायात वाले गलियारा।
- 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

विमानन क्षेत्र

- देश में हवाई अड्डों की संख्या हुई दोगुनी।
- 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं।
- देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए।

हरित ऊर्जा

- वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- परिवहन के लिए कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र

- राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पर्यटन केन्द्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।

निवेश

- वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 में एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले दोगुना है।
- 'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार।
- राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव।

बजट अनुमान 2024-25

- उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी।
- वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।

प्रत्यक्ष कर

- वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया।
- पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी।
- सरकार करदाता सेवाओं में लाएगी सुधार।
- वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इससे एक करोड़ करदाताओं को होगा लाभ।
- सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया गया।

अप्रत्यक्ष कर

- जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया।
- इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ। जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ।

“परिश्रम ही सफलता की कुंजी है”

न नकल करो, न करने दो

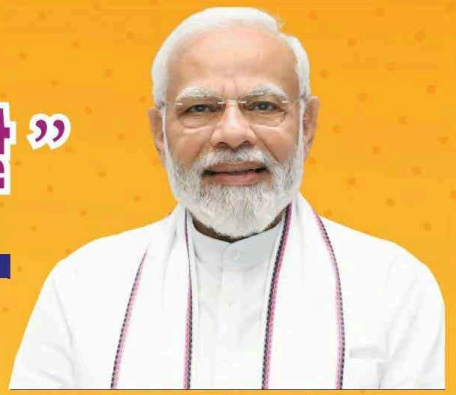

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

- परीक्षा केंद्रों पर कलेक्टर के प्रतिनिधि रहेंगे तैनात
- विद्यार्थियों को तनाव से दूर रखने के लिए ली जा रही मनोवैज्ञानिक मदद
- सायबर सेल करेगा परीक्षाओं की निगरानी
- एडमिशन कार्ड पर होगा क्यूआर कोड
- परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षक और अधिकारी नहीं कर सकेंगे मोबाइल का प्रयोग
- गोपनीयता भंग करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल की सजा
- नकल रोकने के लिए स्पेशल कमेटी का गठन

“

मेरे प्यारे बच्चो,

आप सभी की परीक्षाएं नज़दीक आ गयी हैं। ऐसे में आपको मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि सिर्फ आपका परिश्रम और मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी।

- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

”

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2024

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक - संदीप यादव, मुद्रक - संदीप यादव द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-ब, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अशोका हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- रंजना चितले

D-11190/R-49434/2024